He Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]

मई विल्ली, शनिवार, मई 8, 1971 (वैशाख 18, 1893)

No. 191

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1971 (VAISAKHA 18, 1893)

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग ПП-खण्ड 4

(PART III--SECTION 4)

विधिक निकार्यो द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विकापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं (Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया केन्द्रीय कार्यालय बैंक परिचालन और विकास विकास

बम्बई-1, दिनांक 16 अप्रैल 1971

सं० डी०बी०ओ०डी० सं० 95/इन्क्ल/सी० 102-71—रिजर्ष बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में रिजर्य बैंक आफ़ इंडिया इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल किया जाए :——

दि लॉर्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड, कोर्डुगल्लूर

आरं० के० हजारी, उप गवर्नर

कृषि ऋण विभाग

बम्बई-18, विनांक 28 अप्रैल 1971

कृ०ऋ० वि० सं० 24/ए० 18-70/71--शैंक विनियम अधि-नियम, 1949 की धारा 36-ए की उपधारा (2) के साथ पढ़े जाने वाले धारा 56 के खंड (2a) के अनुसरण में रिजर्ब वैंक आफ इंडिया इसके जरिये यह अधिसूचित करता है कि निम्निखित बैंक उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राथमिक सहकारी बैंक नहीं रह गए हैं:

कर्नि प्राथमिक सहकारी बैंक का नाम राज्य/संघणासित क्षेत्र (1) (2) (3)

 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लेबरर्स को आपरेटिय श्चिपट एण्ड केडिट सोसाइटी लिमिटेड, गांधी ग्राम विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)
 M59GI/71

आरध्य प्रदेश 🕝

(1)

(2)

(3)

 इंडियन लीफ टोबाको डैंवल १ मेन्ट कम्पनी स्टाक को-आपरेटिय बैंक लिमिटेड, "यूनिट हाउस" चिराला जिला गुन्टूर (आन्घ्र प्रदेश) . . .

वही-

3. 'ई' वार्ड ईस्ट एण्ड ''ई'' वार्ड सेन्ट्रल कन्सूरबन्सी लेबर एम्प्लाईज को-आपरेटिव केडिट सोसाइटी लिमिटेड कन्सूरबन्सी वार्ड आफिस जंक्शन आफ रिपन रोड एण्ड साउटर स्ट्रीट, बम्बई-II

महाराष्ट्र

 टैशनल इन्स्ट्रमेन्ट फैक्टरी एम्प्लाईज को-आपरेटिच सोसाइटी लिमिटेड राजा सुबोध मिललक रोड, जादवपुर कलकत्ता-32

पश्चिम बंगाल

5. सर्वे आफ इंडिया को-आपरेटिव केंडिट सोसाइटी विमिटेड 13, वुड स्ट्रोट, कलकत्ता-16

-वही-

एम० वि० हाटे ज्वाइंट चीफ आफिसर

(1171)

स्टेट बैंक आफ परियाला

सुधना

पटियाला, दिनांक 1 अप्रैल 1971

सं० एस० बी० ओ० पी० 15--इस सूचना के द्वारा बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानाम्तरण एवं परिवर्तन की सूचना दी जाती है:---

1. श्री एस० एस० सेठी, जूनियर आफ़िसर ने श्री एस० पी० अग्रवाल, आफ़िसर ग्रेंड "सी०" के स्थान पर 12-2-71 को बैंक का कार्य समाप्त होने के समय से 18-2-71 को बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय तक तथा 22-3-71 को बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय ते 26-3-71 को बैंक का कार्य आरम्भ होने के समय तक माडल बस्ती, नई दिल्ली शाखा में स्थानापन्न मैंनेजर के रूप में कार्य किया।

एस० डी० गंडा, जनरल मैनेजर

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान,

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 अप्रैल 1971

सं० 5 सी० ए० (1)/25/71-72—इस संस्थान की अधि-मूचना सं० 4 सी० ए० (1)/15/70-71 दिनांक 30-11-70 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्स विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री हर्षदराय शान्तिलाल शाह, ए० सी० ए०, 42, त्विपाठी भवन नं० 2, आरे मार्ग, गोरेगांव (प०) बम्बई 62 का नाम दिनांक 29-3-71 से पुनः स्थापित कर दिया है। (सदस्य संख्या 8625)।

सं० 5 सी० ए० (1)/3/71-72-इस संस्थान की अधि-स्थान सं० 4 सी० ए० (1)/9/68-69 दिनांक 31/7/68 एवं मं० 4 सी० ए० (1)/12/68-69 दिनांक 30/8/68 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनु-सारण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सवस्यता रजिस्टर में निम्निखित सदस्यों का नाम दिनांक 1-4-71 से पुन: स्थापित कर दिया है:---

ऋ०सं० स	्सं० नाम एवं प ता
1. 2453	श्री गुजारी वैकटकुष्ण राव, ए० सी० ए∙, 9/2 नव रस्न बाग, इस्दौर-1 ।
2. 6599	श्री गुल्लापाली वैंकट कृष्णराव ए० सी० ए० 42/3-आर० टी० संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद-38।

दिनांक 13 अप्रैल 1971

सं० 4 सी० ए० (1)/1/71-72—चार्टर प्राप्त विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुभरण में एतत् हारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ख) द्वारा प्रवक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सबस्यता रिजस्टर में से निम्न लिखित सदस्यों का नाम सबस्यों की अपनी प्रार्थना पर प्रत्येक के आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है:—

ऋ० सं०	स०सं० नाम एवं पता	तिथि
1. 57	9 श्रीकाशी शंकर मित्र,	31-3-71
	एक० सी० ए०,	
	48-ए०, राजा नव किसन स्ट्रीट,	
	कलकत्ता-5।	
2. 135	66 श्री जाल जमशेद चौथिया,	31-3-71
	ए० सी० ए०,	
	आदम मेनसन, कावस जी पटेल	
	स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1।	
3. 142		31-3-71
	एफ० सी० ए०	
	2 6 9/1, जोधपुर पार्क,	
	कलकत्ता-31।	
4. 157	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	31-3-71
	ए० सी० ए०,	
	ग्रेस कौटेज, सिविल लाइन्स,	
	अजमेर।	
5. 166		31-3-71
	ए० सी० ए०,	
	4/1, नफर कुन्डु रोड,	
	कलकत्ता-26 ।	

सं० 4 सी० ए० (1)/2/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 को धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी हई तिथियों से हटा दिया है:—

क०सं० ससं०	नाम एवं पता	तिथि
1. 1294	श्री रमेश भन्द्र कपूर चन्द्र कोठारी,	11-1-71
	ए० सी० ए०, 2/81, शाहकार निवास, 20, तारदेव रोड,	
2. 2592	बम्बई-34 । श्री आर० वैंकटरमन,	22-3-71
	एफ० सी० ए०, सर्वश्री राम एण्ड कम्पनी,	
	27-ए, नायकर न्यू स्ट्रीट, मथुरा-1।	

चुं० 8 सी० ए० (1)/1/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्निलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पन्न उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से रह कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पन्नों को रखने के इच्छूक नहीं:—

ऋ०सं० स०सं	० नाम एवं पता	तिथि
1. 6368	श्री शिवराज गरण अग्नवाल, एफ० सी० ए०, जी०-44, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-16	27-3-71 से 30-6-71
2. 9208	श्री एल० कक्षीरेणन, ए० सी० ए०, अन्नामलाई, इलाम, पंकज कालोनी, रामनाड रोड, मदुरा-9।	1-4-71 से 30-6-71
3. 9243	श्री श्रीदेव दत्ता, ए० सी० ए०, 458, ब्लाक-के, न्यू अलीपुर, कलकत्ता-53 ।	1-4-71 से 3 0-6- 71
4. 11370	श्री टी० ग्रैलवाराज, ए० सी० ए०, 2, ओल्ड बंगला स्ट्रीट, चिन्ताद्री पेट, मद्रास-2।	2 8- 1-7 1 से 3 0- 6-7 1
5. 11524	श्री अशोकभुमार हीरालाल शाह, ए० सी० ए० 116/3, एस० गांधी मार्ग, केशब बाग, बम्बई-31	25-3-71 से 30-6-71

दिनांक 14 अप्रैल 1971

सं० 4 सी० ए० (1)/3/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के बिनियम 16 के अनुसरण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20, उपधारा 1 (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त_ लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सस्दयता रजिस्टर में से निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है:—

ऋ०सं० स०सं०	नाम एवं पता	तिथि
	श्री एव० राजामणी, ए० सी० ए०, सी०-44, तीरू नगर, मबुरा-6।	1 4- 4-71

क०सं० स०सं०	नाम व पता	तिथि
2. 9732	श्री जी० सेतुरामन, ए० सीं० ए०, 8/216, गुलिस्तां, साइन (पूर्व), बम्बई-22।	14-4-71
3. 10661	श्री सुजान कुमार सेन, ए० सी० ए०, 46, एन० सी० चौधरी मार्ग, कलकत्ता-42।	14-4-71
4. 10696	श्री एस० आर० एम० एम० नैनार, ए० सी० ए०, द्वारा डी० पी० पी०, 6 बी०, नेलसन मार्ग, मद्वास-29।	14-4-71
5. 4633	श्री शैलेश चिमन लाल गाह, ए० सी० ए०, सर्वश्री शैलेश शाह एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, ए०-29, मसकती मार्किट, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-1।	1-7-71
	ं सी० बालकृष्ण	नन्, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1971

सं० इन्स०/22(1)-1/71 (2)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की घारा 46 (2), कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने, जैसा कि उक्त विनियम 95-क और कैरल कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1959 में निर्विष्ट है, बीमाफ़ृत व्यक्तियों के परिवारों के लिए चिकित्सा हितलाभ को कैरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए 23, मई 1971 को तारीख नियत की है अर्थात् :—

'क्विलोन जिले के पठानापुरम तालुक में एडामुलक्कल पंचायत का भीतरी क्षेत्र''

दिनांक 19 अप्रैल 1971

सं० इन्स० 22 (1)-2/71 (3)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उपविनियम (1) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्विष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'ए०' 'बी' तथा 'सी॰' के लिए प्रथम अंशवान एवं प्रथम लाभ अविधयों बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए नियत दिवस 24 अप्रैल, 1971

की मध्य राक्षि को प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसाकि निम्न सूची में दिया गया है:

प्रथम अंगवान अव	រមែ	प्रथम लाभ अवधि					
वर्ग जिस मध्य	जिस मध्य	जिस मध्य	जि स मध्य				
राक्ति को	रात्नि को	राजि को	रात्नि को				
प्रारम्भ होती	समाप्त होती	प्रारम्भ होती	समाप्त होती				
है	है	है	हैं				
ए० 24-4-71	31-7-71	2 2-1-7 2	29-4-72				
बी० 24-4-71	25-9-71	2 2-1-7 2	24-6-72				
सीं० 24-4-71	29-5-71	2 2-1-7 2	26-2-72				

अनुसूची

भध्य प्रदेश राज्य मे शहदील जिले की साहगपुर तहसील में झगराहा बकाहो बकाही, बर्गवान अमलाई ग्राम है।

दिनांक 26 अप्रैल 1971

सं० इन्स I 2 (1) [1/71—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के सशोधन का आलेख जोकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करने का प्रस्ताव रखती है, उक्त विनियम के उपविनयम (1) के अनुसार उनके द्वारा प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाणित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन पर दिनांक 26 मई 1971 या उसके पश्चात विचार किया जायेगा।

उक्त प्रस्तावित संगोधन के विषय में किसी भी ध्यक्ति से निदिब्ट तारीख से पूर्व प्राप्त विरोध या सुझाव पर उक्त निगम विचार करेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 में प्रस्तावित संशोधन

विनिधम 10 (9)

वर्तमान विनियम के प्रथम वाषय में 'वर्ष में दो बार' णब्द "त्रैमासिक में एक बार" ब्रारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। विनियम 10 (14)

विनियम 10 (14) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"एक क्षेत्रीय मंडल जिस क्षेत्र के लिये उसे स्थापित किया गया है उसके लिए निम्निलिखित कार्य करेगा:

- (क) इस प्रकार के प्रशासनिक ओर/या अधिशासी कार्य जोकि समय समय पर निगम या स्थायी समिति के प्रस्ताव द्वारा इसे न्यस्त या सोंपे गये हों।
- (ख) योजना के परिज्ञालनार्थ अधिनियम, नियम और विनियम और भार्मा अ।र कार्य करने को नीति में परिवर्तन के लिये समय-समय पर सुझाब देना ।

- (ग) निगम के सामान्य निर्णयों और अग्रता के कार्यक्रमों के विशास ढांचे के अन्तर्गत निम्निखित विषयों पर निर्णय लेना परन्तु साथ ही जहां निगम या उपयुक्त सरकार को अनुमति की आवश्यकता हो वह ले ली जाये:
- (i) निगम द्वारा निर्धारित अग्रता के ऋम में अन्य वर्गों और संस्थापनों पर योजना का विस्तार करना;
- (ii) नये क्षेत्रों में योजना का विस्तार करना और परिवारों के लिये विकित्सा देख-रेख का विस्तार करना,
- (iii) क्षेत्रों में असाधारण स्थिति को संभालने के लिये विशेष उपाय करना;
- (iv) हितलाभों में सुधार करना;
- (v) अंतरंग चिकित्सा उपचार प्रदान करना;
- (vi) क्षेत्र में उन बीमाकृत व्यक्तियों के पुनर्वास का उपाय व प्रबन्ध करना जोकि पूर्ण रूप से अपंग हो गये हो;
- (vii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के विविध उपबन्धों, विनियमों और अन्य नियमों और निर्देशों का नियोजकों से पालन करवाना ।
- (घ) राज्य में चिकित्सा एवं नकद हितलाभ वोनों ही पक्षा में योजना के परिश्वालन का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और निगम तथा राज्य सरकार को योजना के परिचालन में नकद हितलाभ अदायगी और चिकित्सा हिसलाभ दोनों ही पक्षों में सुधार करने के उपायों की परामर्श देना, विशेषत: स्वास्थ्य-प्रबन्धक उपाय, सुरक्षा और वैयक्तिक स्वास्थ्य विद्या की वृद्धि करना और प्रमाण में ढील का पुनरीक्षण करना व रोकना और योजना के अन्य अपवादों को दूर करना, आदि;
- (ङ) बीमाकृत च्यक्तियों, नियोजको आदि की साधारण व्यथा, शिकायतो और कठिनाइयों को यथा उचित देखना;
- (च) निगम को उन विषयों में परामर्श देना जोकि स्थायी सिमिति या महानिदेशक द्वारा उसे भेजे गये हों।

क्षेत्रीय मंडल अपना कोई भी कार्य चलाने के लिये उपयुक्त उप-समितियां स्थापित कर सकता है और जहां आवश्यक हो स्थानीय समितियों की सहायता एवं परामर्श ले सकता है।

> वी० आर० नटेशन, बीमा आयुक्त

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक बोई की रिपोर्ट

वर्ष 1 जुलाई 1969--- 30 जून 1970

आर्थिक परिवेश

1969-70 के दौरान वास्तिविक राष्ट्रीय आय में अनुमानतः 5 से 5½ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जबिक 1968-69 (अप्रैल-मार्च) में यह वृद्धि केवल 1.8 प्रतिशत हुई थी परंतु मुद्रागत साधनों (जनता के पास चलमुद्रा और सकल बैंक जमा) में 11 प्रतिशत से भी अधिक की जो वृद्धि हुई है वह वास्तिविक उत्पादन में हुई वृद्धि से कहीं ज्यादा है। नवम्बर के उत्तरार्ध से थोक मूल्यों पर दबाव पड़ने लगा किंतु रामग्र रूप से पूरे वर्ष मूल्यों के सामान्य स्तर तथा आद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में हुई कुल वृद्धि िछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। खाद्ययाझ का उत्पादन 100 मेंट्रिक टन के आसपास पहुंच गया और यह अनुमान है कि वह अब तक का एक नया कीर्तिभान है। प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी 1968-69 की अपेक्षा अधिक हुआ हालांकि उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए वह नाकाफी है। ओद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दरकुछ धीमी पड़ गई। 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में तिर्यात में जो वृद्धि (4.0 प्रतिशत) हुई वह 1968-69 में हुई वृद्धि (13.5 प्रतिशत) के मुकाबले बहुत कम थी किंतु परम्परेतर निर्यातों की प्रगति उत्साहवर्द्धक बनी रही। इसके साथ ही खाद्याझों तथा उर्वरकों के आयात में प्रमुख रूप से भारी कमी होने के फलस्वरूप विदेशी अदायगी की स्थिति और पुख्ता हो गई।

- 2. 1968 के प्रारंभ में आँखोगिक उत्पादन में मंदी के बाद जो सुधार शुरू हुआ वह 1969-70 के पहले नौ महीनों (जुलाई-मार्च) तक वरावर चलता रहा, यद्यपि उसकी दर (5.8 प्रतिणत) 1968-69 की तदनुरूपी अवधि की सम्बन्धित दर (7.4 प्रतिणत) की आंक्षा कुछ कम थी। कपास, तिलहन, इस्पात तथा अलाह धातुओं जैसे औद्योगिक कच्चे माल की कमी तथा कित्यय उद्योगों में श्रमिक गड़बड़ियों के कारण इस सुधार की प्रगति में वाधा पड़ी। आँद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक सामग्री के आयात में तेजी लाई गई। उद्योगों के अनुसार जहां भारी अकार्बनिक रसायनों, सोमेंट, तांबे को गलाने, एल्युमिनियम, धातु की वस्तुओं, थिजली की मोटरों और भिट्ठयों, बिजली के तारों, बिजली की मणीनों, उपकरण तथा साधिजों, परिवहन उपस्कर और कागज तथा कागज से बनी वस्तुओं के उद्योगों के उत्पाद की प्रगति में विशेष सुधार हुआ, वहां लोहा और इस्पात, उर्थरकों, मगीनों के पुजों और उप-साधनों, रबड़ के टायरों और ट्यूबों, पेट्रोल के परिसोधन से प्राप्त वस्तुओं मोटर साइकलों तथा साइकलों और वनस्पति जैसे उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि-दर में अपेक्षाकृत कमी हुई है।
- 3. हाल की मंदी के बाद अँद्योगिक उत्पादन में सुधार होने तथा चौथी योजना (1969-74) के शुरू किए जाने के कारण यह आणा बंधी थी कि गैर-सरकारी कंपनियों के क्षेत्र में निवेश की गतिविधियों में शीझता से चेतना आएगी। यह आणा केवल आंशिक रूप से ही पूरी हुई। उद्यमकर्ता अधिक निवेश लागतवाली बड़ी अथवा मझौली परियोजनाओं का सूत्रपात करने से थोड़ा हिचकिचात रहे क्योंकि उद्योग लाइसेंस नीति की जांच समिति द्वारा की गई सिफ़ारिणों के आधार पर सरकार की उद्योग लाइसेंस नीति में संशोधनों का किया जाना सरकार के विचाराधीन था। देश के कुछ भागों में राजनैतिक अस्थिरता तथा औद्योगिक लंबंधों की असतोषजनक स्थिति भी इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इतना होने पर भी वर्ष की अंतिम तिमाही में नये पूंजी इजरों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई जिससे यह पता लगता है कि निवेशों के संबंध में इससे पहले किये गये निर्णयों को अमल में लाया गया है। बाजार में बहुत से ईक्विटी शेयर जारी किये गये और उन सबमें जरूरत से ज्यादा अभिदान हुआ। लघू औद्योगिक क्षेत्र के लिए राज्य वित्त निगमों (रा० वि० निगमों) द्वारा मंजूर किये गये ऋणों तथा बैंको द्वारा दिये गये ऋणों की प्रवृत्तियां इस बात का संकेत करती हुई प्रतीत होती हैं कि इस क्षेत्र की निवेश गतिविधियां 1968-69 की अपेक्षा काफी अधिक हैं।
- 4. इस वर्ष सरकार की नीति में आँचोगिक विकास को प्रोत्साहित करने पर वल दिया गया और इसके साथ ही आर्थिक शिवत के केन्द्रीयकरण की रोकथाम करने, छोटे उचोगों तथा नए उचमकत्ताओं को प्रोत्साहन देने और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के व्यापक उदेश्यों का पालन किया गया । सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों, इलाकों और वर्गों के बीच बैंक ऋणों के वितरण की विश्वमताओं को दूर करने के उद्देश्य से जुलाई 1969 में 14 यहें भारतीय वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया । 1970-71 के बजट में कंपनी क्षेत्र के कर-हांचे को बहुत कुछ उपों का त्यों रहें। दिया गया है ताकि निवेण एंबंधी निर्णय करने के लिए स्थिर वातावरण बना रहे। इसके साथ ही, अचत तथा निवेण को बहुतवा देने के लिए अन्य स्रोतों के साथ-साथ यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों तथा

भारतीय कंपितयों के शेयरों में किये गये निवेशों से प्रोद्भूत आय के लिए आय-कर से छूट विए जाने की सीमा को बढ़ाकर 3040 रुपये कर दिया गया। आयात-प्रतिस्थापन में और अधिक तेजी लामें के लिए मशीनरी की कतिपय मदों के आयात-शुल्क को यथा-मूल्य 27½ प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। प्रबंध एजेंसी प्रणाली को अप्रैल 1970 में समाप्त कर दिया गया। सरकार ने एकाधिकार पर नियंत्रण रखने तथा आर्थिक शक्ति के अत्यधिक केन्द्रीयकरण की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एकाधिकार एवं प्रतिबंधी व्यापार पद्यतियां अधिनयम भी बनाया।

5. उद्योग लाइसेंस जांच समिति की सिफ़ारियों को घ्यान में रखते हुए उद्योग लाइसेंस नीति का नवीकरण भी किया गया। नई नीति में मोटे तौर पर एक "मूलभूत" क्षेत्र (जिसमें बुनियादी, क्रांतिक तथा सामरिक महत्व के उद्योग होंगे) तथा एक ऐसे 'मध्यवर्सी' क्षेत्र की परिकल्पना की गई है जिसमें 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के निवेश किये जाने हों; इसके अतिरिक्त, 5 करोड़ रुपये से अधिक के सभी नए निवेश प्रस्ताव 'भारी निवेशवाल' क्षेत्र में माने जाते हैं। जहां एक ओर वृहत्तर उद्योगों समृहों (जिनकी अस्तियां 35 करोड़ रुपयों से अधिक हैं) और विदेशी संस्थाओं तथा उनकी सहायक संस्थाओं अथवा शाखाओं को आंतरिक तथा भारी निवेशवाले क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में भाग लेने तथा उसमें अपना योगदान देने की अनुमित दी जाएगी वहां दूसरी ओर मध्यवर्ती क्षेत्र में बृहत्तर उद्योग समृहों को छोड़कर बाकी उद्योकत्तिओं का विशेष घ्यान रखा जाएगा। ** समिति ने जिस 'संयुक्त क्षेत्र' की अवधारणा की सिफ़ारिश की थी, सरकार ने उसे मान लिया है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यम समृहों द्वारा 'मूलभूत' तथा भारी निवेशवाले क्षेत्रों में चलाई जानेवाली बड़ी परियोजनाएं इस श्रेणी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा जो बड़ी परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की भारी सहायत से स्थापित की गई हों उनके मामले में इन संस्थाओं को वित्तपोषण की व्यवस्था के अंतर्गत यह विकल्प होगा कि वे भविष्य में जारी देशवे जाने वाले ऋणों और डिबेंचरों को निर्दिष्य गर्तो पर पूर्णतः अथवा अंगतः इक्विटी में परिवर्तित कर सकेंगे तथा जिन कंपनियों को सहायता दी गयी है उनके बोर्डों में उन्हें अपने निदेशक नामजद करने का अधिकार भी होगा। लाइसेंस देने की छूट-सीमा को कतिपय शतों के अधीन वढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है किंतु कतिपय उत्पादों का केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन किए जाने को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की वर्तमान नीति जारी रखी जाएगी।

आवधिक विस्तृपोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा उद्योगों का विस्तृपोषण

6. 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में भारतीय आँद्योगिक विकास बैंक (भा० औ० वि० बैंक), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (भा० औ० वि० निगम), भारतीय आँद्योगिक ऋण और निवेश निगम (भा० औ० ऋ० नि० निगम), राज्य वित्त निगमों (रा० कि० निगमों) और राज्य औद्योगिक विकास निगमों (रा० औ० वि० निगमों) द्वारा मंजूर की गई सहायता की कुल राशि 149,) करोड़ रुपये थी जो 1968-69 के 132.3 करोड़ रुपयों में हुई 13 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है (सारणी 1) । इस वृद्धि का मुख्य कारण रा० वि० निगमों तथा रा० औ० वि० निगमों द्वारा विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता में हुई वृद्धि है। आंध्र प्रवेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रवेश में राज्य वित्त निगमों का तथा गुजरात औद्योगिक नियेश निगम का कार्य विशेष रूप से सराहनीय रहा। जहां तक सहायता के स्वरूप का प्रश्न है पिछले वर्षों की भांति, ऋणों के रूप में दी गई सहायता का प्राधान्य बना रहा। आवधिक वित्तपोषण करनेवाली संस्थाओं के हामीदारी संबंधी कारोबार में 1968-69 के स्तर की अभेक्षा मामूली वृद्धि हुई और यह वृद्धि नए पूंजी इजरों में हुई वृद्धि के अनुरूप थी।

7. सहायता के वितरणों की कुल राशि में 1968-69 के स्तर से 33 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि हुई और यह 85.8 करोड़ रूपयों से बढ़कर 114.0 करोड़ रुपये हो गई।

^{*}यह वृद्धि उस मशीनरी पर लागू नहीं होती जो परियोजना की स्थापना करने के लिए या वर्तमान परियोजनाओं के भारी विस्तार के लिए आवश्यक हो।

^{*}इस बीच सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि (I) 5 करोड़ रुपयों से अधिक आस्तियों वाली विदेशी कंपनियों और उद्योग इकाइयों को विशाखन के लिए सरकार की पूर्व-स्वीकृति लेना आवश्यक होगा और (II) 20 करोड़ रुपयों से अधिक की आस्तियों वाले बड़े औद्योगिक समृह तथा विदेशी कंपनियां मध्यवर्ती और लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यात-आधारित इकाइयां स्थापित कर सकती है वशर्तें कि वे अपने उत्पादन के कमशः 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत का निर्यात करने का वलन दें।

PART III--Sec. 4]

सारणी 1---1969-70और 1968-69 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक वित्तपोषण करनेवाली संस्थाओं द्वारा मंजूर की गयी सहायता

(करोड़ रुपयों में)

						हामीद	ारी और	प्रप्रत्यक्ष ३			
		रुपया ऋण		ण विदेशीचलमुद्राऋ			ण सामान्य और अधिमान शेयर			; ;	जोड़
		1969- 7 0	1968-	1969- 70	1968- 69	1969- 70	1968- 69	1969- 70	1968-	1969- 70	1968- 69
भा०औ०वि०बैक .		50.2** (8.2)	′ 46.1* (7.8)			6.3	1.1		1.5	56.4 (8.2)	48.6
भा० औ० वि० निगम		17.3	17.6	2.3	2.0	1.2	1 . 4	0.2	1.7	21.0	22.7
भा० औ० ऋठ और नि० निगम		4.2	2,2	13.3	27,3	2.7	2.6	2.2	4.9	22.4	37.0
रा० वि० निगम .		32.5	19.3			0.5	0.3	 ,	-	33.0	196
रा० औ० वि० निगम**		12.3	1.9			4.8	2.5		0.02	17.1	4.4
जोड़ .	•	116.5		15,6	29.3	15. 5	7.9	2.4		149.9 (8.2)	132.3
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया†	•					3.5	2.4	6.5	7.9	10.0	10.3
जीवन बीमा निगम@			3.3				3.8		10.6		17.7

^{*}इनमें प्रत्यक्ष ऋष्ण, बैंकों पुनर्विस सहायता और पुनर्भाजन के आंकड़े शामिल हैं और इनमें रा० वि० निगमों को दी गयी पुनर्वित सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाये गये आंकड़े शामिल नहीं है क्योंकि ये आंकड़े राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं अतः दुबारा शामिल नहीं किये गये।

^{**}ये आंकड़े 9 रा० औ० वि० निगमों तथा गुजरात औ० नि० निगम के हैं।

^{† 1969-70} के आंकड़े अनन्तिम हैं।

^{@ 1969-70} के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 2---1969-70 और 1968-69 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक जित्तपोषण करनेवाली संस्थाओं द्वारा वितरित सहायता (करोड रुपयों में)

facility control of the control of t			and the second		हामी	शरी और	प्रत्यक्ष अ	भिदान		
	स्पया ऋण		विदेशी चलमुद्रा ऋण		सामान्य और अधिमा शोयर		ामान डि	मान डिबेंचर 		
	1969- 70	1968- 69	1969- 70	1968- 69	1969- 70	1968-	1969- 70	1968-	1969- 70	1968 - 69
भा० औं ० वि० बैंक .		27.4* (6.0)			1.3	0.4	0.5	0.5	45.1 (5.7)	28.2
भा० औ० वि० निगम	, ,		@ 1.9	2.4	0.4	0.6	0.7	1.1	17.5	19.5
भा० औ० ऋ० और नि० निगग	4.3	2.7	11.8	8.7	1.4	1.5	2.3	3,4	19.8	16.2
रा० वि० निगम .	22.0@	17.9	@		0.3	0.5			22.3	18.4
रा० औ० वि० निगम ^क *	5,4	2.0	Page 1		3.9	1.5		0.02	9.3	3,5
जोड़	89.6 (5.7)	65.3 (6.0)	13.7	11.1	7.3	4.5	3,5	5.0	114.0 (5.7)	85.8 (6.0)
यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया† जीवन बीमा निगम@@		3.9			1.9	1,6 4,6	6,2	8.7 7.0	8, 1	10.3 15.5

*इनमें प्रत्यक्ष ऋण, बैंकों को पुर्निवत्त सहायता और पुनर्भाजन के आंकड़े शामिल हैं और इनमें रा० वि० निगमों को दी गयी पुनर्वित्त सहायता के कोष्ठकों में अलग से दर्शाये गये आँकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अंतर्गत आ चुके हैं अतः दुवारा शामिल नहीं किये गये।

@इनमें गारंटियों के कारण वितरित की गयी राशि शामिल है।

**ये आंकड़े 9 रा० औ० वि० निगमों तथा गुजरात औ० नि० निगम के हैं।

11969-70 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

@@1969-70 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 3--आवधिक वित्तपोषण करनेवासी संस्थाओं (भा० ओ० वि० बैंक, भा० औ० वि० निगम, भा० औ० ऋ० नि० निगम, रा० वि० निगमों, रा० औ० वि० निगमों) द्वारा 1965-66 से 1969-70 (अप्रैल-मार्च) के बौरान मंजूर एवं वितरित की गई सहायता।

						,				(कराड़	ध्पयाम)
		1965-66		1966-67		1967-68		1968-69		1969-70	
				्——् मंजूरियां	•	•			1		
रुपया ऋण* .	 ,	119.7	71.3	95.9	86.6	68.1	79.3	87.1	65.3	116,5	89.6
हामीदारी एवं प्रत्यक्ष अभिदान		25.3	11.6	14.0	17.4	11.9	11.5	16.0	9.5	17.9	10.8
विदेशी चलमुद्रा ऋण .		24.3	22.9	12.1	21.5	7.0	14.2	29.3	11.1	15.6	13.7
जोड़		169.3	105.8	122.0	125.6	87.1	105.0	132.3	85.8	149,9	114.0

*इनमें भा० ओ० वि० बैंक द्वारा कों बैंको दी गई पुनर्वित्त तथा पुनर्भाजन सहायता शामिल है । इनमें रा० वि० निगमों को दी गई पुनर्वित्त सहायता के आंकड़े दोबारा शामिल नहीं किये गए क्योंकि ये आंकड़े राज्य वित्त निगमों के ऋणों के अतर्गत आ चुके हैं । आंकड़ों में गारंटियों के बाबत किये गये वितरण भी शामिल हैं।

^{8.} सारणी 3 में आवधिक विक्तपोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा 1965-66 (तीसरी योजना का अन्तिम वर्ष) से लेकर 1969-70 तक मंजूर की गई और वितरित सहायता की प्रगति दिखाई गई है। 1966-67 से 1969-70 तक के वर्षों के लिए सहायता के नकदी वितरणों का औसत 107.6 करोड़ रुपये रहा है जो 1965-66 के तदनुरूपी औसत 105.8 करोड़ रुपये तथा तीसरी योजना के समग्र वार्षिक औसत 61 करोड़ रुपये की तुलना में काफी संतोषजनक है। फिर भी, मंजूरियों की राणि 1965-66 की संबद्ध राणि से काफी पीछे रह गई हालांकि पिछले दो वर्षों में उसमें 1967-68 की निम्नतम मंदी में पाये जानेवाले निम्न स्तर के मुकाबले वृद्धि ही हुई है।

^{9.} आवधिक वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं की निधियों के स्रोदों और उनके उपयोगों के संबंध में 1969-70 के आकड़े अनुबंध I में विये गए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नीतियां एवं कार्य

10. 1969-70 के दौरान भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई सहायता की कुल राशि 66.6 करोड़ रुपये थी अर्थात् उसका परिमाण 1968-69 में दी गई सहायता के बराबर था (सारणी 4) । पर जहां 1968-69 में यह सहायता केवल 469 आवेदनों पर दी गई थी वहां इस वर्ष इस सहायता को प्राप्त करनेवाले आवेदनों की संख्या इससे बहुत अधिक अर्थात् 1137* थी। वितरणों की कुल राशि भी 48.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 52.3 करोड़ रुपये हो गई। बड़े आकार की परयोजनाओं के लिए बैंक के प्रत्यक्ष ऋणों की मंजूरियों में और कमी हुई परन्तु यह कमी निर्मातों के लिए दिये गये बड़े प्रत्यक्ष ऋणों और बढ़ी हुई हामीदारी गतिविधियों तथा पुनर्भाजन कार्यों से पूरी हो गई। लघु उद्योगों के क्षेत्र में निवेश संबंधी कार्यकलापों में तेजी आने तथा इस क्षेत्र को रा० वि० निगमों द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता में विस्तार होने के फलस्वरूप उन्हें भा० औ० वि० बैंक से पूर्नावित्त का आश्रय लेने की ज्यादा जरूरत पड़ी।

11. वर्ष के दौरान बैंक ने उन विकास एवं संबर्धन कार्यों को अपने हाथ में लेने की दिशा में एक साधारण प्रयास किया है जो अधिनियम के अधीन उसके लिए निर्धारित किये गये हैं और जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा छोटे और नये उद्यमकर्ताओं के प्रोत्साहन पर बल देने की सरकारी नीति के अनुरूप हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में भा० ओ० दि० बैंक ने रिजर्व बैंक, भा० औ० वि० निगम तथा भा० औ० ऋ० नि० निगम के साथ मिलकर पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाने, उद्योग की मूल आवश्यकताओं से संबंधित सुविधाओं और कच्चे माल की पूर्ति तथा विपणन संभावनाओं का मूल्यांकन करने और जो उद्योग ऐसे क्षेत्रों में लाभदायक रूप से स्थापित किये जा सकते हैं उनके विकास का निर्धारण करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों की शुरूआत की है। असम राज्य और तिपुरा के संघशासित क्षेत्र में किये गये पहले दो सर्वेक्षण जून 1970 में पूरे हो चुके थे तथा सर्वेक्षण रिपोर्टी के आधार पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। जम्मू और कम्मीर तथा बिहार में सर्वेक्षण शुरू किये जा चुके हैं और उत्तर-प्रदेश तथा राजस्थान में शीझ ही सर्वेक्षण शुरू किये जाएंगे। दूसरे पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी ऐसे ही सर्वेक्षण किये जाएंगे।

प्रभावी मंज्रियां (गारंटियों को छोड़कर)।

PART III—SEC. 41

- 2

*आवेदनों की संख्या में हुई इस भारी वृद्धि का कारण यह था कि इस वर्ष पुनर्वित्त के लिए छोटे सड़क-परिवहन-चालकों के 652 आवेदन मंजूर किए गए जब कि पिछले वर्ष ऐसे आवेदनों की संख्या 17 थी।

सारणी 4-1969-70 और 1968-69 (जुलाई-जून) के वो वर्षों में भा० औ० वि० बेंक द्वारा मंजूर (प्रभावी) और वितरित की गयी सहायता

सहायता वि० बैंक के लेकर अ मंजूर की ग 1969-70 1968-69 1969-70 1968-69 राशि 1. निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्नुक्ष ऋण 7.6 16.0 10.9 15.3 107. 2. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण 11.2 6.5 2.9 — 17.	964 में भा० औ०
1969-70 1968-69 1969-70 1968-69 राशि 1. निर्यात के लिए दिये गये ऋणों को छोड़कर औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्तुक्ष ऋण 7.6 16.0 10.9 15.3 107. 2. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण	स्थापित होनेसे व तक की कुल
औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्तुक्ष ऋण 7.6 16.0 10.9 15.3 107. 2. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण 11.2 6.5 2.9 — 17.	ई वितरित राशि
औद्योगिक संस्थाओं को दिये गये प्रत्तुक्ष ऋण 7.6 16.0 10.9 15.3 107. 2. निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण 11.2 6.5 2.9 — 17.	
·	4 84.8
	8 2.9
3. औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों, डिबेंचरों आदि	
की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान . 6.2 2.4 2.2 1.6 22.	9 15.9
4. औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्विक्त , 15.7 14.1 12.5 11.6 100.	1 96.9
5. निर्यात उधारों के लिए पुनर्विस . 1.3 7.3 2.7 2.5 10.	3 6.7
6. बिलों का पुनर्भाजन 24.1 15.5 . 20.6 13.3 61.	4 52.7
1 से 6 तक का जोड़ 	
66.1 61.8 51.8 44.3 319.	9 259.9
7. वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में	
अभिदान* 0.5 4.5 0.5 4.5 20.	1 20,1
1 से 7 तक का जोड़ 66.6 66.3 52.3 48.7 340.	0 280.0
8. ऋणों और आस्थगित अदायगियों के लिए गारंटी 2.5 0.01 0.1** 0.01** 26.7	19.1**
9. अग्रिम अदायगी गारंटी (निर्यात) . — 0.6 0.3** — 0.	6 0,3**

ैंबन आंकड़ों में अगस्त 1964 तक उद्योग पुर्निक्त निगम द्वारा स्वीकृत पुनर्वित्त सहायता के आधार पर भा० औ० वि० बैक द्वारा वितरित राशि शामिल हैं।

M59GI/71-2

^{*}इन आंकड़ों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के खरीदे गये हिस्सों की राणि शामिल नहीं है।

^{**}से आंकड़े निष्पादित की गई गारंटियों के हैं।

12. इस वर्ष कलकत्ता, मदारा और नई दिल्ली में कार्यालय खोले गये। वे कार्यालय आयायक स्थानीय संपर्क थापित करने में सहायक होंगे। उन्हें निश्नित सीमाओं तक प्रत्यक्ष, पुनिवत्त और पुनर्भाजन सहायता के आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रान्ति दी गई है। बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए तथा सहायता मंजूर करने का निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का निश्चय भी किया है; कलकत्ता कार्यालय के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया जा खुका है। भा० औ० वि० वैंक ने छोटे उद्यमकर्ताओं के लाभ के लिए इन कार्यालयों में कुछ तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की है जो टैंक्नॉलाजी, प्रबंध और विपणन व्यवस्था जैसे विषयों पर परापर्श सेवाए प्रदान करेंगे। बैंक ने अन्य राज्यों की राजधानियों में भी छोटे शाखा कार्यालय खोलने का निश्चय किया है जो उद्यमकर्ताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों आदि के लाभ के लिए सूचना केन्द्रों तथा आरंभिक संपर्क स्थलों के रूप में कार्य करेंगे।

13. भा० औ० वि० वैंक ने कम विकसित क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्भापना के लिए रियायती शर्तों पर सहायता देने की योजना के अपने निर्णय की घोषणा भी की है। इस प्रयोजन के लिए विभन्न राज्यों में योजना आयोग द्वारा निर्धारित पिछडे जिलों/क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को दोनों प्रकार की योजनाओं अर्थात प्रत्यक्ष सहायता योजना तथा पूर्नाकत योजना के अंतर्गत भार और विरु बैंक की सहायता महैया की जाएगी। पिछड़े क्षेत्रों/जिलों की जिन परियोजनाओं को सरकार से अनुदान/उपदान प्राप्त होगा, वे भा० औ० वि० बैंक से भी रियायतें पाने के योग्य होंगी। पिछड़े जिलों/श्रेतों की औश्रोगिक इकाइयों को ब्याज की रियायती दर पर प्रत्यक्ष ऋण दिये जाएंगे। यह दर बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी और वह वर्तमान सामान्य दर जो कि 8 प्रतिशत है, कि बजाय न्युनतम 7 प्रतिशत होगी। जिन अन्य रियायतों को देने की पेशकश की गई है उनमें ये शामिल हैं: ऋण की वापसी अदायगी के लिए प्रारंभिक छट की सामान्य अवधि का 3 वर्ष से वहाकर 5 वर्ष किया जाना, वापसी अदायगी के लिए 15-20 वर्ष की अधिक लम्बी अवधि को निर्धारण और ऋण के अनाहरित बकायों पर वायदा प्रभार का घटाया जाना । शेयरों तथा डिबेंचरों की हामीदारी देते समय वैंक कम दर पर अपना हामीदारी कमीशन लेगा और इसके अलावा वह पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाओं की श्रोयर पंजी में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अभिदान करेगा। परियोजना की लागत तथा ऋणों के मार्जिनों के संदर्भ में प्रवर्तकों के अंगदान से संबंधित सामान्य निबंधनों में भी ढील दी जाएगी । भा० औ० वि० बैंक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में परांमर्श सेवाओं के आरंभिक व्यय का वहन करने के लिए भी राजी हो सकता है *बशर्ते* की परियोजना ज्यों ही मुनाफे के चरण में पहुंचे त्यों ही इस व्यय की प्रतिपृति कर दी जाए। इस योजना के अधीन आम तौर पर उन्हीं परियोजनाओं के लिए रियायसें उपलब्ध होंगी जिनकी समग्र परियोजना लागत एक करोड़ रुपयों से अनिधक हो; इनसे बड़ी परियोजनाओं के लिए चयनात्मक आधार पर रियायती पुनिवत्त प्रदान किया जाएगा।

14. पुर्नावत्त के क्षेत्र में भा० औ० वि० वैंक ने रा० वि० निगमों तथा बैंकों को रियायतें और प्रोत्साहन दिये हैं तािक पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को अपेक्षाकृत आसान कर्तों पर सहायता प्रदान कर सकें। इस प्रकार निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित और गारंटी योजना के अन्तर्गत आनेवाली और इनके साथ ही इस योजना के अन्तर्गत न आनेवाली 20 लाख रुपयों तक की छोटी और मझौली इकाइयों को दिये गये सभी योग्य ऋणों पर वार्षिक 3½ प्रतिशत की रियायती दर से शतप्रतिशत पुनिवत्त प्रदान किया जायगा, वशर्तों कि वित्तपंषण करनेवाली संस्था द्वारा उधारकर्ता से 6 प्रतिशत से अधिक दर 'पर भ्याज न लिया जाए। इसके अतिरिक्त पुनिवत्त की शर्तों का निर्णय करने समय भा० औ० वि० बेंक वायदा प्रभार से छूट देने, वापसी अदायगी के लिए ज्यादा लम्बी अवधि प्रदान करने और 2 या 3 वर्ष से अधिक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि देने, प्रारंभिक वर्षों में मूलधन और व्याज की किस्तों की अदायगी का आस्थगन करने आदि जैसे उन प्रोत्साहनों को भी ध्यान में रखेगा जिन्हें वित्तीय संस्थाएं अपनी ओर से पिछले क्षेत्रों में छोटे और मझौले आकार की परियोजनाओं को देने का प्रस्ताव करें।

15. भा० औ० वि० बैंक ने अपने अनुभव का लेखा-जोखा करने तथा बैंक की मूल्यांकन तथा अनुवर्ती कार्यविधि और तकनीक में सुधार लाने के बारे में सुभाव देने की दृष्टि से मार्च 1970 में एक समिति का गठन किया जिसमें भा० औ० वि० बैंक के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त एक औद्योगिक सलाहकार, एक प्रबंध विशेषज्ञ और आवधिक उधारों के क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ थे। इस समिति ने जून 1970 में अपनी रिपोर्ट दी और यह मत व्यक्त किया कि भा० औ० वि० बैंक मूल्यांकन तथा मंजूरी के बाद के पर्यवेक्षण के लिए जो तकनीकों अपना रहा है वे भारत तथा विदेशों की अन्य आवधिक उधार देनेबाली संस्थाओं द्वारा तयार की गई तकनीकों के मुकाबले की हैं। फिर भी, समिति की राय में कुछ क्षेत्रों में बर्तमान व्यवस्थाओं में और अधिक परिष्कार लाने की गुंजाइश है। समिति ने भा औ० वि० बैंक के मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यों को और अधिक कारगर तथा लाभदायक बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिये हैं। संक्षेप में , ये सुझाव इस प्रकार हैं:— भा० औ० वि० बैंक द्वारा प्रवर्तक के पूर्व इतिहास, अनुभव तथा प्रबंध क्षमता का बेहतर निर्धारण, परियोजना के मूल्यांकन के दौरान उद्यमकर्ताओं को परियोजना की कार्यान्विति को सरल बनाने के लिए आरंभ से ही योग्य तकनीकी और प्रवंध कार्मिकों का एक केन्द्रीय आधार बनाने की आवश्यकता समझाना तथा परियोजना कार्याक्रम निर्धारित करने के लिए अधिक सुनिश्चित तकनीक का पालन करने की वांछनीयता पर जोर देना, वित्तीय मूल्यांकन कार्य के अंतर्यंत आंतरिक प्रतिलाभ की दर निश्चित करना जिससे परियोजना की यथार्थ आय क्षमता को सामने लाया जा सकें; और मूल्यांकन, परिचालन और विधि विभागों के बीच काम का पुनर्वितरण करना ताकि किसी कार्य का दोहराव न हो और मंजूर की गई सहायता

का **द**्धिन्न बिसरण निष्चित हो सके । समिति द्वारा सुक्षाये गये सुधार के त्रिभिन्न उपायों को अमल में लाने के लिए पहले से ही कदम उठाये जा चुके हैं।

- 16. पिछली रिपोर्ट में भा० औ० मि० बैंक के इस निर्णय का उल्लेख किया गया था कि सरकारी क्षेत्र की जिन वर्तमान कंपनियों ने कम से कम एक बार लाभांण की बोवणा की हो और जिनके पास अपने नये कार्यक्रमों में आंशिक रूप से पैसा लगाने के काफी आंतरिक साधन हों उनसे विस्तार तथा विशाखन के लिए प्राप्त परिमित मात्रा की प्रत्यक्ष सहायता के आवेदनों पर वैंक गुणावगुण के आधार पर विचार करेगा बशतें कि उक्त कंपनियों संबंधित सरकार से कोई वित्तपोषण प्राप्त न करें तथा भा० औ० वि० बैंक की सामान्य निगरानी तथा अनुशासन को मानने के लिए तैयार हों। इस वर्ष के दौरान भा० औ० वि० बैंक के सामने सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को प्रयक्ष सहायता देने का कोई मौका नहीं आथा हांखांकि इस बारे में कई बार पूछताछ की गई तथा वर्ष के अन्त में बुछ मामलों पर बैंक में सिक्षय कियार हो। यहा था। सार्वजित्क वित्तीय संस्थाओं ने अन गीति के रूप में यह तथ कर लिया है कि वे वित्तीय सहायता के लिए सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों से ही आयेदन प्राप्त करेंगी जी कंपनीं अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों के रूप में निगमित हो तथा इन कंपनियों से उसी आधार पर आवेदन लिये जाएंगे जिस आधार पर वे गैर सरकारी कंपनियों से लिए जाते हैं।
- 17. 3 अप्रैल 1970 से प्रबंध एजेंसी प्रणाली समाप्त कर दी गई। इसके फलस्वरूप जिन औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध एजेंट, या सिचब अथवा कोषाध्यक्ष थे वे अब उनके बदले प्रबंध व्यवस्था के वैकल्पिक स्वरूपों को अपना रही हैं: एक ओर जहां किसी कम्पनी के प्रबंध के वारे में नई व्यवस्था और उसको देय परिश्रमिक पर सरकार का अनुमोदन आवश्यक है वहां दूसरी और जिन अद्योगिक संस्थाओं पर आवधिक वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं की वित्तीय सहायता की राणि बकाया है, उन्हें प्रस्तावित प्रबंध व्यवस्था के लिए संबंधित वित्तपोषण संस्था का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। आवधिक वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं का यह देखना कर्तव्य होगा कि प्रस्तावित प्रबंध व्यवस्था मितव्ययी और दक्ष हो। भाव औव विव बैंक, भाव औव वि निगम, भाव औव ऋव निव निगम तथा जीवन बीमा निगम के विरुट कार्यपालकों की मासिक अंतर संस्था बैंडकों में भाव औव विव बैंक हम प्रकार की समस्याओं पर अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार विमार्ग करता है। अंतर संस्था बैंडक का यह मंच इस प्रकार के महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलों और विशिष्ट परियोजनाओं के वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य पहलुओं पर अन्योचारिक विचार विनिमय के लिए खास तौर पर उपयोगी रहा है।
- 18. भा० औ० वि० बैंक अब अपने कार्यों और भौगोलिक क्षेत्र दोनों के ही प्रसार की दृष्टि से विकास की एक नई मंजिल पर पहुंच गया है। अब से आगे भा० औ० वि० बैंक का एक महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह यह होगा कि वह कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाए, व्यवहार्य परियोजनाओं की सुरपष्ट रूपरेखा तैयार करे तथा इन परियोजनाओं की शीझ कार्यान्विति के लिए बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं सरकारी एजेंसियों, प्रबन्धक तथा तकनीकी परामर्गदाली फर्मों आदि के सहयोग से वित्तीय साधन और उद्यमणील प्रतिभाओं को जुटाने में सहायता करें। एक ओर जहां बैंक की यह नई विकासमूलक भूमिका आने वाले वर्षों में अधिकाधिक महत्व ग्रहण करेगी वहां दूसरी ओर बैंक 1970-71 में अपने कार्यकलापों को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह आणा की जाती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए वित्तपोषण में सहभागिता करने पर भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा। रा० वि० निगमों से अब तक की अपेक्षा अधिक सित्रय संपर्क रखा जा रहा है ताकि वे भा० औ० वि० बैंक से अधिक पुनर्वित्त सहायता प्राप्त कर सकें। देश में फले हुए मशीन निर्माताओं के निकटतर संपर्क स्थापित करके मशीन के बिलों के पुनर्भाजन की बैंक की योजना और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इंजीनियरी और पूंजीगत माल के निर्यात के लिए निर्धारित उच्चतर लक्ष्य के अनुरूप निर्यात सहायता को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक जो विभिन्न प्रकार की विसीय सहायता तथा अन्य सहलियतें प्रक्षान करता है, उनका व्यापक अचार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
- 19. विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के संबंध में भा० औ० वि० बैंक के 1969-70 के दौरान किये गये कार्यो की व्योरे-वार समीक्षा नीचे दी गई है।

औद्योगिक संस्थाओं को दी गई प्रस्थक्ष सहायता (निर्यात के लिए वी गई सहायता को छोड़कर)

20. भा० औ० वि० बैंक प्रत्यक्ष सहायता के अधीन टकनीणनों पर आधारित परियोजनाओं के लिए उदारतापूर्वक सहायता उपलब्ध करके उन परियोजनाओं की स्थापना को विशेष रूपसे ऐसे राज्यों में बढ़ावा देता रहा है जहां भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों का अपेक्षाइत कम असर हुआ है। जिन परियोजनाओं को इस वर्ष के दौरान सहायता दी गई है वे महाराष्ट्र के विदर्भ, आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में स्थित थीं। बैंक ने गैर-परम्परागत क्षेत्रों में नये उद्यमकर्ताओं द्वारा प्रवर्तित तीन योजनाओं का वित्तपोषण करने में अगुआई की। ये योजनाएं ईट बनाने, के स्थनालित संयंत्र पूर्वविमित मकान बनाने की सामग्री तथा कुछ महत्वपूर्ण निवारक औषधियां बनाने से संबंधित थीं जिनका देश में पहली बार निर्माण किया जा रहा है। भा० औ० वि० बैंक ने एक विकास एजेंसी द्वारा अपेक्षाइत कम विकसित क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर शुरू किए गए सूती वस्र उद्योग की परियोजना के जिए वित्तपोषण करके एक नये क्षेत्र में पदार्पण किया।

21. संयुक्त क्षेत्र में स्थापित एक बड़ी उर्वरक परियोजना को इस वर्ष (2.9 करोड़ रुपयों की) हामीदारी के रूप में तक्त्यता मंजूर की गई। भा० औ० वि० बैंक अब तक गैर सरकारी क्षेत्र की आट उर्वरक परियोजनाओं के लिए 49.2 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर कर चुका है जिनमें से 6 उर्वरक कारखाने व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करने लगे हैं। भा० औ० वि० बैंक के पास तीन और उर्वरक परियोजनाएं विचाराधीन हैं। इनमें से दो गैर सरकारी क्षेत्र की हैं और एक सहकारी क्षेत्र की हैं। इनमें से एक परियोजना संभवतः अगले कुछ महीन के भीतर ही सहायता पाने के लिए योग्य हो जाएगी।

22. 1969-70 के दौरान भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का ब्योरा सारणी 5 में दिया गया है। जिन औद्योगिक परियोजनाओं को इस वर्ष सहायता प्रदान की गई है, उनकी सूची अनुबंध II (क) में दी गई है।

23. जून 1969 में भा० औ० वि० बैंक ने धीरे-धीरे उन शेयरों को बेचने की नििति शुरू की जो उसने हामीदारी के अपने वायदों को पूरा करने के लिए खरीदे थे ताकि शेयर बाजरों में अच्छे ऋणपत्नों की अपेक्षाकृत कमी दूर की जा सके और जनता के बीच शेयरों का अधिक व्यापक प्रसार करने में मदद मिल सके। शेयरों की यह बिकी मान्यताप्राप्त दलालों के जरिए चालू भाव पर छोटे- छोटे समृहों में की जाती है। जून 1970 के अंत तक बैंक द्वारा की गई निवेशों की कुल बिकी (अंकित मृत्य) की राशि 2.4 करोड़ रुपये थी। इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आपस में तय की गई दर पर सीधे ही बेचे गये अधिमान शेयरों और डिबेंचरों की राशि शामिल है।

सारणी 5--1969-70 और 1968-69 में मंजूर की गई प्रत्यक्ष विसीय सहायता का न्योरा

(करोड़ रुपयों में)

		मंजूर की गयी सहायता								
	परियोजनाओं की संख्या		ऋ ण		• हामीदारी		गारंटी		जोड़	
	1969-	1968-	1969-	1968-	1969- 1970	1968-	1969-	1968-	1969-	1968- 69
1. नई परियोजनाओं को						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
सहायता .	11	6	4.3	0.7	5.4	0.3	0.1	-	9,8	1.0
 विस्तार/विशाखन/ अभिनवीकरण की 										
यीजनाओं के लिए सहायता	4	8	1.2	7.6	0.1	1.8	2.4	0.01	3.7	9.4
 औद्योगिक संस्थाओं को 		-								
अनुपूरक सहायता*	7	9	2.1	7.7	0.3	0.2			2.4	7.9
 सहायता प्राप्त संस्थाओं के स्वामित्व शेयरों में 										
अभिदान .		-11			0.4	0.1			0.4	0.1
— ⊸ - जोड़	22	23	7.6	16.0	6.2	2.4	2.5	0.01	16.3	18.4

24. यह तसल्ली करने के लिए, सहायता-प्राप्त परियोजनाएं निष्चित कार्यक्रम के अनुसार भाल रही हैं और कंपनियों का कारोबार दक्षतापूर्वक तथा लाभदायक ढंग से चलाया जा रहा है, भा० औ० वि० बैंक की अनुवर्ती कार्य-प्रणाली के अन्तर्गत जो कदम उटाए जाते हैं उनमें परियोजना की कार्यान्वित और परिचालन के दौरान समय समय पर प्रगति रिपोर्ट मंगाना, की गई प्रगति को वस्तुतः देखकर उसका सत्यापन करने के लिए परियोजना स्थलों के दौरे करना तथा सहायता-प्राप्त कंपनी के कारोबार का निरीक्षण करना णामिल है। 1969-70 के दौरान 32 कंपनियों के मुआयने और निरीक्षण किये गये। अब निरीक्षणों से संबंधित काम क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप दिया गया है और इसके बाद अधिक नियमित आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई करना संभव हो सकेगा। जहां आवश्यक हो वहां अपेक्षित अनुभव रखने वाले परामर्शदाताओं से भी सलाह ली जाती है ताकि सहायता-प्राप्त

^{*}अर्थात् (1) रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप परियोजना की लागत के अधिक बढ़ जाने, िक्रयान्विति में देर होने, मशीनों और इमारती सामग्री लागत में बृद्धि होने और अनुमानित नकदी साधनों आदि की कमी को पूरा करने, (2) जिन कंपनियों ने अचल आस्तियों के अर्जन के लिए कार्रकारी पूंजी की निधियों का पहले ही उपयोग कर लिया था उनके नकदी साधनों पर पड़ने वाले दबाव की कम करने, (3) परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए संतुलन उपस्कर खरीदने और (4) वित्तीय पुनर्गटन, आदि के लिए दी गयी सहायता ।

संबंधित कंपनियों के कार्यकारी परिणामों में सुधार लाने के लिए उपयुक्त साधन खोजे जा सकें। जहां यह जरूरी होता है कि कंपनी के कारोबार पर या तो उसको दी गई सहायता के परिमाण' अथवा उसके सामने उपस्थित विशेष समस्याओं के कारण अपेक्षाकृत अधिक निगरानी रखी जाए वहां भा० औ० वि० बैंक ऐसे कारखानों के निदेशक बोर्ड में अपना नामित निदेशक नियुक्त करने के अपने अधिकार का भी प्रयोग करता है । सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार ऐसी उपयुक्त व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अन्य वित्तीय संस्थाओं से परामर्श करके इस अधिकार का और ज्यादा बार तथा कारगर प्रयोग किया जा सके।

नियति के सिए प्रस्यक्ष ऋण और गारंटियां

25. पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अनुमोदित वाणिज्य बैंकों की सहभागिता में इंजीनियरी बस्तुओं और हेवाओं के निर्यात के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों की आँद्योगिक संस्थाओं को कम ज्याज दर पर प्रत्यक्ष आवधिक वित्त और गारंटी सुविधाएं देने की एक योजना दिसम्बर 1968 से अपनाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों ही अवस्थाओं के दौरान 6 महीने से अधिक की अविध के लिए नियति ऋण और नियतिकों की ओर से निष्पादन तथा वित्तीय गारंटियां देने की व्यवस्था है। भा० औ० वि० बैंक अपने नियति ऋण के भाग पर 🛂 प्रतिशत की दरसे क्याज लेता है और सहभागी बैंक अपने भाग पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत से अनिधक क्याज दर पर ब्याज लगाते हैं। बैंक को प्रस्तृत किये गये नियति प्रस्तावों के संबंध में बैंक के दुष्टिकोण की यह विशेषता रही है कि वह कुछ सीमा तक लचीला ही रहा है ताकि निर्यातकों की बदलती हुई आवश्यकताओं और प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जा सके।

26. इस योजना के अंतर्गत भा० औ० वि० बैंक ने इस वर्ष के दौरान वस्त्र उद्योग की मशीनों इस्पात की पटरियों, आटोमो-बाइल चेसिज, पारेषण लाइन टावरों, ए०सी० एस० आर० और तांबे के संवाहक तथा इस्पात के शटर व स्केफोल्ड की सामग्री के निर्यात के लिए 11.2 करोड़ रुपयों के 14 पोतलदानोत्तर ऋण मंजूर किये ^क । बैंक ने 1968-69 के दौरान दो आवेदनों पर 7.1 करोड रुपयों की ऋण और गारंटी सुविधाएं मंजर की। भार और बिर बैंक ने ऐसे कई निर्यात प्रस्तावों के संबंध में सिद्धांतत: सहायता देना स्त्रीकार कर लिया है जो अभी विचार विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । 30 जून 1970 को वस्त्र उद्योग की मणीनों और उनके पूर्जों, रेल के बैगनों, बायलरों आदि के निर्यात से संबंधित कुल 12.8 करोड़ रुपयों के मुख्य के पांच आवेदन विचाराधीन थे।

बेकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी जाने बाली सहायता

27. भा० औ० वि० बैंक द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत ये मदें आती हैं: (i) योग्य संस्थाओं द्वारा दिये गये औद्योगिक ऋणों और निर्यात ऋणों के लिए उन्हें दिया गया पुनर्वित्त (ii) आविधक उधार देनेवाली योग्य संस्थाओं (राज वित्त निगमों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम) के शेयरों और बांडों में अभिदान करना ताकि उनकी साधन स्थिति सुदृढ़ हो सके और (iii) ऐसे बिलों, वचनपत्नों का पुनर्भाजन जो देशी मशीनों की आस्थगित अदायगी के आधार पर की गयी बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त हुए हों और जिनका भाजन बैंकों द्वारा किया गया हो।

औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्विश

28, भा० औ० वि० मैंक ने 1967-68 और 1968-69 के दौरान पुनर्वित्त सुविधाओं के क्षेत्र को बढ़ाने और उनकी लागत को कम करने के कई उपाय किए थे ताकि उद्योग के लघु और मझोले आकार के क्षेत्रों को अधिक मात्रा में निधियां उपलब्ध ही सकें। ऋण गारंटी योजना के अधीन आने वाले लघु उद्योग कारखानों को दिया जाने वाला जो ऋण पुनर्वित्त पाने के योग्य होता है उसकी न्यूनतम राश्चि को भा० औ० वि० बैंक ने मई 1970 में 20,000 रुपयों से घटा कर 10,000 रुपये कर दिया ताकि बैंक और राज्य वित्त निगम लघु उद्योग के कारखानों की अधिक संख्या में सहायता कर सकें।

29. उधार की लागत कम करने और पुनिवित्त की राशि शीध आहरित कर सकने की दृष्टि से पुनिवित्त के आहरण की वर्त-मान विधि को सरल बनाया गया। पुनर्वित योजना में भी सुधार किया गया ताकि उधार लेनेवाले उद्योग कारखानों से प्राप्त होनेवाली प्रतिभूतियों/प्रतिभूतियों के दस्तावेजों का लेन देन करने से संबंधित वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं की कार्यविधि को और अधिक लचीला बनाया जा सके।

30. 1969-70 के दौरान औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त की योजना के अन्तर्गत भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों (सारणी 6) में दो स्पष्ट विशेषताएं दृष्टिगोचर हुई हैं; (क) मंजूर किये गये आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और (ख) लधु उद्योग के कारखानों (छोटे सड़क परिवहन चालकों सहित) को दी जानेवाली सहायता में क्रांमक वृद्धि ।

[†] देखिये परिशिष्ट I

सारणी 6--औद्योगिक ऋणों की पुनर्विस व्यवस्था

करोड़ रुपयों में

				-	1969-70 (जुलाई-जून)		1968 (जुलाई-	
			*		संख्या	राष्ट्री	संख्या	रागि
1. प्राप्त आवेदन					1231	23.7	426	15.2
 स्वीकृत आवेदन * . 					992	16.2	336	15.2
 (अवधि के अंत में) विचाराधीन आवेदन 			•		306	14.3	156	12.0
 कुल प्रभाषी मंजूरियां . 			•	•	966	15.7	321	14.1
 पुनर्वित्त की वितरित राशि . 		,	•	•		12.5		11.6
 पुनिवत्त की अदायगी . 	•					14.0		14.4
7. अस्वीकृत/बापस लिये गये/लौटाये गये	आवेदन			•	89	5.1	28	2.5
8. (अवधि के अंत में) बकाया राशि			•			60.1		61.6
9. (अवधि के अंत में) स्वीक्रुत की गर्य	अवितरि	रंत राशि				14.4	•	12,7

नोट :--इस सारणी में दिये गये आंकड़े केवल औद्योगिक ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था से संबंधित हैं। इनमें निर्यात ऋण णामिल नहीं हैं।

1968-69 में जहां औद्योगिक ऋणों के संबंध में मंजूर किये गये पुनिवित्त की कुल राणि 321 अवेदनों पर 14.1 करोड़ रुपये ही थी वहां 1969-70 में वह बढ़कर 966 आवेदनों पर 15.7 करोड़ रुपये हो गयी। 1969-70 के आंकड़ों में छोटे सड़क परिवहन चालकों से प्राप्त 625 आवेदनों पर 3.1 करोड़ रुपयों की मंजूर की गयी राणि भी ग्रामिल हैं। 1968-69 में इस मद में 17 आवेदनों पर दी जाने याली तदनुरूपी राणि 5 लाख रुपये थी। लघु उद्योग की इकाइयों को दिये गये पुनिवित्त की राणि 1968-69 के 185 आवेदनों पर 2.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 243 आवेदनों पर 3.7 करोड़ रुपये हो गयी जिसमें से 61 लाख रुपयों की राणि के लिए प्राप्त 114 आवेदनों में से प्रत्येक की राणि एक लाख रुपयों से कम थी। वितरित किये गये पुनिवित्त की राणि 11.6 करोड़ रुपयों से बढ़कर 12.5 करोड़ रुपयों तक पहुंच गयी।

31. औद्योगिक ऋण पर दिये गये पुनर्वित्त का संस्थावार विभाजन करने पर पता चलता है कि कुल पुनर्वित्त में से राज्य वित्त निगमों को दिये गये अंग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है; भा० औ० वि० बैंक हारा मंजूर किये गये कुल पुनर्वित्त में से इन संस्थाओं को लगभग दो-तिहाई पुनर्वित्त प्रदान किया गया है (सारणी 7)। राज्य वित्त निगम मुख्य रूप से लघु उद्योगों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को दिये गये ऋणों के संबंध में ही पुनर्वित्त प्राप्त करते रहे हैं। सारणी 8 से यह पता चलता है कि 1968-69 और 1969-70 में लघु उद्योगों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को सहायता प्रदान करने के लिए 14 राज्य वित्त निगमों ने भा० औ० वि० बैंक से पुनर्वित प्राप्त किया (जब कि 1967-68 में केवल 4 राज्य वित्त निगमों ने ही पुनर्वित्त प्राप्त किया था)। पुनर्वित्त की राशि 1968-69 के 202 आवेदनों पर 2.7 करोड़ रुपयों से बढ़कर 882 आवेदनों पर 6.7 करोड़ रुपये हो गयी। भा० औ० वि० बैंक की पुनर्वित्त सहायता का अधिक व्यापक वितरण हुआ और जहां 1967-68 में 14 जिलों में पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गदी थी वहां 1968-69 में 72 और 1969-70 में 95 जिलों में यह सहायता प्रदान की गई है।

मध्यावधि निर्यात ऋण का पुनिवस

32. पिछलं वर्ष निर्मात विक्त के लिए सहभागिता की जो योजना चलायी गयी थी उसके साथ-साथ भा० औ० वि० बँक ने पूंजीगत और इंजीनियरी माल के निर्मातकों को योग्य बैंकों द्वारा दिया गये मध्यावधि निर्मात ऋणों के पुनर्वित्त की योजना भी आरी रखीं। इस योजना के अन्तर्गत 4½% पर शतप्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है और उधार देने वाले बैंक 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज महीं ले सकते। इस वर्ष बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन लिया जाने वाला पुनर्वित्त कम हो गया। संभवतः निर्मातक नयी योजना के अधीन निर्मात ऋणों पर ब्याज की कम औसत दर का लाभ उठा रहे हैं। अतः 1969-70 के दौरान 5 आवेदनों पर के बला 1.3 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गयी जबिक इसकी तुलना में 1968-69 के दौरान 11 आवेदनों पर 7.3 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर की गयी थी (सारणी 9)। निर्मात की मदों में पारेषण लाइन टावर, ए० सी० एस० आर० और तांबे के संवाहक, वस्न निर्माण की मणीनें, डीजल इंजिन, पम्प सेट, आटा मिल की मणीनों के पुजें और अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं।

^{*}कुल मंजूरियां।

[†] धेखिये परिशिष्ट II.

•	सार	णी 7अं	ोद्योगिक त्र	हणों के रि	तए किए ग	ए पुनर्बि	स्त का संस्थावा	र विभाजन	(कर	ोड़ रुपयों में)
							1969		1968	-69
				-			मंजूर की गयी राशि*	वितरित राशि	मंजूर की गयी राणि*	वितरित राशि
वाणिज्य बैंक					·		5.8 (35.8)	6.0 48.0	6.1 (40.1)	5.1 (44.0)
राज्य सहकारी बैंक			•				` <u>-</u>	****	` <u>'</u>	`
राज्य वित्त निगम	•		•		•		$\begin{pmatrix} 1 \ 0 \ . \ 4 \\ (64 \ . \ 2) \end{pmatrix}$	$\binom{6.5}{52.0}$	9.1 (59.9)	6.5 (56.0)
		•					16 2	19 5	15 2	11 6

^{*}कुल मंजूरियां।

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत है।

सारणी अ—लघु उद्योगों और छोटे सड़क परिवहन चालकों को राज्य किस निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर किया गया पुनर्वित्त

					पुनर्वित्त ^ह आने वा	के अंतर्गत ले जिले		मंजूर की गयी ⊶————————————————————————————————————	सहायता‡	
					1969-70	1968-69	19	69-70	19	68-69
					1909-70	1900-09	आवेदनों की संख्या	रकम (लाख रुपयों में)	आवेदनों की संख्या	रकम (लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश			-	ı	3	9	3	1.8	23	34.1
बिहार		•			5	4	8	20.7	6	12.1
गुजरात	•	•	•	•	18 (18)	15	502 (419)	2 8 1.9 (205.1)	74	80.8
हरियाणा				•	6		19	34.9		
केरल			•		-,	1			1	2.0
मध्य प्रदेश	•				8	1	11	9.3	1	2.2
महाराष्ट्र			4		18	5	240	161.9	12	28.9
					(18)	(1)	(207)	(97.6)	(1)	(0.4)
मै सूर	•	•	•	•	4 (1)	$\begin{pmatrix} 1 \ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$	5 (1)	15,5 (0.3)	37 (15)	37.2 (4.6)
उड़ीसा	٠	•	•	•	$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,	. 1	4 (1)	5.8 (0.5)	1	0,6
पंजाब		•		•	6	2	11	17.5	5	5.7
राजस्थान		•		•	4	5	8	21.5	- 11	13.3
तमिलनाडु		•		•	3	5	3	7.8	5	21,9
उत्तर प्रदेश			•		12	6	24	46.8	9	18,€
पश्चिम बंगाल		•	•	•	3	4	4	3.6	10	8.8
संघणासित क्षेत्र	7	•	•	•	3@ (1)	3@	$\begin{pmatrix} 40 \\ 21 \end{pmatrix}$	40.4 (9.3)	7 (1)	5.5 (0.5)
जो	ोड़ 		•		95 (39)	72 (7)	882 (649)	669.4 (312.8)	202	271.7 (5.5)

नोष्ट:---कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मुख्य आंकड़ों में शामिल छोटे सड़क परिवहन चालकों को मंजूर की गयी सहायता के हैं। प्रभावी मंजुरियां।

[्]रेये आंकड़े महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के राज्य वित्त निगमों को उनके द्वारा क्रमशः गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दिल्ली के संघणासित क्षेत्रों की लघु इकाइयों को दिये गये ऋणों के संबंध में दी गयी पुनर्वित्त सहायता से संबंधित हैं।

सारणी १---निर्वात ऋण के लिए पूर्नावस

(करोड रुपये में)

						(3,40	9 644 A)
					69-70 ाई-जून)	(जुलाई	68-69 -जून)
				———— संख्या	राशि	———— संख्या	राशि
1 प्राप्त आवेदन			,	5	1.3	13	9.1
2. मंजूर किये गये आवेदन*			•	5	1.3	11	7.5
3. (अवधि के अन्त में) विचाराधीन आवेदन			•	1	0.2	1	0.2
4 कुल प्रभावी मंजूरियां	•	•		5	1.3	11	7.3
5 वितिरित पुनर्वित्त	•				2.7		2.5
 पुनर्वित्त की वापसी अदायगी 	•				1.4		0.3
7. अस्वीकृत/वापस लिये गये/लौटाये गये आवेदन			•			2	0.1
8. (अवधि के अन्त में) बकाया राशि		•			3.6		2.4
9. (अवधि के अंत में) अवितरित राशि					3,5		5.2

^{*}कुल मंजुरियां

अन्य वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और डिबॅसरों में अभिवान

33. अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त तथा पुनर्भाजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के अलावा भा० औ० वि० बैंक इन संस्थाओं की शेयर पूंजी तथा बांड इज़रों में अंशदान करके उनके वित्तीय साधनों की स्थिति को मजबूत बनाने में भी सहायता पहुंचाता है। यद्यपि 9 राज्य निगमों ने 1969-70 में 10.4 करोड़ रुपयों के बांड बाजार में जारी किये थे, तथापि इन इज़रों में ज़रूरत से ज्यादा अंशदान किया गया और भा० औ० वि० बैंकों को इन इज़रों में अंशदान करने का मौका नहीं मिला। 1968-69 में भी० भा० औ० वि० बैंक ने मामूली सहायता ही दी थी। इस वर्ष राज्य वित्त निगमों द्वारा शेयर पूंजी के लिए जनता को शेयर नहीं बेचे गये। अपनी स्थापना से लेकर अब तक भा० औ० वि० बैंक ने बांड इज़रों में 5.2 करोड़ रुपयों (अंकित मूल्य) का और राज्य वित्त निगमों के शेयर पूंजी इज़रों में 1.2 करोड़ रुपयों का अंशदान किया है। दिसम्बर 1969 में भा० औ० ऋ० नि० निगम द्वारा जनता के लिए जारी किये गये 5 करोड़ रुपयों के डिबेंचरों में भा० औ० वि० बैंक के अभिदान की राशि 49.8 लाख रुपये थी जिसे मिलाकर जून 1970 तक भा० औ० ऋ० नि० निगम के सार्वजनिक और विशेष इज़रों में उसकी कुल अभिदत्त राशि 13.9 करोड़ रुपये थी।

पुनर्भाजन सहायता

- 34. भा० औ० वि० बैंक ने अप्रैल 1965 में आस्थिगत अदायगी पर देशी मणीनों की बिकी के अन्तर्गत आनेवाले बिलों/ नचनपत्नों के पुनर्भाजन की एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत मणीनों का उत्पादन करने वाले सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योग आते हैं। आस्थिगत अदायगी की अवधि सामान्यतः 5 वर्षों तक और विशेष मामलों में 7 वर्षों तक रहती है। पुनर्भाजन की दर बिलों की शेष अवधि के आधार पर 4½ प्रतिशत और 5½ प्रतिशत के बीच रहती है और इन बिलों का भांजन करनेवाले बैंक इन दरों से 1 प्रतिशत से अधिक की दर से भांजन नहीं ले सकते। पुनर्भाजन की इस योजना के प्राय: अपने आप ही चलने से मशीनों के निर्माताओं तथा तथा खरीदार उपभोक्ताओं, दोनों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ गयी है। छोटे और मझौले उद्योगों को अपने उपस्करों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने में उक्त योजना से विशेष सहायता मिली है। पुनर्भाजन बिलों की राशि 1965-66 के 2.2 करोड़ रुपयों से उत्तरोत्तर बढ़कर 1968-69 में 18.5 करोड़ रुपये और 1969-70 में 24.1 करोड़ रुपये हो गयी। जून 1970 के अंत तक दी गई कुल सहायता की राशि 61.4 करोड़ रुपये थी जिसका लाभ कुल मिलाकर 160 मशीन निर्माताओं और 793 खरीदार उपभोक्ताओं ने उठाया है।
- 35. मशीनों के खरीदार-उपभोक्ताओं के विश्लेषण से इस बात का पता चलता है कि यह सहायता पहले की तरह सूती बस्न और चीनी उद्योगों में ही केन्द्रीभूत हो गई है हालांकि जो दूसरे उद्योग इस सहायता पर निर्भर करते हैं उनकी संख्या पिछले वर्षों में बढ़ गयी है; ऐसे उद्योगों की सूची में अब इंजीनियरी (मशीन औजारों को मिलाकर), बिजली की मशीनें, प्लास्टिक, तेल घोलकों के निस्सारण संयंत्र आदि भी आते हैं। जिन खरीदार-उपभोक्ता उद्योगों को इस वर्ष पहली बार वित्तीय सहायता प्रदान की गयी उनमें कृषि उद्योग, फिल्म उद्योग और छपाई उद्योग आते हैं।
- 36. उक्त योजना पर लगातार पुनर्विचार होता रहा है और उसमें समय समय पर संशोधन किये गये हैं ताकि उससे मशीनों के निर्माताओं और खरीदार-उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें। इस वर्ष किया गया महस्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि इस योजना के अधीन राज्य बिजली बोर्ड खरीदार-उपभोक्ता के रूप में जिस अधिकतम सीमा तक सहायता प्राप्त कर सकते थे उसे 50 लाख रुपयों से बढ़कर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि इसके पहले की सीमा राज्य बिजली बोर्डों के विस्तार र किम के लिए आवश्यक भारी

विद्युत मशीनों को प्राप्त करनेके लिए अपर्याप्त मानी गयी। इस योजना के क्षेत्र को इस वर्ष और व्यापक बना दिया गया और उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में गठित कृषि उद्योग निगमों, किसानी उद्यमों, दस्तूरी कृषि सेवाओं और कृषि मशीनरी के किराया खरीद केन्द्रों द्वारा की जानेवाली ऐसी खरीदों को भी लाया गया जो, उक्त केन्द्र कृषि मशीनों/उपस्करों के निर्माताओं से उनके वितरकों/विकेताओं के रूप में करते हैं।

37. यद्यपि उक्त योजना ने काफी प्रगति की है, फिर भी इस बात की काफी गुंजाइण है कि उसके अंतर्गत अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को लाया जाए तथा आजकल की अपेक्षा को और अधिक संख्या में उसके अंतर्गत लाया जाए । भा० औ० वि० बैंक का एक अधिकारी शीघ्र ही उन राज्यों का दौरा करेगा जिनमें योजना की ज्यादा प्रगति नहीं हुँई । ताकि यह पता चल सके कि मशीनरी निर्माता इस योजना का लाभ उठाने में किन व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं।

समय वित्तीय सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण

38, भा० औ० वि०वैंक द्वारा जुलाई 1964 से जून 1969 तक की अविध में और 1969-70 में औद्योगिक परियोजनाओं को दी गयी कुल सहायता का उद्योगवार विवरण सारंणी 10 में दिया गया है (अनुबन्ध III भी देखिए) । 1969-70 में मंजूर *यह सीमा अक्तूबर से सितंबर तक के एक वर्ष के लिए लागू मानी जाएगी।

सारणी 10--- जुलाई 1964 से जून 1969 तक की अवधि में और 1969-- 70 में भा० औ० वि० बेंक द्वारा मंजूर की गई और विसरित की गई सहायसा का उद्योगवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपयों में)

			जुलाई 196	4-जून 1969			19	969-70	
	- उद्योग	मंजूर की गयी सहायता	कुल राशि से प्रतिशत	वितरित की गयी सहायता			कुल रागि से ा प्रतिशत		कुल राणि से ता प्रतिणत
1.	पेय पदार्थी को छोड़			_					
	खाद्य पदार्थों के उद्योग	4.5	1.9	4.5	2.2	1.9	3.5	0.5	1,1
2.	वस्न (जूत सहित) .	33,0	13.9	31,2	15,3	6.3	11.7	4.8	10.4
3.	कागज और कागज की चीज	में 14.1	5,9	8.6	4.2	0.3	0.6	0.3	0.7
4.	उर्वरकों को छोड़कर मूल								
	औद्योगिक रसायन	25.9	10.9	21.1	10.3	2.1	3,9	4.6	10.0
5.	अन्य रसायन और								
	रासायनिक पदार्थ .	11,6	4.9	9.6	4.7	2,1	3.9	1.8	3.9
6.	उर्वरक .	35.5	14.9	34.2	16.8	3,2	6.0	1.7	3.7
7.	सीमेंट .	13.4	5.6	10,6	5.2			1.1	2.4
8.	मूल धातु के उद्योग (मिश्र और विशेष इस्पात सहित) .	23.7	9,9	15,4	7.6	0.8	1.5	3.3	77 1
9.	बिजली की मशीनरी को छोड़कर मशीनरी	23,7	9. 9	15, 4	7.6	0, 8	1, 5	3.3	7.1
	कानिर्माण .	51.8	21,8	44.7	21.9	25.5	47.5	22.6	48.9
10.	बिजली की मशीनरी								
	का निर्माण .	10.3	4.3	9,5	4.7	0.9	1.7	0.8	1.7
11.	सेवाएं	1.6	0.7	1.3	0.6	3.3	6.1	1.5	3.2
	बहन के लिए)	(0.1)	()	(0.1)	()	(3.2)	(6.0)	(1,2)	(2.6)
12.	अन्य उद्योग .	12.7	5,3	13.3	6.5	7.3		6 3,2	6.9
	जोड़ .	238.1	100.0	204.0	100.0	53.7	100.0	46.2	100.0

^{*}इनमें (निर्यातों के लिए दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों को छोड़कर) प्रत्यक्ष ऋण, हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान, औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त और पुनर्भाजन सहायता शामिल हैं।

^{. .} नगण्य ।

सारणी 11--जुलाई 1964-जून 1970 में भा० औ० वि० बेंक द्वारा

मंजूर की गयी सहायता (प्रभावी)

	राज्य	ऋण निर्यात के लिए दिये गए ऋणों को छोड़कर	निर्यात के लिए दिए गए ऋण	हामीदारी और प्रस्पक्ष अभिदान	गारंटी	औद्यौगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त	निर्यात उधारों के लिए पुर्नावस	पुनर्भाजन	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	1066,0		132.5		665,6	——		1864.1
2.	असम .					12.4			12.4
3.	बिहार	570.5	<u> </u>	30.0		125.1		146.5	872.1
4.	गुजरात	1900.0	_	394.7	511.9	1119.5		375.8	4301.9
5.	हरियाणा	13.2		56.0	8.4	349.1		2.4	429.1
6.	जम्मू और काश्मीर								_
7.	केरल	147.0		4.0		366.8		0.7	518.5
8.	मध्य प्रदेश	98.0	449.0	88.5		324.8		321.4	. 1281.7
9.	महाराष्ट्र	2620.3	733.2	671.2	1390.0	2851.4	756.0	2858,5	11880.6
10.	मैसूर	279.8		221.0	-	433,2		456.6	1390.6
11.	नागा लै ण्ड				-				
1 2.	उड़ीसा	380.0		44.0		56.2		37.0	517.2
13.	पंजाब			_		130.4			130.4
14.	राज स्था न	366.0	62.5	5.0	278.1	174.5	251.3		1137,4
15.	तामिल नाडु	1235.5	179.0	174.6	1.1	1844.6		743.2	4178.0
16.	उत्तर प्रदेश	504 0		84.0	295.0	333.4		109.4	1325.8
17.	पश्चिम बंगाल	1357.0	352,3	95.9	241.5	1002.2	21.1	1051.1	4121.0
18.	सं घगा सित क्षे त्र	200.0		292.4		218.0	· •	39.5	749.9
	जोड़ जोड़	10737.3	1776.0	2293.8	2725.9	10007.2	1028.4	6142.1	34710.7

िष्पणी: (i) प्रत्येक राज्य में जिन परियोजनाओं को सहायतादी गयी है, उनके निर्माण स्थल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कुछ मामलों में एक से अधिक राज्यों में वर्तमान कारखानों के विस्तार/नये कारखानों की स्थापना के लिए सहायता मंजूर की गयी थी,ऐसी सहायता उस राज्य में शामिल की गयी है जिसे अपेक्षाकृत अधिक सहायता दी गयी है। पुनर्भाजन का वर्गीकरण मशीनरी के निर्माताओं /विकेताओं के स्थान पर के आधार पर किया गया है।

⁽ii) इन आंकड़ों में राज्य विक्त निगमों तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के शेयरों और बाण्डों में कियें गये अभिदान के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

मंजूर और वितरित की गई विसीय सहायता का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

	=	वितरित र्क	गियी सहायता (f	जनमें निष्पादित की ग	ई गारंटियाँ शामिल ——————	₹)	
ऋण (निर्यात के लिए दिए गए ऋणों को छोड़कर)	निर्यात के लिए दिए गए ऋण	हामीदार्र और प्रत्यक्ष अभिदान	ो गारंटी	औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित*	निर्यात उधारों के लिए पुनर्वित	पुनर्भाजन	जोड़
985.0		57.0		706.9			1748.
		-		24.4			24.
453.0		8.9		158.0		125.6	745.
1840.0		373.5		991.7	_	322.2	3527.
		11.3	8.4	312.3	_	2.1	334,
		—		30.0		_	30.
140.0		3.9	_	367.0		0.6	511,
42.0	_	48.8	·	323.9		275.6	690.
2242.1	93.8	534.6	1363.3	2667.5	406.9	2451,2	9759.
171.0		155.9	Param	420.9	-	391.5	1139.
	_					·	_
60.0		43.5		103.5		31.7	238.
_				144,6			144.
175.0	N-4	4.6	278.1	200.4	245.0	_	903.
1178.0	28.8	122.0	1.1	1788.9		637.3	3756.
491.3		70.0	295.0	251.7	<u></u>	93.8	1201.
499.0	169.2	86.8	-	1023.4	21.1	901.3	2700.
200.0		67.7		174.7	_	33.9	476.
8476.4	291.8	1588.5	1945.9	9689.8	673.0	5266.8	2 7932 .

^{*}इसमें औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सितम्बर 1964 में भा० औ० वि० बैंक के साथ अपना विलय होने से पहले मंजूर किए गए पुनर्वित्त से सम्बन्धित वितरण शामिल हैं।

की गई सहायता का अधिकांश भाग मुख्यतः मणीन निर्माताओं को दिया गया और उनके बाद णेष भाग ऋमणः वस्त्र उद्योग, उर्फरकों, रासायनिक पदार्थों और सड़क परिवहन के लिए दिया गया। निम्नलिखित निर्माण उद्योगों को पहली बार सहायता दी गयी, पानी के कुएं खोदने के रिग और उनके अनुषंगी पुर्जे बनानेवाले उद्योग, पूर्वनिर्मित इमारतों के सामान (प्रिफ़ेक्किकेटेड बिल्डिंग मेटीरियल) का उद्योग, ट्रांसफार्मर तेल उद्योग, गाजों, विनयरों और जमीन मापने के फीता टेपों जैसे औजारों के उद्योग, मणीनीकृत ईट/टाईल बनाने के सन्यन्त्र, गामा, ग्लोबुलिन और ऐल्बुमिन जैसी निवारक औषधियाँ बनाने के उद्योग तथा सब्जियों का निर्जलीकरण उद्योग।

सहायता का राज्यबार वितरण

39. भा० औ० वि० बैंक द्वारा जून 1970 के अन्त तक दी गई कुल सहायता का राज्यवार वितरण सारणी II में दिया गया है। अब तक अपेक्षाकृत अधिक विकसित इने-गिने राज्यों को ही बैंक की सहायता का अधिकांश भाग मिला है। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि ऐसे राज्यों से सहायता के लिए बहुत बड़ी संख्या में और दूसरों से बहुत कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए क्योंकि जिन राज्यों से कम आवेदन आए हैं वहाँ बिजली परिवहन जैसी उद्योग की उन मूलभूत सुविधाओं और स्थानीय उद्यमकर्ताओं का अभाव था जो औद्योगिक विकास के आवश्यक अंग हैं। इसके बावजूद भा० औ० वि० बैंक कम विकसित क्षेत्रों में स्थापित की जानेवाली परियोजनाओं के लिए उदारीकृत आधार पर सहायता प्रदान करके उनपर विशेष ध्यान देता आ रहा है। इस प्रकार 1969-70 में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों और गोवा के संघशासित क्षेत्र जैसे अपेक्षाकृत ऐसे कम विकसित क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष ऋण दिया गया जहाँ विगत वर्षों में भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों का कम प्रभाव पड़ा है। यह आशा की जाती है कि भा० औ० वि० बैंक के कार्यकलापों का भौगोलिक विशाखन हो जाने और पिछड़े हुए क्षेत्रों की प्रगति में महस्वपूर्ण योगदान देने के लिए बैंक द्वारा किए गए संकल्प से भविष्य में भा० वि० बैंक की वित्तीय सहायता का अधिक व्यापक वितरण करने में सहायता मिलेगी।

विकास सहायता निधि*

40. 1969-70 के दौरान विकास सहायता निधि (वि० स० निधि) में से सहायता के लिए कोई नई मंजूरी नहीं दी गई। भा० औ० वि० बैंक ने अब तक इस निधि में से तीन परियोजनाओं के लिए 33.2 करोड़ रुपयों की सहायता मंजूर की है जिसमें 5.1 करोड़ रुपयों की आस्थगित अदायगी गारन्टी के अतिरिक्त 25.4 करोड़ रुपए के ऋण और 2.7 करोड़ रुपए की हामीदारी सहायता शामिल है।

41. 1969-70 के दौरान इस निधि में से वितरित की गई राणि 35 लाख रुपए थी जो गेडे आयरन एण्ड स्टील कं० लि० को 1968-69 में मंजूर की गई अतिरिक्त ऋण सहायता है। वि० स० निधि के शुरु किए जाने से लेकर जून 1970 के अन्त तक इस निधि में से वितरित की गई राणि 27.9 करोड़ रुपए हैं। इस वर्ष इस निधि के लिए सरकार से कोई नए उधार नहीं लिए गए। भा० औ० वि० बैंक ने भारत सरकार से 1964-65 में लिए गए एक लाख रुपयों के ऋण की वापसी अदायगी की। 30 जून 1970 को इस निधि में सरकार से लिए गए उधारों की बकाया राणि 27.3 करोड़ रुपए थी। वि० स० निधि के प्रशासन खर्च की व्यवस्था के लिए सामान्य निधि में 4.9 लाख रुपए का अन्तरण करने के बाद वि० स० निधि में 1969-70 के दौरान 78 लाख रुपए का लाभ हुआ है (जबिक 1968-69 में 50 लाख रुपए का लाभ हुआ था)।

लेखे और अन्य विषय

आय और स्यय

42. इस खण्ड के अन्तर्गत भा० औ० वि० बैंक की सामान्य निधि के लेखों का उल्लेख किया गया है। 1969-70 के दौरान निधि की कुल आय 1968-69 के 10.4 करोड़ रुपयों से बढ़कर 11.8 करोड़ रुपए हो गई और कुल ब्यय पिछले वर्ष के 6.8 करोड़ रुपयों से बढ़कर 7.9 करोड़ रुपए हो गया तथा लाभ की राणि उक्त वर्ष के 3.6 करोड़ रुपयों से बढ़कर 3.9 करोड़ रुपए हो गयी। लाभ में से 3.1 करोड़ रुपयों (1968-69 में 2.8 करोड़ रुपए) की राणि रक्षित निधि में अन्तरित कर दी गई जिससे 30 जून 1970 को निधि की राणि बढ़कर 12.0 करोड़ रुपए हो गई। 80 लाख रुपए की शेष राणि (1968-69 में 75 लाख रुपए) भी रिजर्ब बैंक ऑफ़ इंडिया अन्तरित कर दी गयी जिससे लाभांग की दर 3 रित्र प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत हो गई।

†निवेश की रक्षित निधि की लगभग 42 लाख रूपयों की उस राशि को छोड़कर जो निवेशों की बिक्री का लाभ दर्शातो है।

^{*}भा० औ० वि० बैंक की सामान्य निधि से अलग यह निधि भा० औ० वि० बैंक अधिनियम की धारा 14 की णतों के अनुसार मार्च 1965 में बनाई गई थी ताकि केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विशेष रूप से योग्य ऐसी परियोजनाओं के लिए सहायता दी जा सके जिनके लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से उनके सामान्य कारोबार के दौरान आवश्यक सहायता मिलना संभव नहो।

किसीय साधन

43. 1969-70 और 1968-69 के दौरान भा० औ० वि० बैंक की निधियों* के मुख्य साधन नीचे लिखे अनुसार थे :--(करोड़ रुपयों में)

					·			1969-70	1968-69
, ,	नुकता पूंजी और रक्षित निधियों में वृद्धि लए गए ऋण :	<u>.</u>		•	•			3.5	2.8
()	(क) भारत सरकार से		•						25.0
	(ख) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से		•		•		•	20.0	0.2
(iii) f	नेवेशों की बिकीं		•					1.7	
(iv) 3	सहायता का भुगतान								
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							14.0	14.4
	(ख) नियति ऋणों का पुनर्वित्त		•	•		•		1.4	0.3
	(ग) पुनर्भाजन					•	•	8.0	5.5
	(घ) प्रत्यक्षऋण		•	•	•		•	3.6	1.4
						जोड़		52.2	49.6

^{*}ये आंकडे विकास सहायता निधि को छोड़कर हैं।

(i) सेयर पूंजी

44. 1969-70 के दौरान बैंक की चुकता पूंजी ज्यों की त्यों अर्थात् 20 करोड़ रुपए बनी रही।

(ii) भारत सरकार से लिए गए ऋण

45. बजट सम्बन्धी आबंटन की कोई व्यवस्था 1969-70 के वजट में नहीं की गई थी। फलस्वरूप, इस वर्ष सरकार से नतो सामान्य निधि और न ही विकास सहायता निधि के लिए कोई ऋण लिया गया। भा० औ० वि० बैंक ने सरकार को 0.7 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जो 1964-65 में लिए गए 8.99 करोड़ रुपयों के ऋण की पहली किस्त थी। 30 जून 1970 को सरकार से लिए गए ऋणों की वकाया राणि (विकास सहायता निधि में जमा की जाने वाली 27.3 करोड़ रुपयों की राणि को छोड़कर) 149.4 करोड़ रुपए थी।

(iii) रिजर्ब बैंक ऑफ़ इंडिया से लिए गए ऋण

46. सामान्य कारोबार (अर्थात् राज्य वित्त निगमों के बाण्डों और शेयरों में अभिदान करने के सियाय) के लिए भा० औ० वि० बैंक ने रिज़र्य वैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं) निधि से 20 करोड़ रुपयों की राशि उधार ली। इस वर्ष राज्य वित्त निगमों द्वारा जारी किए गए बाण्डों या शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए भा० औ० वि० बैंक को रिज़र्य बैंक से कोई ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनके बाण्ड बाजार में सफलतापूर्वक बिक गए और उनके लिए भा० औ० वि० बैंक की सहायता की आवश्यकता नहीं थी तथा इस वर्ष उक्त निगमों ने कोई सार्वजनिक शेयर जारी नहीं किया। जून 1970 के अन्त में इस निधि से लिए गए ऋणों की राशि 26.3 करोड़ रुपए थी और इसी तारीख को निधि में 68.7 करोड़ रुपयों की राशि शेष थी, जिसका उपयोग नहीं किया गया।

लेखा परीक्षक

47. बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कं० ने की जिसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा भा० औ० वि० बैंक अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन की गई थी।

निवेशक बोर्ड

- 48. भा० औ० वि० बैंक का निदेशक बोर्ड रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड जैसा ही है। बैंक के अध्यक्ष श्री एल० के० भा० संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किए जाने पर 4 मई 1970 को अपने पद-भार से मुक्त हो गए और श्री वी० एन० आड।रकर जो रिजर्व बैंक के उप गवर्नर तथा भा० औ० वि० बैंक के उपाध्यक्ष थे, उसी तारीख से रिजर्व बैंक के गवर्नर और भा० औ० वि० बैंक के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए और वे इन पदों पर अपनी निवत्ति की तारीख 15 जून, 1970 तक बने रहे। श्री एस० जगन्नाथन, जिन्हें 16 जून, 1970 से 5 वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया, उसी तारीख से भा० औ० वि० बैंक के अध्यक्ष हो गए हैं। बोर्ड सर्वश्री एल० के० झा और बी० एन० आडारकर द्वारा बैंक के लिए की गई उनकी अमूल्य सेवाओं के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है।
- 49. वैंक के उपाध्यक्ष श्री ए० वक्सी भारत सरकार के वित्त मन्द्रालय में बैंकिंग विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने पर 8 सितम्बर 1969 को अपने पद-भार से मुक्त हो गए और उसी तारीख से श्री बी० एन० आडारकर बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। बोर्ड श्री बक्सी द्वारा बैंक के लिए की गई उनकी अमुल्य सेवाओं के लिए उनका हार्दिक आभारी है। 25 अक्तूबर

1969 से भारत सरकार ने रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) के अधीन श्री बक्सी को श्री आई० जी% पटेल के स्थान पर रिज़र्व बैंक का निदेशक नामित किया।

- 50. 4 मई 1970 को भा० औ० वि० बैंक के अध्यक्ष के रूप में श्री आडारकर की नियुक्ति होने के फलस्वरूप श्री आर० के० हजारी को जिन्हें 27 नवम्बर 1969 से वर्षों के लिए रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया था, बैंक का उपाध्यक्ष नामित किया गया।
- 51. श्री जें० जें० अंजारिया 28 फरवरी 1970 को रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में अपनी पदावधि समाप्त होने पर उक्त पद से निवक्त हो गए और 10 अप्रैल 1970 को उनका अकरमात निधन हो गया। दो निदेशक नामतः श्री एन० ए० पाल-खीवाला और प्रो० सी० एन० वकील क्रमणः 14 और 23 जनवरी 1970 को अपने पद की अवधि समाप्त होने पर रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड से निवत्त हो गए और उनके स्थान पर भारत सरकार ने 28 फ़रवरी 1970 से डा० पी० बी० गजेन्द्र-गडकर और डा० ए० एम० खुसरो को रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए और परिणामस्वरूप भा० औ० वि० बैंक के निदेशक बोर्ड के लिए नामित किया। बोर्ड स्वर्गीय श्री जें० जें० अंजारिया, श्री एन० ए० पालखीवाला और प्रो० सी० एन० वक्तील बारा की गई सेवाओं के लिए उनका आभारी है।

बोर्ड और कार्यकारिणी समिति

52. इस वर्ष निदेशक बोर्ड की 7 बैठकें अर्थत् वो बम्बई में और एक-एक मद्रास, जयपुर कलकत्ता, पटना और नई दिल्ली में हुई। कार्यकारिणी समिति (जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आठ अन्य निदेशक हैं) की बारह बैठकें हुईं। इनमें से एक-एक बैठक मद्रास, जयपुर, कलकत्ता, पटना और नई दिल्ली में और शेष बैठकें बम्बई में हुईं।

आंतरिक संगठन

53. कुछ दिन पहले तक भा० औ० वि० बैंक बम्बई में स्थित अपने प्रधान और एकमात कार्यालय से अपना कार्य कर रहा था। बैंक ने इस वर्ष कलकत्ता, मब्रास और नई दिल्ली में अपने प्रादेशिक कार्यालय खोले हैं ताकि कार्य का विकेन्द्रीकरण करने में सुविधा हो और उद्योग की वित्तीय और सम्बद्ध समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके। इन कार्यालयों के खोले जाने की तारीखें और उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नीचे दिए गए हैं।

प्रादेशिक कार्यालय	खोले जाने की तारीख	कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र
कलकत्ता	8 दिसम्बर 1969	असम, बिहार, नागा लैण्ड, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल के राज्य। मणिपुर, त्निपुरा और अन्दमान तथा निकोबार के संघ शासित क्षेत्न।
मद्रास	16 फरवरी 1970	आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और तमिलनाडु के राज्य। पांडिचेरी और लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनीक्षीय के संघ शासित क्षेत्र।
नई दिल्ली	9 मार्च 1970	हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य । चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्न ।

54. केन्द्रीय कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों के बीच कार्य का विभाजन व्यापक रूप से इस प्रकार होगा कि अखिल भारतीय महत्व की बड़ी परियोजनाओं, बड़ी निर्यात योजनाओं और औद्योगिक विकास की अखिल भारतीय समस्याओं पर केन्द्रीय कार्यालय ध्यान देगा जब कि अन्य परियोजनाएं और नितान्त क्षेत्रीय समस्याएं प्रमुख रूप से प्रादेशिक कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में आएंगी। बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी प्रावेशिक कार्यालयों की सलाह और टिप्पणीयां सभी उचित मौकों पर ली जाएंगी। प्रादेशिक कार्यालय मैंनेजरों के अधीन हैं। उन्हें 20 लाख रुपयों तक की प्रत्यक्ष सहायता तथा पुनर्वित्त और 5 लाख रुपयों तक की पुनर्भाजन सहायता मंजूर करने की शक्तियां दी गई हैं। इन कार्यालयों को चलाने के लिए पर्याप्त तकनीकी और अन्य कर्मचारी रखे गए हैं। इसके अलावा बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय में एक अलग अनुभाग का गठन किया गया है जो उपर्युक्त सीमाओं के अधीन पुनर्वित्त और पुनर्भाजन सहायता के लिए पश्चिमी क्षेत्र* से प्राप्त प्रार्थनाओं पर विचार करेगा भाव औव विव बैंक ने यह निश्चय किया है कि प्रादेशिक कार्यालयों की सहायता और मार्ग दर्शन के लिए प्रारेशिक सामितियों का गठन किया जा चुका है।

55. श्री पी० के० दास गुप्ता जो सितम्बर 1967 से भा० औ० वि० बैंक के जनरल मैंनेजर के पद पर आसीन थे, 4 अप्रैल 1970 से निवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चले गए। श्री दास गुप्ता ने बैंक की जो सेवा की है, बोर्ड उसके लिए उनका आभारी है। श्री एस० एस० एन० सिम्हा ने रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी के रूप में अपनी प्रतिनियुक्ति की अविधि समाप्त होने पर 4 अप्रैल 1970 को भा० औ० वि० बैंक के जनरल मैंनेजर के पद का कार्यभार ग्रहण किया। वे इसके पहले 10 जनवरी 1966 और 16 सितम्बर 1967 के बीच बैंक के जनरल मैंनेजर रह चुके थे।

^{*}इसमें गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य और गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत शामिल हैं।

तदर्थं सलाहकार समितियां

56. पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी भा० औ० वि० बैंक विशेष परियोजनाओं के सम्बन्ध में सलाह प्राप्त करने के लिए तकनीकी सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं की सेवाएं बराबर लेता रहा । इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर तदर्थ सलाहकार सिमितियां गठित की गईं। इस वर्ष इन सिमितियों की कुल मिलाकर आठ बैठकें हुईं। निदेशक बोर्ड सलाहकार और विशेषज्ञों द्वारा बैंक को दी गई बहुमूल्य सहायता तथा सलाह के लिए उनका आभारी है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य का पर्यवेक्षण

57. भा० औ० वि० बैंक जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत का धारक है, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अनुसार भा० औ० वित्त निगम के कार्य का पर्यवेक्षण करता रहा। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 34 (I) के अनुसार भा० औ० वि० बैंक ने नई दिल्ली की वाकर चांडीओक एण्ड कम्पनी को निगम का लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 10 (1) (कक) के अधीन 27 अप्रैल 1970 से भा० औ० वि० बैंक के जनरल मैनेजर श्री एस० एल० एन० सिम्हा को श्री पी० के० दास गुप्ता के स्थान पर भा० औ० वि० निगम के बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित किया गया है। 1969-70 में सर्वश्री चरत राम, जी० रामानुजम और आर० एन० भागव भा० औ० वित्त निगम के निदेशक वोर्ड में भा० औ० वि० वैंक के नामितों के रूप में वर्षभर कार्य करते रहे।

उपसंहार

58, अपने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में भा० औ० वि० बैंक ने अन्य आवधिक ऋणदास्री संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करने के अलावा सीमेंट, उर्वरकों और मूल रसायन जैसे उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का वित्तपोषण करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। इनमें कुछ कार्यों का स्वरूप तो परम्परागत था और कुछ कार्य बैंक को शीर्षस्थ संस्था होने के नाते करने पड़े। अब इस बैंक के जिम्मे जो कार्य है और जिन पर उसे भविष्य में विशेष ध्यान देना होगा वे अपेक्षाकृत अधिक जटिल और चनौतीपर्ण हैं। 'हरित' क्रांति में हुई प्रगति, मन्दी के बाद औद्योगिक उत्पादन में हुए सुधार और चौथी योजना का आरम्भ होने के कारण अर्थव्यवस्था ऐसे चरण में पहुंच गई है जहां से वह अधिक ठोस विकास कर सकती है। इसके साथ ही, विभिन्न प्रदेशों के संतुलित औद्योगिक विकास, छोटे और मसौले उद्यमकर्ताओं के नए वर्ग के विकास, निर्यात क्षेत्र के प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के नए साधन और कियाविधियां खोजने की समस्याओं का यह तकाजा है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए। देश के प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के संगठन और वित्त, दोनों ही साधनों में अधिक व्यापकता आ गई है और यह राष्ट्रीयकरण इन लक्ष्यों की प्राप्त करने की ओर उठाया गया एक बड़ा कदम है। सरकारी क्षेत्र की आवधिक ऋण देनेवासी शीर्षस्थ संस्था होने के नाते भा० औ० वि० बैंक को इन उद्देश्यों के अनुरूप ही अपनी नीतियां और कार्य निर्धारित करने हैं। बैंक अब तक अनेक ऐसे कदम उठा चुका है जिनके फलस्वरूप वह इस नई चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कहीं अधिक समर्थ बन गया है। इस बात की चुपचाप प्रतीक्षा करने के बजाए कि बैंक के पास वित्तीय सहायता के लिए नए आवेदन आएं, अब वह स्वयं कम विकसित क्षेत्रों में निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों का पता लगाने के उपाय कर रहा है। उसने प्रादेशिक कार्यालय खोले हैं और रिजार्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के साथ संयुक्त रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों की औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है ताकि वह इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में सिकिय भाग ले सके। बैंक ने सहायता सम्बन्धी अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों योजनाओं में इस प्रकार संशोधन किया है कि निर्धारित पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं को अपेक्षाकृत आसान मर्तो पर वित्तीय सहायता दी जा सके। उद्यमकर्ताओं के उभरते हुए नए वर्ग को तकनीकी मार्गदर्गन प्रवान करने के लिए बैंक ने अधिक संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की भरती करके अपने आपको सक्षम बना लिया है। कम विकसित प्रदेशों का औद्योगिक विकास एक दूष्कर कार्य है जिसे पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रदेशों के भीतर और बाहर कार्य करनेवाली कई वित्तीय और विकासात्मक एजेंसियां सणक्त और संगठित प्रयत्न करें।

अनुबन्ध I 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग (करोड रुपयों में)

						(कराड़ रुपया म)
	भा०औ० वि०बैंक	भा० औ० वि० निगम	भा०औ० ऋरु०नि० निगम	राज्य विस निगम	जोड़	ओड़ (इनमें संस्थाओं का परस्पर आवान-प्रदान शामिल नहीं है)
1	2	3	4	5	6	7
			. निधियों के	स्रो त		
1. चुकता पूंजी में वृद्धि		_		0.20	0.20	0,20
 रिक्षत निधियों में वृद्धि . 	2.89	1.46	1.26	1.02	6.63	6,63
 भारत में निम्नलिखित से लिए गए (सकल) उधार 						

1	2	3	4	5	6	7
 (i) सरकार .	<u>-</u>	-	- 	0.68	0.68	0.68
(ii) रिजर्व बैंक आफ				0.00	0.08	
इण्डिया .	_	2.31		5.07	7.38	7.3
(iii) भा०औ०वि०बैंक		_	1.80	5.66 *	7.46	
(iv) बैंक			_	0.51	0.51	0.5
(v) अन्य <mark>'</mark>	_			0.11	0.11	0.1
l. बांडों/डिबेंचरों के रूप में प्राप्त किए गए उधार .	_	5.50	5.00	11.51	22.01	21.5
ं विदेशी मुद्रामें लिए गए उधार						
(i) उपल ब्ध ऋ ण की कुल सीमा	_	(15.35)	(5.12)		(20.47)	
(ii) उपयोग की गयी ृं राणि	<u> </u>	1.87	11.79		13.66	13.6
. स्वीकार की गई जमा ्राशियां	_	_		2.67	2.67	2.6
. निम्नलिखित में किए गए निवेशों की बिक्री <u>†</u>						
(i) सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियां	_	<u> </u>	0.12	0.10	0.22	0.2
ं(ii) ग्रेयर डिबेंचर आदि ॄैं(इनमें हामीदारी ग्रामिल है)	2 05	0.29	1 55	0 44	4.33	4.3
. उधारकत्तीओं द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी :		0,25	1,00	, 0, 11		4,0
(i) रुपयाऋण	25.12	8,58	3.87	10.78	48.35	45.1
(ii) विदेशी चलमुद्रा ऋण	<u></u>	1.85	8.06	_	9,91	9.9
. गारंटियों के सम्बन्ध में						
वसूली		0.03		0.09	0.12	0.13
. अन्य **	34.84	11.98	5,42	6,60	58.84	58.8
<u></u>						

^{*}ये आंकड़े पुनर्वित्त सहायता के हैं।

^{**}इन आंकड़ों में नकदी और दूसरे चल-साधन शामिल हैं।

अनुबन्ध I — जारी 1969-70 (अप्रैल-मार्च) में आवधिक वित्तपोषण करने वाली संस्थाओं की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

	भा०औ० वि०वैक	भा०औं० वि० निगम	भा० औ० ऋ० नि० निगम	राज्य वित्त निगम	जोड़	जोड़ (इनमें संस्थाओं का परस्पर आदान-प्रदान णामिल नहीं है)
	ख. नि	धियों के उपयोग	π			
 निम्नलिखित रूप में सहायता का वितरण 						
(i) ऋण:						
(क) रुपयाऋण .	49.00	14.39	4.26	21.54	89.19	83.53
(खा) विदेशी चलमुद्राऋण .		1.87	11.79		13.66	13.66
(ii) औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों,				•		
डिबेंचरों, आदि में अभिदान	1.76	1.08	3.71	0,34	6.89	6.89
(iii) वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/						
बांडों में अभिदान	2.30				2.30	
(iv) गारंटियां		0.16		0.45	0.61	0.61
2 सरकारी और न्यासी प्रतिभूतियों में						
निवेश		3.31		0.15	3.46	3.46
3. ऋणों की अदायगी (भारत में)						
(i) सरकारी		1,61	0.70	0.76	3.07	3.07
(ii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया .				6,19	6.19	6.19
(iii) भां०औं वि०वैंक			_	3.18*	3.18	 ,
(iv) बैंक				0.48	0.48	0.48
(v) अन्य				• •		
4. बांड़ों/डिबेंचरों का विमोचन .				0.03	0.03	0.03
5. विदेशी चलमुद्रा में ऋणों का भुग-						
तान		2.06	9.04		11.10	11.10
 जमा राशियों का भुगतान 				2.58	2.58	2.58
7. अन्य**	11.84	9.39	9.37	9.74	40.34	40.34
जोड़ .	64.90	33.87	38.87	45.44	183.08	171.94

^{*} ये आंकड़े पुर्नावित्त सहायता के हैं ।

[😬] ये आंकड़े नगण्य हैं ।

^{**} इन आंकड़ों में नकदी और दूसरे चल-साधन शामिल हैं। M59 G1/71—4

अनुबन्ध उन औद्योगिक परियोजनाओं का स्योरा जिनके लिए 1969-70 में भा० औ० वि० वैंक द्वारा

	·	विस	पोषण के	साधन	
, ऋम कम्पनी का नाम संख्या	परियोजना की लागत	शेयर पूंजी		ऋण** भादि	आस्थगति अदायगी
राज्य।	का लागत	सामान्य	अधिमान	माद	अदायगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पानीपत फूड्स लि॰	32.0	13.0	6.5	5 . 8	6.8
2. ड्रिलमैंक लि॰	34.0	18.0	4.0	12.0	
 इनचैक टायसँ लि० 	746.5	46.8	_	501.7	198.0
-				(367.2)	
4. इन्टरनेशनल ट्रेक्टर कंपनी आफ इंडिया लि०	410.0	82.3	70.0	257.7	_
r				(107.7)	
5. अजन्ता टेक्सटाइल्स लि०	98.7	32.5	12.5	43.5	10.2
 आर० बी० रोड्डा एण्ड कंपनी लि० 	106.3	19.5		79. '	7. (
				(3.2)	
7. सिपोरेक्स इंडिया लि०	240.0	90.0	30.0	120.0	
 नागपाल अम्बाडी पेट्रोकेम रिफायनिंग लि० 	520.0	200.0	50,0	270.0	
9. कनाड़ियां-हेकाक सेन्डरसन लि०	101.0	35.8	14.2	51.0	
 इंडिया फायर बिक्स एण्ड इन्सूलेशन कंपनी लि०** 	425.8	95.2111	30.011		_
.1. केमीकस्स एण्ड प्लास्टिक्स इंडिया लि०	101.7		4 5.0**	* 56.0	
,				(31.5)	
2. इंडिया मीटर्स लि०**	123.0	60.0	15.0	48.0	_
 एक्सेलिसयर प्लाट्स कार्पोरेशन लि० 	57.0	25.0	7.0	20.0	5.0
4. एसोसिएटेड ग्लास इंडस्ट्रीज लि॰	358.4	90.0	30.0	142.5	98,
15. क्योरवेल (इंडिया) लि॰	72,0	27.5	9.0	28.2	7.
16. बिनोद मिस्स फैं० लि॰	60.0‡			43.0	
7. जुआरी एगरो केमीकल्स लि०	5655.0	1242.7	412.5	3999.7	_
18. शर्मा पिस्टन्स एन्ड रिंग्स लि०	187.2	48.2	16.2	116.0	6.
 टेक्सटाइल कार्पोरेशन आफ मराठवाड़ा लि० 	383.0	120.0	30.0	233.0	_
2.€. महिन्द्रा यूजीन स्टील कं० लि०	1050.0	317.5	5 0.0	643.1	39.
21. टाटा योडोगवा लि०	708.1	250.0	<u></u>	458, 1 (3, 1)	
22. श्री सिन्थेटिक्स लि०	735.0	243.7	81.3	(3.1) 410.0	_
उप जोड़	12204.7	3097 · 7	913.2	7839·6 (512·7)	378

II (**भ)**---(जारी)

प्रत्यक्ष विलीय सहायता निर्यातों के लिए दी गई सहायता को छोड़कर) मंजूर की गई

(लाखा रुपयों में)

2 से 13	2 से 9		ही गयी 	सहायता		*	परियोजना की लागत में प्रवंतकों और सहभागियों का अंग्रदान		
का प्रतिगत	का प्रतिमत	गारंटी*	10,11 और 12का	दिवारी 	हार्म सामान्य	 ऋण*	7 और 8 काजोड़*	सहभागी	
			जोड़*	जावनाग <u>्</u> शेयर*	शेयर*	<i>ন</i> হুণ	मन जाङ		।नदशक आदि*
(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)
15.6	20.3		5.0		5.0		6.5		6, 5
14.7	20.6		5.0	1.2	3.8		7.0	1 4 11-44	7.0
6.0	5 49.2	241.	45.0			45,0	367.2		367.2
(6.7)	5)	(241.5	(50.0)	(5.0)	()	(45.0)			
3.7	33.6	· 	15.0			15.0	137.7	30.0	107.7
(24.7)			(101.5)		(10.0)	(91.5)			
22.8	15.8		22.5	2,5	·	20.0	15.6	-	15.6
(27.9)			(27.5)	(3.7)	(3.8)	(20.0)			
56.4	36.9		` 60. ó††		. ,	`60. ot	39.2		39.2
					•		(16.5)		(16.5)
28.1	15.6		67.5	5.0	37.5	25.0	37.5	12.5	25.0
8.7	14.8		45.5	10.5	10.0	25. 🖲	77. ●		77.0
- 8.9	19.8		9.0	3.8	5.2		20.0		20.0
15.8	13.9		67.5			67.5	59.3	14.7	44.6
(24.0)			(102.5)			(102.5)			
9.9	56.9		10.0	10.0	_	`	57.5	15.0	42.5
(44.5)			(45.0)	(20.0)		(25.0)			
6.1	14.1		7.5	` <u>,</u>	·	7.5	17.4	2.0	15.4
(14.6)			(17.9)	(2.5)	(7.9)	(7.5)			20. #
31.6	21.0		18.0	3.0	15.0	\	12.0	5 .0	7.0
36.6	44,2		131.0	22.5	27.5	81.0	158.4	98.4	60.0
32.2	38.6	8.4	23.2	3.0	7.0	13.2	27.8		7.0
100.0	10.0	_	60.0	_	17.0*	43.0	6.0	_	6.0
5.2	12.8	_	292.4	242.4	50.0		726.0	525.0	
1							(22.5)		(22.5)
10.1	16.8		19.0	_	7.0*	12.0	31.5	11.5	20.0
(13.9)			(26.0)		(7.0)	(19.0)			20.0
.79.1	20.9		303.0£	30.0	40.0£	233.0£	80.0		80.0
4.1	14.4	_	43.0		_	43.0	151.0	65.5	85.5
(12.9)			(135,1)			(135.1)		00.0	00.0
2.8	22.9		20.0	—	_	20.0	162,1	66.0	96.1
(36.9)			(261.0)		(21,0)	(240.0)		00.0	30.1
10.2	16.6		77.5£	7.5£	15.0£†	55.0£	122.0	60.0	62.0
11.0	19.1		1346.7 24	341.5	240.0	765.2	2318.7	926.4	1392.3
(15.3)		.9.9)	(1863.7)(24	(360.2)	(282.7)	(1220.8)	(39.0)		(39.0)

्रभनुबन्ध उम औद्योगिक परियोजनाओं का ब्योरा जिनके लिए 1969-70 में भा० औ० वि० बेक द्वारा

				साधन		
क्रम कम्पनी संख्या	कम्पनी कानाम	परियोजना की सम्बद्ध	परियोजना शेयर पूंजी की लागत ———————		· ऋण**	आस्थगित
सक्या		મા ભાગત	सामान्य	अधिमान	· ऋणः आदि	आस्थागत अदायगी
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वामित्व शेयर	रों के लिए अभिदान					
1. पीलियोले	फ़िन्स इंडस्ट्रीज लि०		180.0			
2. इंटरनेशन	ल ट्रेक्टर कंपनी आफ इंडिया लि०		63.0	74.7		,
3. इंडिया मी	टर्स लि०		22,5			
*	क्रुल जोड़	12204 7	3363 2	987.9	7839 6 (512·7)	378.9

नोट : ये आंकड़े सहायता मंजूर करते समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं । कुछ परियोजनाओं के संबंध में प्रवर्तकों निदेशकों आदि के अंग्रदान के आँकड़े उस जानकारी पर आधारित हैं जो सम्बन्धित कंपनियों के विवरण-पत्नों में उपलब्ध हैं ।

- * इन आंकड़ों में आंतरिक साधन, प्रोद्भूत नगदी राशियां, आदि शामिल हैं । मुख्य आंकड़ों में शामिल प्रवर्तकों और सहभागियों द्वारा ऋण, जमा आदि के रूप में किया गया अंशदान कोष्ठकों में अलग से दिखाया गया है ।
- ** कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े मुख्य आंकड़ों में शामिल आन्तरिक साधन और प्रोद्भूत नकदी राशियों आदि से सम्बन्धित हैं। *कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल सहायता से सम्बन्धित हैं जिसमें भा० औ^ वि० बैंक द्वारा मंजूर की गई अतिरिक्त सहायता शामिल है।

अनुबन्ध 1969-70 में भा० औ० वि० बेंक द्वारा निर्यात के लिए

निर्यातक का नाम	निर्यात की मदें	आयातक देश	अदायगी की चलमुद्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1. टेक्सटाइल मशीनरी कार्पोरेशन लि० (2 ऋण)	वस्त्र उद्योग की मशीनें	संयुक्त अरब गणराज्य	भारतीय रुपये
2. मशीनरी मेन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लि० (2 ऋण)	-वही-	ँ -वही-	-वही-
3. लक्ष्मी मशीन वर्कस लि० (2 ऋण)	-वही-	-बही-	-वही-
4. हिन्दुस्तान मोटर्स लि॰	बसों और ट्रामों के आधार ढांचे (Chassis) और अतिरिक्त पुर्जे	-बही-	-वही-
 नेशनल मंगीनरी मेन्यूफेक्चरसं लि० 	वस्त्र उद्योग की मशीनें	-वही-	-बही-
 कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि० 	पारेषण लाइन टावर और ए० सी० एस० आर संवाहक	थाईलैंड	अमरीकी डालर
7वही-	पारेषण लाइन टावर	ईरान	-वही-
8. एको इंडिया लि०	इस्पात के शटर और स्केफोल्डिंग सामग्री	संयुक्त अरब गणराज्य	भारतीय रुपये
 हिन्दुस्तान स्टील लि० 	इस्पात की पटरियां	ईरान	अमरीकी डालर
0. जयपुर भेटल्स एण्ड इलेनिट्रकल्स लि० (2 ऋण)	तांबे के संवाहक	-वही-	-वही-
			जो

(लाख रुपयों में)

👡 🎞 (क)—(जारी)

प्रत्यक्ष विसीय सहायता (निर्यांतों के लिए वी गई सहायता को छोड़कर) मंजूर की गई

(लाख रुपयों में) परियोजना की लागत में भा० औ० वि० बैंक द्वारा मंजूर की गयी 2 से 9 2 से 13 प्रवर्तकों और सहभागियों वित्तीय सहायता का का का अंशदान प्रतिशत प्रतिशत हामीदारी 10,11 और गारंटी× प्रवंतक. सहभागी 7 और 8 निदेशक अधिमान का जोड* ऋण× सामान्य 12 朝 आदि* शेयर× शेयर× जोड़× (7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)17.6 17.6 (140.0)(55.2)(195.2)(245.7)7.8 3,2 4.6 11.5 11.5 1383 6 272.3 346.1 249 9 1392 3 926.4 2318 7 765 2 (39.0)(39.0) (1360.8)(352.6)(364.8) (2078.2) (495.6)

ी ये आंकड़े इस मार्त पर मंजूर की गयी कुल सहायता के द्योतक हैं कि कंपनी भा० औ० वि० वैंक से आवश्यक हामीदारी सहायता लेकर अपनी पूजी बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर ले और शेष राणि ऋण के रूप में आहरित कर ले ।

imes imesवित्तीय पुनर्गठन योजना ।

† † † पूंजी निर्माण में पुनर्गठन करने के बाद ।

- ं-प्रत्यक्ष अंशदान के आंकडे ।

£यह रकम उस सीमा तक घटा दी जायगी जिस सीमा तक उसे मंजुर करने के लिए अन्य संस्थाएं सहमत हो जाएं।

- ‡‡आपूर्ति के लिए वित्तपोषण--कंपनी की केवल तात्कालिक आवश्यकता के लिए।
- ***ये आँकड़े अतिरिक्त पूंजी (परिवर्तनीय विकल्प) के हैं।
- ौ प्रत्यक्ष अभिदान के आँकड़े मिलाकर **।**

II (**u**)

मंजूर किए गए प्रत्यक्ष ऋण और गारंटियां

भा० औ० वि० बैंक और वाणिज्य बैं से अपेक्षित कुल सहायता	कों	मंजूर की गर्य सहायता में भा वि० बैंक व		
पोतलदानोत्तर ऋण	गारंटी	पोतलदानोत्तर ऋण	गारंटी	
(5)	(6)	(7)	(8)	
178.35		126.00 (70)		
233,88		165.00 (70%)		
254.58		179.00 (70%)		
34.54		17.27 (50%)		
55.07	_	39.00 (70%)		
25.59		13.00 (50%)		
25.53		12.77 (50%)		
97.00		58.00 (60%)		
641.00	l-words	449.00 (70%)	_	
124,88	_	62.50 (50%)		
1670,42	_	1121.54		

⁽²⁾ कोष्ठकों में दिये गये प्रतिशत भा० औ०वि० बैंक की सहभागिता के अंश के द्योतक है।

अनुबन्धः ≄ भा० औ० वि० वैंक द्वारा मंजूर और वितरित की गई

			1969-70		·	
		मंजूर	 की गयी वित्तीय	सहायता		 वितरण
उद्योग	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित	पुन भाँ जन	जोड़	
		1				
1	2	3	4	5	6	7
्र वित्तीय सहायता (निर्यातों के लिए दी गयी सहायता को छोड़कर)						
1. कोयला खनन			8.0		8.0	23.
2. पत्थर, खदान, मिट्टी और रेत की खानें			2.0		2.0	_
3. धातु खनन						13.
 खाद्य पदार्थ निर्माण (पेय उद्योगों के सिवाय) 						
(क) चीनी			61.0		61,0	9.
(ख) अन्य	 ·	5.0	123.2		128.2	40.
5. कपड़ों का निर्माण	•					
(क) सूती कपड़े	356.0	89.5	143.2	_	588.7	294.
(ख) अन्य			39.3		39,3	185.
 लकड़ी और कार्क का निर्माण (फर्नीचर के सिवाय) 			1.9		1.9	0.
7. फर्नीचर और जुड़नारों का निर्माण		·	0.4	_	0.4	1.
8. कागज और कागज की चीजों का						
निर्माण	_		28.8	_	28.8	27.
 मुद्रण, प्रकाशन गौर संबद्ध उद्योग 			29.4		29.4	8.
 चमड़े तथा उससे बनी डौर फ़र की चीजों का निर्माण, जूते और पहनने के अन्य परिधानों सिवाय 	_		1.5		1.5	
ासवाय 1. चमड़े के बने हुए जूते और पहनने योग्य परिधान			9.6		. 9.6	. -
पारधान 12. रब्रष्ट्रकी चीजों का निर्माण	45.0 (241.5)	35.4	—	80.4 (241.5)	28. 39

र सहायता का	उद्योगवार वर्गी	करण					(लाख रुप	यों में)
1	968-69				भा०औ० वि०वैंक की स्थापनासे - जून 1970 के अन्त तक			
मंजूर क	ो गई वित्तीय र	महायता			वितरण			
ऋण	हामीदारी	पुनवित्त	पुनर्भाजन	जोड़	14(12)	मंजूर की गई कुल सहायता	सभी उद्योगों केप्लिए स्वीकृत कुल राशि से मंजूर की गई सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण *
8	9	10	11	12	13	14	15	16
		15.8		15.8		91.6	0.3	231.3
		8,1		8.1	7.5	34.4	0.3	31.
		16.4		16.4		50.9	0.2	48.1
	<u> </u>	13.0		13.0	47.6	295.3	1.0	244.5
		81.7		81.7	√ 83,5	4 346.9	1.2	254.0
45.0	10.0	320.4		375.4	193.8	2943.5	10.1	2737.3
150.0	~-	93.6		243.6	103.2	979.5	3.4	861.7
		1.5		1.5	1.3	19.4	0.1	52.4
		2.3		2.3		7.0		5.9
580,0	1.9	39.4		621.3	343.3	1442.3	5.0	886.9
		20.6		20.6	14.8	95.2	0.3	66.8
	-~	4.2	<u></u>	4.2	3.5	2.1	• •	0.6
22.0	11.5			33.5		47.3	0.2	31,9
		17.7	 -	17.7	40.5	167.9 (241.5)	0.6	117.8

अनुबन्ध भा० औ० वि० वैक द्वारा मंजूर और वितरित की गई

			196) 70	,	
	, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	मंजूर	की गई विसीय	। सहायता		वितरण
उद्योग	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित	पुनभजिन	—— जोड़	वितरण

1	2	3	4	5	6	7
 रसायन और रसायनिक चीजों का निर्माण 						
(क) मूल औद्योगिक रसायन उर्वरकों के						
सिवाय	g-4 pm	27,6	178.9		206.5	463.5
(ख) उर्वरक	~-	292,5	31.2		323.7	170.7
(ग) (खाद्य तेलों को छोड़कर) वनस्पति						
और जानवरों के तेल और चरबी			1.8	~~	1.8	3.9
(घ) कृत्रिम रेशों का निर्माण	55.0	22.5	10.5		88.0	5.9
(ङ) रंगों, वार्निशों और लैकर का निर्माण			34.0	_	34.0	2.8
(च) विविध रासायनिक चीजों का निर्माण	13.2	10.0	66.8		90.0	168.5
	(8.4)				(8.4)	(8.4)
 पेट्रोलियम और कोयले की चीजों का निर्माण 	25.0	20.5			45.5	4.3
 अधात्विक खनिज पदार्थों का निर्माण, पेट्रोलियम और कोयले की चीजों के सिवाय 				,		
(क) इमारती मिट्टी की चीजों का निर्माण	67.5		3.0		70.5	2.1
्ख) कांच और कांच को चीजों का निर्माण	81.0	50.0	49.8		180.8	10.8
्र (ग) मृत्तिका भाण्ड, चीनी मिट्टी और						
मिटटी के वर्तन (सिरेमिक्स)			27.8		27.8	28.3
(घ) सीमेंट	-		_			106.0
(इ.) अक्की के पाट और अपघर्षी			0.3	Production 1	0.3	_
(च) एंस्बेस्टस	~-					1.6
(छ) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजों	25.0	42.5	7.8		75.3	39.3
;. मूल धातुओं के उद्योग						
(क) लोहे और इस्पात के मूलोद्योग	63.0		17.5		80.5	256.6
(ख) अलोह धातुओं के मूलीचोग			يحنصو			75.4
. धातुओं की बनी हुई चीजों का निर्माण, मणीनों और परिवहन उपस्कर के सिवाय			69.6		69.6	38.8
•		.—	00.0			50.0
. मशीनों का निर्माण, बिजली की मशीनों	27.0	37.8	81.4	2407.5@	2553.7	2262.0
के सिवायं	47.0	37.0	01.4	2407.300	2000.7	##V#, U

PART 111—SEC. 4]

M59GI/71-5

nt-(लाख रुपयों में) विलीय सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण---जारी भा० और विश्वक की स्थापना से 1968-69 जुन 1970 के अन्त सक मंजूर की गई विसीय सहायता बितरण सभी उद्योगों मंजूर की कुल गई कुल के लिए स्वीकृत हामीदारी पुनवित्त पूनभजिन जोड वितरण* 雅可 कुल राशि सहायता से मंजूर की गई। सहायता का प्रतिशत 8 9 10 11 12 13 14 15 16 200.0 2801,3 100.0 25.0 75.0 200.0 2576,6 (1081.4)(1081.4)15.0 9.0 3.3 27.3 247.3 3874.0 13.3 3591.7 (1085.0)(573.1)26.1 26.1 20,1 62,4 0,2 51.2 17,2 17,2 1.4 314,3 1.1 217.4 2.8 2.3 2.8 100.8 66.8 66.0 66.0 88,8 893.9 3,1 880.6 (8.4)(8.4)45.5 0.1 34.3 7,7 7.7 6.5 132.1 0.5 61.1 24.9 24.9 23.3 276.3 0.9 101.1 30,4 30.4 34.2 93.0 0.3 81.2 190.0 190.0 217.0 1341.0 4.6 1163.9 (248.5)(248.5)0.3 4.0 3.5 3.5 2.0 27.3 0.1 26.6 4.0 4.0 1.4 79.3 0.340.7 69.7 52.2 121.9 211.0 1901.8 6.5 1365.8 150.0 1.0 226.0 245.1 75.0 543.8 1.9 505.9 39.4 39.4 39.6 334,1 1.1 244.7 316.8 167.2 1549.4 2047.9 1796.5 7735.0 14.5 26.5 6731.5 (1.1)(1,1)(1.1)(1.1)(1.1)

अनुवेर्क्य मा० औ० वि० चैक द्वारा मंजूर और वितरित की गई

			1969-70	•		
		मंजूर क	ो गई विसीय स	ाहायता		- वितरण
उद्योग	ऋण	हामीदारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	
-						
1	2	3	4	5	6	7
 बिजली की मंशीनों, उपकरणों, साधितों 						
और पूर्ति सामग्री का निर्माण	eren i-T		86.1		86.1	77.
•						
). परिवहन उपस्करों का निर्माण			48.8		48.8	39.
. विविध निर्माण से संबंधित उद्योग						
(क) वैज्ञानिक माप और नियंत्रण के वृत्तिक औजारों का निर्माण	_	9.0			9.0	0.
(ख) घड़ियों और दीवार घड़ियों का निर्माण	·			, -		
(ग) प्लास्टिक की ढलवां चीजें			20.6	· —	20.6	6
(ष) शल्य चिकित्साकी पट्टियां आदि			1.0		1.0	
(🕏) सिगरेट के फिल्टर		_			_	
(च) लेखन सामग्रीकी चीजें	-		5,0		5.0	-
(छ) पानी, भाप और विजली के मीटर	7.5	11.5			19.0	
(ज) छत बनाने की सामग्री			0.3		0.3	-
(इन) वाद्ययंत्र	_		 ·			-
(ञा) ऊष्मीय और ध्वनिक इन्सुलेटरों निर्माण			——	—		22
(ट) फोटोग्राफ़ी के और प्राकाशिक (आप्टिकल) उपकरण	programme.		—		_	0
(ठ) पैंक करने की सामग्री	production,		1.8	`	1.8	3
` ′ (डा) अन्यत्र वर्गीकृत न की गई चीजें			19.4		19,4	6

सहायता क	त उद्योगवार व	ार्गीकरण—(ज	गरी)			(लाख रुपयों में)			
	1968-69					भा० औ० वि० बैंक की स्थापना से - जून 1970 के अन्त तक			
	मंजूर की गई	वित्तीय सहाय	ा ता		वितरण	· · ·			
ऋण	हामीदारी	पुर्नावित	पुनर्भाजन	जोड़		मंजूरकी गई कुल सहायता	सभी उद्योगों के लिए स्वीकृत कुल राशि से मंजूर की गई सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण*	
8	9	10	11	12	13	1 4	15	16	
37.0	8.7	84.7		128.4	67.5	1116.8	3.8	1024.3	
		31.8	<u></u>	31.8	29.7	296.5	1.0	332.4	
		11.8	Bergland	11.8	11.1	20.8	0.1	14,4	
						11.0		9.0	
		1.2		1.2	5.9	27.9	0.1	13,3	
 ,				_	_	8.2	• •	7.2	
-				_	_			4.0	
	_	2.1	_	2.1		7.1	• •	~-	
	3.0			3,0	2.9	33.4	0.1	14.3	
_	_				2.0	4.8	• • •	4.5	
		6.0		6.0	4.8	6.0	••	4.8	
·· <u></u> ·	· - ·	24.3		24., 3		25.9	0.1	24.4	
	- -	1.4		1.4	0.2	1.4	• •	1.4	
		8.3	_	8.3	8.7	20,5	0.1	18.1	
	_	1.7		1.7	0.9	21.1	0.1	6.7	

अनुबर्म्ध भा० औ० वि० वैक द्वारा मंजूर और वितरित की गई

उद्योग	1969-70					
	मंजूर की गई वित्तीय सहायता					– वितरण
	ऋण	हामीषारी	पुनर्वित्त	पुनर्भाजन	जोड़	- ।वतरण
1	2	3	4	5	6	7
22. बिजली, गैस, पानी और सफ़ाई सेवाएं, गैस निर्माण और वितरण (औद्योगिक गैस)			<u></u>	*** *		47
23. सेवाएं			н о		T 0	00.0
(क) होटल उद्योग (ख) सड़क परिवहन	_	_	7.2 320.6	<u> </u>	7.2 320.6	28.8 119.0
(ख) सङ्गारपहन (ग) अन्य		_	J20.0	<u></u>	320.6	115.0
- जोड़	765.2 (249.9)	618.4	1574.9	2407.5	5366.0 (249.9)	4620.1 (8.4)
II मध्यावधिक निर्यात ऋणों के लिए पुर्नीवस		 	126.7		126.7	269.6
UI निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष ऋण	1121.5		-		1121.5	291.8 (33.4)
कुल जोड़ ————————————————————————————————————	1886.7 (249.9)	618.4	1701.6	2407.5	6614.2 (249.9)	5181.5 (41.8)

नोट: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ऋणों और आस्थगित अदायगियों/अग्रिम अदायगी गारंटी (निर्यात ऋण) के लिए मंजूर की गई तथा निष्पादित की गई गारंटियों के हैं जिन्हें मुख्य आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

		1968-69				भा० औ० वि० बैंक की स्थाप जून 1970 के अन्त तक		स्थापना से	
	मंजूर की गई विश्लीय सहायता				ુ ષ્	1 <i>७७</i> ० क जन्त	(IM)		
ऋ्ष	हामीदारी	पुनर्विस	पुनर्भाजन	जोड़	बि तरण	मंजूर की गई कुल सहायता	सभी उद्योगों के लिए स्वीकृत कुल राशि से मंजूर की गई सहायता का प्रतिशत	कुल वितरण*	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		5.6		5.6	1.7	8.8	• •	19.2	
_	6.0	62, 5 8. 9		68.5 8.9	54.2 7.2	141.4 329.5	0.5 1.1	133.4 126.2	
		7.2	<u> </u>	7.2	7.2	20.0	0.1	20.0	
16005.5 (1.1		1412.9	1549.4	4800.4 (1.1)	4177.3 (1.1)	29180.4 (2665.8)	100.0	25021.5 (1912.5)	
_	-	730.0	_	730.0	249.3	1028.4		673.0	
654.5				654,5		1776.0		291.8	
(60.1)				(60,1)		(60.1)		(33.4)	
2255.0 (61.2)	237.6	2142.9	1549.4	6184.9 (61.2)	4426.6	31984.8 (2725.9)		25986.3) (1945.9)	

^{*}इन आंकड़ों में भा० औ० वि० बैंक में उद्योग पुनर्वित निगम के मिलाये जाने के पहले उसके द्वारा मंजूर की गई पुनर्वित्त सहायता के संबंध में किये गये वितरण शामिल हैं।

[@]बिजली की मशीनों और परिवहन उपस्कर के निर्माताओं को दी गई सहायता के आंकड़े मिलाकर।

^{..}नगण्य ।

परिशिष्ट I

वंक

30 जून 1970 की पुनर्वित्त और पुनर्भाजन की सुविधाएं पाने के लिए योग्य बेंकों वित्तीय संस्थाओं की सुची

- *1 इलाहाबाद बैंक
- *2. अमेरिकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
- *3. दि आन्ध्र बैंक लि०
- * 4. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
- *5. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- *6. बैंक ऑफ़ इंडिया
- 7. बैंक ऑफ़ कराड़ लि०
- बैंक ऑफ़ मदुरा लि०
- * 9. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
- *10. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि०
- *11. दि बैंक ऑफ टोकियो लि॰
- *12. बैंक नेशनल द पेरिस
- 13. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि॰
- 14. बेलगाम बैंक लि०
- 15. बनारस स्टेट बैंक लि॰
- *16. दि ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
- *17. कनारा वैंक
- 18. कनारा बैंकिंग कार्पोरेशन लि॰
- 19. कैथलिक सीरियन बैंक लि॰
- * 20. सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
- *21. चार्टर्ड वैंक
- * 2.2. धेनाबैंक
- *23. दि ईस्टर्म बैंक लि॰
- *24. फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक
- *25. जनरल बैंक ऑफ़ दि नीदरलैंड्स
- *26. दि हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
- * 27. इंडियन बैंक
- *28. इंडियन ओवरसीज बैंक
- ***29. कर्नाटक बैंक लि०**
- 30. करूर बैंक लि०
- 31. कुष्णराम बलदेव बैंक प्राइवेट लि॰

आन्ध्र राज्य सहकारी बैंक लि०

2. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लि॰

3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि॰

तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लि०

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि॰

32. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि०

- 33. लक्ष्मी कर्माशयल बैंक लि॰
- 34 लक्ष्मी विलास बैंक लि॰
- *35. मर्कन्टाइल बैक लि०
 - 36. मिरज स्टेट बैंक लि॰
- *37. दि मित्सुई बैंक लि॰
- *38. नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक लि०
- *39. नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान
- 40. ने दुनगाड़ी बैंक लि०
- 41. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया लि०
- *42. पंजाब नेशनल बैंक
- 43. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०
- 44 रत्नाकर बैंक लि॰
- 45 सांगली बैंक लि०
- 46. साज्य इंडिया बैंक लि॰ (तिन्नेवेल्ली)
- 47. साउथ इंडियन बैंक लिं०
- *48. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
- *49. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
- *50. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
- *51. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
- *52. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
- *53. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
- *54. स्टेट वैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
- *55. स्टेट मैंक ऑफ़ स्नावणकोर
- * 56. सिंडीकेट बैंक
- 57. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि० (तूत्तुकृडि)
- 58 तंजाऊर पर्मनेन्ट बैंक लि॰
- *59. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
- *60. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
- * 61. युनाइटेड कर्माशयस बैंक
- 62. युनाइटेड वेस्टर्न बेंक लि०
- 63. विजया बैंक लि०
- 64. वैश्य बैंक लि॰

राज्य सहकारी बैंक

- मैसूर राज्य सहकारी शिखर बैंक लि॰
- 7. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लि०
- 8. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०
- 9. पश्चिम बंगाल प्रान्तीय सहकारी बैंक लि॰

रा∮य विस्त निगम

- 1. आन्ध्रप्रदेश राज्य वित्त निगम
- 2. असम बित्त निगम
- 3. बिहार राज्य विस निगम

- 4. दिल्ली वित्त निगम
- 5. गुजरात राज्य बित्त निगम
- हरियाणा वित्त निगम
- *ये बैंक मध्याविध निर्यात ऋण पर पुर्निवत्त प्राप्त करने और निर्यात वित्त की सहभागिता योजना के अधीन भा० औ**० वि०** बैंक के साथ सहभागिता करने के योग्य हैं।

- 🥍 हिमाचल प्रदेश वित्त निगम
- 8. जम्मू और काश्मीर राज्य विता निगम
- 9. केरल वित्त निगम
- 10. मध्य प्रदेश विस्त निगम
- 11. तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि०
- 12. महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम

- 13. मैसूर राज्य वित्त निगम
- 14. उड़ीसा राज्य वित्त निगम
- 15. पंजाब वित्त निगम
- 16. राजस्थान वित्त निगम
- उत्तर प्रदेश वित्त निगम
- 18. पश्चिम बंगाल वित्त निगम

अन्य संस्थाएं

भारतीय औद्योगिक विस निगम

2. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि०

परिशिष्ट II

30 जून 1970 को धुनर्वित्त सुविधाएं पाने के लिए योग्य निर्यात की जानेवाली मदों की सूची

क पूंजीगत माल

- (खांडसारी मशीनों सहित) चीनी मिलों की मशीनें
- 2. मूली मिलों की मशीनें
- 3. जुट मिलों की मशीनें
- 4. तेल मिलों की मशीनें
- 5. जुसे बनाने की मशीनें
- 6. चाय की मशीनें
- 7. आटा, चावल, दाल मिलों की मणीनें
- 8. छपाई की मशीनें
- 9. कागज बनाने की मशीनों
- 10. लकड़ी का काम करने की मशीनें
- 11. उर्वरक संयंत्र और उपस्कर
- 12. पानी साफ करने के संयंत्र
- ब. उत्पादक माल
- 1. बिजली मोटर
- 2. ट्रॉन्सफ़ॉर्मर (पावर और वितरण)
- 3. जनित (जेनरेटर)
- 4. स्विच गियर
- 5. औद्योगिक स्विच बोर्ड और नियंत्रण पैनल
- 6. सर्किट श्रेकर
- 7. एयर ब्रेकर स्विच
- 8. टेलीफ़ोन
- 9. टेलीफ़ोन स्विच बोर्ड और टेलीग्राफ़
- 10. गैस संयंत्र
- 11. बोरहोल टर्बाइन पम्प
- 12. डीजल इंजन
- बस, बस बाडी किट, मोटर गाडियां और चेसिज
- 14. पारेषण लाइन टावर
- 15, सब-स्टेशन संरघनाएं और रेल विद्युतीकरण संरचनाएं

- 16. संरचना संबंधी गढ़ाई, जैसे पुल, कारखानों के शेड, मकान तथा शटर और स्केफ़ोल्डिंग सामग्री
- 17. खरादें
- 18. इस्पास के बिलेट
- 19. इस्पात की पटरियां
- 20. रेल पटरी बिछाने की सामग्री
- 21. रेलवे सिगनल उपस्कर
- 22. अपकेन्द्री पम्प
- 23 बाहनों के ट्रेलर और मोटरों के पुर्जे
- 24. औषार (दस्ती और मशीनी)
- 25. कृषि उपकरण
- 26. गैस के सिलिंडर
- .27. इस्पात के टैंक
- 28 तोलने की मशीनें
- 29. तेल निष्कासक
- 30. ट्यूब के आकार के खंभे और उपसाधन
- 31. उलटाने वाले वैगन और रेल वैगन
- 32. कोलतार बायलर
- 33. ऋेन

ग. उपभोक्ता माल

- 1. सिलाई मशीनें और उनके पूर्जे
- 2. साइकलिंग-उनके पुर्जे और उपसाधन
- बिजली के प्रशीतक (रेफिजिरेटर),
 बातानुकूलक और जल-शीतक
- 4. बिजली के पंखे
- 5. एसीएसआर संवाहक और तांबे के संवाहक
- एक्स-रे बिजली-चिकित्सा उपस्कर और अस्पताल उपस्कर
- 7. आग बुझाने के उपस्कर
- घ ऐसे बूसरे माल जिनके संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन नियमावली, 1952 के नियम 6 के (अधीन 6 महीनों से अधिक आरंभिक अवधि के लिए छूट दी गयी है।

वोधिक भारतीय औद्योगिक 30 जून 1970

			30 4/1 1370
पिछले वर्ष	बेयता एं	इस वर्ष	
रुपये		रुपये	रुपये
50,00,00,000	 पूँजी अधिकृत जारी की गई और प्रदत्त 		50,00,00,000
20,00,00,000	जारा का गर्जार प्रचल		20,00,00,000
	 रिक्षत राशियां और रिक्षत निधि 		
8,91,30,000	(i) रक्षित निधि	12,00,70,000	
	(ii) अन्य रक्षित राशियाँ		
1,905	(क) निवेश के लिए रक्षित राशि -	41,64,126	
	 उपहार, अनुधान, चंदे और दान 		12,42,34,126
	(i) सरकार से		****
	(ii) अन्य स्रोतों से		
	 बाड और डिमेंचर 		
	5. जमा राशियां ~		 -
	6. ऋण		
	(i) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से		
	(क) स्टाक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभृतियों की		
	जमानत पर	**************************************	
	(ख) विनिमय बिलों या वचन-		
	पन्नों की जमानत पर (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		
	(दीर्घकालीन कियाएं)		
6,26,71,044	निधि में से	26, 26, 71, 044	•
10.00.00.000	(ii) भारत सरकार से (क) ब्याज-मुक्त ऋण	10,00,00,000	
10,00,00,000	(का) अन्य ऋण (खा) अन्य ऋण	1,39,43,539	
1,40,15,00,000	(iii) अन्य स्रोतों से		
_	(iv) विदेशी चलभुद्रा में		
~	, ,	مساسر إسراس إسراك المساد المسا	1,75,70,23,583
3,92,38,524	7. चालू देयताएं और व्यवस्थाएं		5,73,55,813
1,89,25,41,473	आगे ले जाया गया	_	2,13,86,13,522

विकास बैंक को तुलन पक्र

सामान्य मिधि

नग पुलन नम्न			सामाग्य ।गाध
पिछले वर्ष	आस्तियाँ	इस वर्ष	
ग्न		रुपये	रुपये
	 नकदी और बैंकों के पास गोप 		
13,842	(i) हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पाम शोष	72,577	
٦	(ii) अन्य बैंकों के पाम गोष		
	(क) चालूखाते में		
	(ख) जमाखातेमें		72,577
	2 निवेश @		
13,95,94,453	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में	12,74,18,214	
23,82,79,044	(ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों, और डिबेंचरों में	24,32,54,044	
10,25,05,110	(iii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाकों, णेयरों, बांडों और डिबेंचरों में*	10,45,36,189	
			47,52,08,447
	3. ऋण और अग्रिम		×
	(i) अनुस्त्रित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य विसीय संस्थाओं		
63,99,94,315	को	63,76,87,733	
46,35,08,000	(ii) औद्योगिक संस्थाओं को	56,20,84,969	
			1, 19, 97, 72, 702
26,76,50,387	 विनिमय बिल और यचन पत्न जिनका भाजन या पुनर्भाजन किया गया 		42,86,08,008
	 परिसर (लागत में से मूल्यह्नास घटाकर) 		
2,20,606	6. अन्य अचल आस्तिया (लागत में से मूल्यह्नास घटाकर)		2,68,844
4,07,75,716	7. अन्य आस्तियां		3, 46, 82, 944
1,89,25,41,473	आगे ले जाया जया	- <u>-</u>	2,13,86,13,522

मारतीय औद्योगिक

30 जून 1970

হল বৰ্ণ 	देतयाएं	इस वर्ष	·
रुपये		रुपये	रुपये
1,89,25,41,473	आगे लाया गया		2,13,86,13,522
	8. लाभ-हानि लेखा		
	संलग्न लेखे से अंतरित किया गया		
3,58,54,325	लाभ पोष	3,89,40,829	
2,83,50,000	घटाइये : रक्षित निधि को अंतरित	3,09,40,000	
	चटाइये : भारतीय औद्योगिक विकास		
	बैंक अधिनियम 1964 की धारा 22		
	(2) के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया		
75,04,325	को अंतरणीय शेष 	80,00,829	
	आकस्मिक देयताएं		
	(i) बैंक परकिये गये दावे जिनको		
	ऋणों के रूप मेंस्वीकार नहीं		
4,45,060	किया गया	4,45,060	
45,77,91,646	(ii) जारी की गई गारंटियो के लिए**	40,63,92,799	
1,93,50,000	(iii) हामीदारी की वर् षन बद्ध ता	•	
	के लिए	3,06,11,973	
·	(iv) अंशत: प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांग न की गई		
70 00 050	जााद पर माग न का गाइ राशियों के लिए	17 21 005	
78,96,958	राशियाकालए (v) वे राशियां जिनके लिए बैंक	17,31,225	
	भाकस्मिक रूप से उत्तरदायी		
	जानासमा <i>७५ स</i> उत्तरपाया है		
1,89,25,41,473		43,91,81,087	2,13,86,13,522
	·		
		बही मूल्य रुपये	बाजा र मूल्य रुपये
@ (क) निवेश जिनका भ	व लगाया गया	21, 28, 76, 496	24,78,20,342
(ख) निवेश जिनका भ		26,23,31,951	
	 -	47,52,08,447	24,78,20,342

^{*}हामीदारी दायित्वों को निभाने के कारण अजित (इनमें 'अधिकार' शेयरों और प्रस्यक्ष अभिदानों के अर्जन की 65,20,170 रुपयों की राशि शामिल हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार एस० बी० विलीमोरिया एण्ड कम्पती सनदी लेखापाल

^{**}इनमें 25,06,28,043 रुपयों की वेयता-राणि णामिल है जिसे सहभागी विसीय संस्थाएं वहन करने के लिए सहमत हैं (पिछले वर्ष यह राणि 28,49,97,508 रुपयें थी) ।

TUVI	TTT	OEC.	7

किंग्स बेंक

को तुलन पत्र				
पिछले वर्ष	आस्तियाँ	इस वर्ष		
चपये		रुपये	रूपये	
1,89,25,41,473	आगे लाया गया		2, 13, 86, 12, 522.	
	8. लाभ-हानि लेखा			
	पिछले तुलन पनका शेव			
	संलग्न लेखें से अंतरित किया गया			
	लाभ/की गई हानि			

1,89,25,41,473

2,13,86,13522

बोर्ड के आवेशानुसार

बी० एन० मलहोता संयुक्त जनरल मैनेजर बम्बई, 17 अगस्त 1970 एस० जगन्नाथन, अध्यक्ष आर० के० हजारी, उपाध्यक्ष जे० रामवधे राच, निवेशक जी० बसु, निवेशक

भारतीय औद्यों

30 जून 1970 को समाप्त हुए

पिछले वर्ष	ह्यय	इस वर्ष
रुपये		 रुपये
6,41,75,090	া जमाराक्षियों, उधारों आदि पर अदा किया गया व्याज	7,37,90,182
30,92,490	2. स्थापना-खर्च	39,24,013
	 निदेशकों और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की फीस और 	
36,657	खर्च	27,355
9,000	4. लेखा परीक्षकों की फीस	9,000
3,00,958	5 _. किराया, कर, बीमा , प्र काश आदि	3,91,906
3, 5 2, 1 1 9	6. विधि-प्रभार	2,57,361
12,881	7. डाक, तार और मुद्रांक	14,997
40,162	8. लेखन-सामग्री, छपाई, विज्ञापन आदि	72,044
35,591	9. मूल्यह्नास	31,168
	10. निवेशों की ब्रिकी पर वास्तविक हानि (जिसे रक्षित निधियों या किसी	
	विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	
1,14,323	11. अन्य खर्च	3,13,554
3, 5 8, 5 4, 3 2 5	12. लाभ गेष जिसे तुलनपत्र में ले जाया गया है	3,89,40,829
10,40,23,596		11,77,72,409

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी सनदी लेखापाल

किंस बेंक

	आब	
पिछले वर्ष	(अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान की गयी व्यवस्था को घटाने के बाद)	इस वर्ष
रुपये	,	रुपये
7,94,58,890	ा. ब्याज और भाजन	9,54,75,993
2,07,52,923	2. निवेशों से आय	1,89,60,632
37,23,982	3. कमीशन, दलाली, आदि	27,71,570
	 निवेशों की ब्रिकी पर वास्तविक लाभ (जिसे रक्षित निधियों या किसी विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है।) 	
5,87,801	5. अन्य आय*	5,64,214
	6. हानि शेष जिसे तुलनपत्र में ले जाया गया है।	_
10,40,23,596	·	11,77,72,409

भी० एन० मलहोसा संयुक्त जनरल मैनेजर बोर्ड के आवेशानुसार

एस० जगन्नाचम, अध्यक्ष

आर० के० मुजारी, उपाध्यक्ष

जे० रामध्ये राष, निवेशक

बम्बई, 17 अगस्त 1970

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

जी० बस्, निवेशक

हमने 30 जून 1970 तक के भारतीय आँद्योगिक विकास बैंक के संलग्न तुलनपत तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के बैंक के लाभ-हानि लेखें की लेखा-परीक्षा की है और हम नीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:---

- (1) मद्रास और कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालयों में रहने वाले कुल 88,43,016,54 रुपयों के पुनर्भाजन किये गए विनिमय विलों का हमने सत्यापन तो नहीं किया है किन्तु उनके बारे में क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा दिये गये प्रमाणपक्षों को मान लिया है।
- (2) उपर्युक्त तथ्य के अधीन:-
 - (क) हमने लेखा-परीक्षा के लिए अपेक्षित जो जनकारी मांगी है और जो स्पष्टीकरण मांगें हैं वे सब हमें दिये गये हैं और वे सन्तोषजनक हैं;
 - (ख) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है, उसके अनुसार और हमें विये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त सुलन पत्न पूर्ण और सही तुलन पत्न है जिसमें ऐसे सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं जिनसे 30 जून 1970 तक के बैंक के कार्य-कलाप की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलन पत्न भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की आवश्यकताओं के अनुसार भी उचित ढंग से तैयार किया गया है।

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

बम्बई, 17 अगस्त 1970

भारतीय औद्योगि

, 30 जून 1970

पिछले वर्ष	वेमताएं		इस वर्ष
रुपये		रुपये	रुपये
27,35,00,000	 ऋण (i) सरकार से (ii) अन्य स्रोतों से 	27,34,92,050	
	 उपहार, अनुवान, चन्दे और वान (i) सरकार से (ii) अन्य स्रोतों से 		27,34,92,050
5,00,000 88,10,105 50,27,406	 अन्य देयताएं और व्यवस्थाएं लाभ-हानि लेखा पिछले तुलनपत्र का शेषांश संलग्न लेखे से अंतरित किया गया लाभ शेष 	1,38,37,511 77,85,331	4,94,75 0
	आकस्मिक देयताएं (i) बैंक पर किये गये दावे जिनको ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं		2,16,22,842
	किया गया (ii) जारी की गई गारंटियों के लिए (iii) हामीदारी की वचनबद्धता के लिए (iv) अंशत: प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर		
·	मांग न की गयी राशियों के लिए (v) वे राशियां जिनके ृेलिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हैं 		
28,78,37,511			29,56,09,642

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार एस० बी० विलीमोरिया एण्ड कम्पनी सनदी लेखापाल ्र विकास बैंक

पिछले वर्ष	आस्तियां	इस वर्ष		सहायसा	
रुपये		रुपये		<u></u>	 रुपये
	1. नकवी और बैंकों के पास शोष	,			
1,029	(i) हाथ में नकदी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास शेष	6,294			
	(ii) अन्य बैंकों के पास शेष				
_	(क) चालूखातेमें (खा) जमास्त्रातेमें	 			
	-	·			
	2. मिवेश(@				6, 29
	 (i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की 				
61,84,856	प्रतिभूतियों में	2,50,30,225			
2,48,98,200	(ii) औद्योगिक संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बांडों और डिवेंचरों में*	1,83,45,150			
				4,33,7	75.37
25,00,00,000	3. ऋण और अग्रिम	•		24,47,5	
67,53,426	4. अर् आस्तियां				7,97
	5. लाभ-हानि लेखा				
	पिछले तुलनपत्र का शेषांश संलग्न क्षेत्र से अंतरित किया गया			;	1 -
	लाभ/की __ गई हानि				-
				·	
28,78,37,511				29 56,0	9,64
		वही मूल्य	1	बाजा	 र मू ल्य
@[क्क] निवेश जिनका भार [ब्क] निवेश जिनका भार		4,33,75,375		7, 58, 5	3,67
		4, 3 3, 7 5, 3 7 5	 · · · · ·	7,58,5	3, 67
*हामीवारी दायित्वों	को निभाने के कारण अजित । बोर्ड के आवेशानुसार				

बी० एन० मलहोता संयुक्त जनरल मैनेजर बम्बई, 17 अगस्त 1970

एस० जगन्नाथम, अध्यक्ष आर० के० हजारी, उपाध्यक्ष जे० रामववे राव, निदेशक जी० बसु, निदेशक

भारतीय औद्योगिक

30 जून 1970 को समाप्त हुए

पिछले वर्ष	व्यय	इस वर्ष
रुपये	·	रुपये
1,50,42,000	1. उधारों पर अदा किया गया ब्याज	1,50,42,000
5,00,000	•	4,94,750
	3. लेखा परीक्षकों की फीस	
	4. किराया, क्र, बीमा, प्रकाश आदि	
	5. विधि-प्रभार	
	 डाक, तार और मुद्रांक 	
		·
	 निवेशों की विकी पर वास्तविक हानि (जिसे रिक्षत निधियों या किसी 	
	विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है)	
	9. अन्य खर्च	
50,27,406	10. लाभ शेष जिसे तुलन-पत्न में ले जाया गया है -	77,85,331
2,05,69,406		2,33,22,081
	·	

@इस निधि के प्रशासन और उपयोग से सम्बन्धित खर्च के लिए सामान्य निधि को की गयी प्रतिपूर्ति का परिचायक है।

हमारी संलन रिपोर्ट के अनुसार एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी सनदी लेखापाल

विकेशिस खेक

वर्ष का लाभ-हानि लेखा		विकास	सहायता निधि
पिछले वर्ष	आय (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य आवश्यक और उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए वर्ष के दौरान की गयी व्यवस्था को घटाने के बाद)		इस वर्ष
रुपये			रुपये
2,00,00,000	 व्याज निवेशों से आय 		1,98,47,632
	 कमीशन, दलाली आदि निवेशों की बिक्री पर वास्तविक लाभ (जिसे रक्षित निधियों या किसी 		10,03,570
	विशेष निधि या लेखे के नामे नहीं डाला गया है) 5. अन्य आय		24,70,879
	6. हानि शेष जिसे तुलन-पत्न में ले जाया गया है		
2,05,69,406		-	2,33,22,081
			.

बोर्ड के आवेशानुसार

बी॰ एन॰ मलहोता संयुक्त जनरल मैनेजर बम्बई, 17 अगस्त 1970

एस० जगक्षाथन, अध्यक्ष आर० के० हजारी, उपाध्यक्ष जे० रामदेवे राव, निदेशक जी० बक्ष, निदेशक

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 30 जून 1970 तक के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की विकास सहायता निधि के संलग्न तुलन-पत्न तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के निधि के लाभ-हानि लेखे की लेखा-परीक्षा की है और हम भीचे लिखे अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :---

- (1) हमने लेखा-परीक्षा के लिए जो जानकारी मांगी है और जो स्पष्टीकरण मांगे हैं वे सब हमें दिये गये हैं और वे सन्तोषजनक हैं;
- (2) हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार, और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्न पूर्ण और सही तुलन-पत्न हैं जिसमें ऐसे सभी आवश्यक विवरणों शामिल हैं जिनसे 30 जून 1970 तक के निधि के कार्यकलाप की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके और उक्त तुलन-पत्न भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विनियमावली, 1964 के विनियम 14 की आवश्यकताओं के अनुसार भी उचित ढंग से तैयार किया गया है।

एस० बी० बिलीमोरिया एण्ड कम्पनी सनदी लेखापाल

बम्बई. 17 अगस्त 1970 M59GU/71—7 (30 जून 1970 को)

प्रमुख अधिकारी

मुख्य कार्यालय

जनरल मैनेजर उप-जनरल मैनेजर एस० एन० एन० सिम्हा बी० एन० मलहोत्ना ए० एन० विज एन० के० सील

मैनेजर

ओ० पी० बेरी
डी० एम० दीक्षित
टी० एन० गिडवानी
डी० पी० गुप्ता
एन० डी० जोशी
वाई० एस० केंदार
एस० डी० खोसला
एस० डी० खोसला
एस० डि० एस० राघयन
के० एस० राजन
एन० जी० सेन
सी० आर० सेन गुप्ता
एन० वी० सीताराम
एस० के० सुक्रमणियन

क्षेत्रीय कार्यालय

मैनेजर

कलकत्ता

पी० सी० जैन

टी० तिवारी

मद्रास

एम० आर०बी०पुंजा

नई दिल्ली

डी० सी० वधवा

भारतीय औद्योगिक विकास बेंक

न्यू इंडिया सेन्टर

17, कूपरेज

पोस्ट बाक्स सं० 1241.

यम्बई-1

तार : 'INDBANKIND'

RESERVE BANK OF INDIA Central Office

Department of Banking Operations & Development

Bombay-1, the 16th April 1971

DBOD. No. 95/Incl./C.102-71.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act, of the following bank, namely:—

The Lord Krishna Bank Ltd., Kodungallur.

R. K. HAZARI, Deputy Governor

AGRICULTURAL CREDIT DEPARTMENT

Bombay-18, the 28th April 1971

No. ACD No. 24/A.18-70/71.—In pursuance of subsection (2) of Ssection 36A read with clause (za) of Scction 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following banks have ceased to be primary co-operative banks within the meaning of the said Act.

Name of the primary co-operative bank and State/Union Territory

Sr. No.

- Hindustan Shipyard Labourers' Co-operative Thrift and Credit Society Ltd., Gandhigram, Visakhapatnam.—Andhra pradesh.
- 2. Indian Leaf Tobacco Development Company Staff Co-operative Bank Ltd., 'Unity House', Chirala, Guntur District.—Andhra Pradesh.
- 3. 'E' Ward East and 'E' Ward Central Conservency Labour Employees' Co-operative Credit Society Ltd., Conservancy Ward Office Junction of Ripon Road and Souter Street, Bombay-11,--Maharashtra
- National Instrument Factory Employees Co-operative Society Ltd., Raja Subodh Mallick Road, Jadavpur, Calcutta-32.—West Bengal
- Survey of India Co-operative Credit Society Ltd., 13, Wood Street, Calcutta-16.—West Bengal

M. V. HATE, Joint Chief Officer.

STATE BANK OF PATIALA

Patiala, the 1st April 1971

SBOP No. 15.—The following transfers and changes in the posting of Bank's Supervising Staff are hereby notified:—

1. Shri S. S. Sethi, Junior Officer officiated as Manager, Model Basti, New Delhi Branch as from the close of business on 12-2-71 to the commencement of business on 18-2-1971 and from the commencement of business on 22-3-71 to the commencement of business on 26-3-71 vice Shri S. P. Aggarwal, Officer Grade 'C'.

S, D. GANDA, General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 12th April 1971

No. 5-CA(v)/25/71-72.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/15/70-71 dated 30th November, 1970, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has restored to the Register of Members with effect from the 29th March, 1971, the name of Shri Harshadrai Shantilal Shah, A.C.A., 42, Tripathi Bhuwan No. 2, Aarey Road, Goregaon (W), Bombay-62 (M-8625).

No. 5-CA(1)/3/71-72--With reference to this Institute's Notification Nos. 4-CA (1)9/68-69 dated 31-7-1968 and 4CA (1) 12/68-69 dated 30-8-1968, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the 1st April, 1971, the names of the following gentlemen:-

St. Membership No. No.		Name and Address	
1.	2453	Shri Gujjari Venkata Krishna Rao, A.C.A., 9/2, Navratan Bagh, Indore-1,	
2.	6599	Shri Gullapalli Venkata Krishna Rao, A.C.A., 42/3-RT, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad-38.	

The 13th April 1971

No. 4-CA(1)/1/71-72. In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute at their own request, with effect from the dates mentioned against their names the names, of the following gentlemen:—

SI. Membership No. No.		Name and Address	Date of Removal	
J.	579	Shri Kasi Sankar Mitra, F.C.A., 48-A, Raja Nobo Kissan Strect, Calcutta-5.	31-3-71	
2.	1356	Shri Jal Jamshedji Chothia, A.C.A., Adam Mansion, Cowasji Patel Street, Fort, Bombay-1	31-3-71	
3.	1423	Shri Priyamohan Chakra- barti, F.C.A. 269/1, Jodhpur Park, Calcutta-31.	31-3-71	
4.	1572	Shri William Beatty, A.C.A., Grace Cottage, Civil Lines, Ajmer.	31-3-71	
5.	1664	Shri Bhagavtiswara Aiyar Mahadev, A. C.A., 4/1, Nafar Kundu Road, Calcutta-26	31-3-71	

No. 4-CA(1)/2/71-72 In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:—

	Member- ship No.	Name and Address	Date of Removal
1.	1294	Shri Rameshchandra Ka- purchand Kothary, A.C.A., 2/81, Sahakar Niwas, 20, Tardeo Road, Bombay-34 W.B.	11-1
2.	2592	Shri R. Venkataraman, F.C.A M/S Ram & Co. 27-A, Naickar New Street, Madurai-1	λ.

No. 8-CA (1)/1/71-72 In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled or the period mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice,

SI No.	Member- ship No.		Period during which the Certi- ficate shall stand cancelled
1.	6368	Shri Shiv Raj Saran Agarwat, F.C.A. G-44, Green Park, New Delhi-16	27-3-71 to 30-6-71
2.	9208	Shri L. Kathiresan, A.C.A., Annamalai Illam, Pankajam Colony, Ramand Road, Madurai-9	1-4-71 to 30-6-71
3.	9243	Shri Srideb Datta, A.C.A., 458, Block-K New Alipore, Calcutta-53.	1-4-71 to 30-6-71
	11370	Shri T. Salvaraj, A. C. A., 2, old Bangalow Street, Chintadripet, Madras-2	28-1-71 to 30-6-71
5.	11524	Shri Ashokkumar Hiralal shal A.C.A., 116/3, S. Gandhi Marg, Keshavbaug, Bombay-3.	5, 25-3-71 to 30-6-71

The 14th April 1971

No. 4-CA(1)/3/71-72—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that is exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of prescribed non payment of fees, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:

SI, No.	Member- ship No.	Name and Address	Date of Removal
1.	9581	Shri H. Rajamani, A.C.A., C-44, Thirunagar, Madutai-6	14-4-71
2.	9732	Shri G. Sethuraman, A.C.A., 8/216, Gulestan, Sion (East), Bombay-22 (DD)	14-4-71
3.	10661	Shri Sujan Kumar Sen,A.C.A., 46, N.C.Choudhury Road Calcutta-42.	14-4-71
4,	10696	Shri S. R. M. M. Nainaí, A.C.A., C/o. D.P.P., 6B, Nelson Road, Madras-29,	14-4-71
	4633	Shri Shailesh Chimanlal Shah, F.C.A., M/s. Shailesh Shah & Co., Chartered Accountants, A-29, Maskati Market, Relief Road. Ahmedabad-1.	1-7-70

C. BALAKRISIINAN, Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 17th April 1971

No. INS.I.22(1)1/71(2).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 23rd day of May, 1971 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1959, shall be extuded to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala, namely:—

"The area within the Edamulakkal Panchayat in Pathanapuram Taluk in Quilon District."

The 19th April 1971

No. INSI 22(1)-2/73(3)...In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the schedule given below the first contribution and first benefit periods for sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in repect of pesons in insurable employment on the appointed day of midnight on 24th April, 1971 as indicated in the table given below:—

First Contribution perio		oution period	First benefit period	
Set	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	24-4- 1971	31-7-1971	2 2-1 -1972	29-4-1972
В	24-4-1971	25-9-1971	22-1-1972	24-6-1972
C	24-4-1971	29-5-1971	22-1-1972	26-2-1972
		· ——		· - ·

Schedule

"Village Jhagraha, Bakaho, Bakahi, Bargawan and Amlai in Tehsil Sohagpur in the District of Shahdol in the State of Madhya Pradesh".

Dated the 26th April 1971

No. INS.I.2(1)1/71—The following draft of amendment of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 which the Employees' State Insurance Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred by section 97 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) is published as required by sub-section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft amendment will be taken into consideration on or after 26th May 1971.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft amendments before the date specified will be considered by the said Corporation.

Drast amendments to the E.S.I. (General) Regulations, 1950

Regulation 10(9)

In the first sentence of the present Regulation, the words "Twice each year" shall be replaced by "once a quarter".

Regulation 10(14)

Regulation 10(14) shall be substituted as under:-

- "A Regional Board shall perform the following functions in respect of the Region for which it is set up:
 - (a) Such administrative and/or executive functions as may, from time to time be entrusted or delegated to it by a resolution, by the Corporation or the Standing Committee.

- (b) To make recommendations from time to time in regard to changes which may in its opinion be advisable in the Act, Rules and Regulations and forms and procedure to be followed in the running of the Scheme.
 - (c) To decide within the board frame-work of the general decisions and Programme of priorities of the Corporation, the following matters, provided that where the specific approval of the Corporation or the appropriate Government is required, such approval shall be taken:—
 - (i) Extension of the Scheme to other categories of establishments in accordance with the order of priorities laid down by the Corporation.
 - (ii) Extension of Scheme to new areas and extension of Medical care to families;
 - (iii) Adoption of special measures to meet peculiar conditions in the area;
 - (iv) Improvement in benefits;
 - (v) Provision of indoor medical treatment;
 - (vi) Measures and arrangement for the rehabilitation of insured persons in the area, who are permanently disabled;
 - (vii) Securing compliance by employers with the various provisions of the E.S.I. Act, the regulations and other rules and instructions.
 - (d) To review from time to time the working of the Scheme in the State both on the medical side as well as cash benefit side and to advise the Corporation and the State Government on measures to improve the working of the Scheme both in regard to payment of cash benefits and administration of medical benefits and in particular to promote preventive health measures, safety and personal hygiene and to review and check lax certification and other abuses of the Scheme.
 - (e) To look into general grievances, complaints and difficulties of insured persons, employers, etc. as it may consider necessary.
 - (f) To advise the Corporation on such matters as may be referred to it for advice by the Standing Committee or the Director General.

The Regional Board may set up suitable sub-Committees for carrying out any of its functions and may seek the assistance or advice of Local Committees were necessary."

V. R. NATESAN Insurance Commissioner

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 30th April, 1971

The food corporation of India (staff) Regulations, 1971.

No. 1-6/71-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and all other powers hereunto enabling, and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India, hereby makes the following regulations, namely:—

SECTION-I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application: (1) These regulations may be called the Food Corporation

- of India (Staff) Regulations, 1971.
 - (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to all the employees of the Corporation including transferred employees, other than,—
 - (a) Persons employed on a purely part-time basis; and
 - (b) Persons employed on special contracts to the extent that the terms and conditions of such contracts are inconsistent with the provisions of these regulations:

Provided that, nothing contained in these regulations shall apply to any Director of the Corporation or to the Secretary.

- 2. Definitions:—In these regulations, unless the context other-wise requires:—
 - (a) "Act" means the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964);
 - (b) "Board" means the Board of Directors of the Corporation;
 - (c) "Chairman" means the Chairman of the Corporation;
 - (d) "Corporation" means the Food Corporation of India established under Section 3 of the Act;
 - (e) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Corporation;
 - (f) "Financial Adviser" means the person appointed by the Corporation to be the Financial Adviser or any other person authorised to perform the duties of the Financial Adviser;
 - (g) "Food Department" means the Department of the Central Government dealing with food or any of its subordinate or attached offices and ongaged in the performance of these functions;
 - (h) "Heads of Divisions" means all officers appointed in the rank of Managers or above in the Head Office of the Corporation, or any other officer designated by the Corporation to be a head of a Division;
 - (i) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation;
 - (j) "Pay" excludes allowances;
 - (k) "Secretary" means the Secretary of the Corporation;
 - (1) "Transferred employee" means on officer or other omployee transferred to the Corporation by an order issued under Sub-section (1) of Section 12A of the Act.

SECTION-2

GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

3. Classification: (1) The posts in the Corporation shall be categorised as follows:

All posts with a fixed pay of or on a Scale of pay with a maximum of	Classification
Not less than Rs. 950/-	Category-I
Not less than Rs. 700/- But less than Rs. 950/-	Category-II
Not less than Rs. 150/- But less than Rs. 700/-	Category-III
Less than Rs. 150/-	Category-IV

- (2) The Corporation shall have posts of the description specified in the Table set out in Appendix 1.
- 4. Appointments: (1) Subject to the provisions of regulation 17, the unit for the purpose of appointment, seniority, promotion, reversion and retrenchment shall be as follows namely:—

Category	Recruitment Unit	Promotion/Re- version/retrench- ment unit
IV.	District (Regional and Zonal Offices and Head Office will be separate units).	Region*
III.	Region (Zonal Offices, Head Office will be separate units)	Zone*
П.	Zone (Head Office will be a unit).	Zone
I.	All-India	All-India

- *Head Office will be treated as a separate unit for the purpose of Promotion/reversion/retrenchment provided that the Managing Director shall have the discretion to transfer any employee of the Head Office to any of the Zones or vice-versa, whenever he considers it necessary. In doing so, the Managing Director will keep in view the necessity to give due representation to the various Zones.
- 5. General conditions relating to appointments: The following general conditions shall apply to all appointments to the service of the Corporation:
 - (a) No person shall be eligible for initial appointment unless he has attained the age of 18 years.
 - (b) A candidate for appointment in the service of the Corporation shall be:
 - (i) a citizen of India, or
 - (ii) a subject of Sikkim, or
 - (iii) a subject of Nepal, or
 - (iv) a subject of Bhutan, or
 - (v) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
 - (vi) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tangenvika and Zanibar) with the intention of permanently settling in India:

PROVIDED THAT, a candidate belonging to categories (iii), (iv), (v) and (vi) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India.

- (c) A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview and may also be appointed provisionally subject to the necessary certificate being given to him by the Government.
- (d) No person shall be initially appointed unless he has been certified by a qualified registered medical practitioner approved by the appointing authority to be of sound constitution and medically fit to discharge his duties.

Explanation: Unless the appointing authority otherwise directs, the application of this provision shall be limited to regular appointments by direct recruitment.

- (e) No person shall be eligible for appointment who has previously been dismissed, or compulsorily retired from the service of the Corporation or from a Department of a State or the Central Government or from any public sector undertaking.
- (f) No person shall be eligible for appointment who has been convicted in a court of law for any offence involving moral turpitude.
- (g) No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment in the service of the Corporation;

Provided that, the Managing Director may, if satisfied that such marriage is pormissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- (h) Without prejudice to the generality of the provisions of clauses (d), (e), (f) and (g), no person shall be appointed unless the appointing authority is satisfied that the person is fit for appointment in all respects.
- 6. Appointing Authority: The authorities competent to make appointments to the type of posts indicated in column 2 of the Table set out in appendix 2 will be those specified in the coresponding entries in column 3 of that Table.

Provided that the transferred employees shall be deemed to have been appointed by the competent authority.

- 7. Mode of Appointment: (1) Regular appointments in the service of the Corporation can only be to the posts specified in column (2) of the Table ser out in Appendix 1 sanctioned for a period of not les sthan one year and shall be made:—
 - (a) in accordance with any of the modes specified against each in column (4) thereof; or
 - (b) by transfer from the corresponding categories as specified in column (9) of the said Table of employees of the Central Government in the Directorate General of Food/Pay & Accounts Offices; or
 - (c) by permanent absorption of deputationists in the service of the Corporation.
- (2) Where any qualification, or age limits, have been specified in columns (7) and (8) respectively of the table set out in Appendix 1 in respect of any post with reference to any mode of appointment thereto, only persons satisfying such qualifications and within the age limits so specified shall be appointed to that category through such mode.

Provided that, the authority specified in column 4 of the Table set out in Appendix 2 may in respect of the posts indicated in the corresponding entries in column 2 of that Table.

- (a) relax the specified age limits in the case of persons with exceptional qualifications or experience; and
- (b) relax the qualifications in the case of persons with outstanding record of service.
- (c) Provided further that the Board may relax, by order, any of the provisions of the Recruitment Rules contained in Appendix 1, if in their opinion it is necessary or expedient so to do.

- (3) Notwithstanding aynthing contained in this regulation, appointments may be made to any post in the Corporation on an ad-hic basis.
 - (a) by deputation of suitable officers from the Central or from any State Government or from any public sector undertaking or with the prior approval of the Managing Director from any private sector undertaking for a period not exceeding three years;

Provided that, an authority immediately higher than the appointing authority may extend the period of deputation of an employee belonging to Categories J. II or III beyond 3 years but not exceeding 5 years.

- Provided further that, the Board/Executive Committee, as the case may be, may extend the period of deputation of an employee beyond 5 years in exceptional cases of merit if it is considered necessary in the interest of the Corporation.
- (b) by re-employment of personnel superannuated from service of the Central or any State Government or of the Corporation for a period not exceeding two years; such re-employment being sanctioned by an authority not lower in rank than the Managing Director.

Provided that, the Executive Committee (or in case where the Board of Directors is the appointing authority, the Board) may extend the period of re-employment of Category I. II, or III officers beyond a period of 2 years subject to a maximum age limit of 60 years.

- (c) on a purely temporary basis for a period not exceeding one year;
- (d) on special contracts subject to such terms and conditions as may be decided by the Board.
- 8. Creation of posts: (1) The Corporation shall from time to time determine the number of posts each description in the service of the Corporation.
- (2) The authorities specified in column (1) of the following Table shall be empowered to create new or additional posts in the Corporation of the description specified in column (2) thereof.

Authority	Category of post		
(1)			
Board	Any post below the Board level.		
Chairman	Category-I post the maximum of the scale of pay of which does not exceed Rs. 1600/-		
Managing Director	Category-Il posts and Category-I posts the maximum of the scale of which does not exceed Rs. 1250/		
Personnel Manager	Category-III and IV posts.		
Zonal Manager	 Category-II posts upto six months. 		
	Category-III & IV posts upto one year.		

(3) When a new post is created, the authority creating such post shall specify the scale of pay (which shall not be different from the standard scales of pay adopted by the Corporation) of the post, the mode or modes of appointment thereto and the qualifications and the age limits, if any, applicable thereto. Thereafter such post shall be deemed to have been included under the appropriate category in the Table set out in Appendix 1.

9. Procedure for direct recruitment: The following procedure shall be followed in the case of direct recruitment to posts sanctioned for more than 3 months or to posts sanctioned initially for less than 3 months but extended beyond 3 months.

(a) Category III and IV Posts:

. ...: --- . :==1...

- The vacancies shall be notified to the Employment Exchange/Exchanges having jurisdiction over the unit of appointment. If the Employment Exchanges furnish a non-availability certificate, the appointing authority shall arrange for the issue of an advertisement in a prominent newspaper or newspapers circulating in the Region covered by the Unit of appointment.
- All applications received shall be considered and promising candidates called for interview. Final selection shall be made on the basis of an interview or after holding a test, wherever such a test is considered necessary or appropriate, having regard to the nature of the post.

(b) Category I and II Posts:

- (i) The appointing authority shall notify the vacancies to the Regional Employment Exchanges concerned. At the same time, it will arrange or cause to be arranged for the issue of an advertisement in a few prominent newspapers having All-India circulation. It will be stipulated in such advertisement that other things being equal, preference will be given to candidates registered with the Employment Exchanges.
- (ii) All applications received shall be scrutinized and the candidates considered prima facie suitable shall be called for interview. Interviews shall be held by Selection Boards duly constituted from time to time for different categories of posts. A Selection Board shall consist of not less than 3 members. The Selection Board shall draw up a panel of candidates fit for selection and furnish it to the appointing authority together with its recommendations in the order of The number if persons on the panel shall generally be one and a half times the number of vacancies and the panel shall remain vaild for one year from the date it is draw up. The appointing authority shall ordinarily make appointments in accordance with the list prepared by the Selection Board but where any appointing authority does not agree with the recommendations of the Board, it shall record its reasons in writing for disagreeing with the recommendations and pass such orders as it deems fit.

(c) General:

- (i) Candidates shall be required to appear for interview at their own expense.
- Provided that the appointing authority may in the case of interviews held for Category-II and Category-I post and for departmental candidates grant travelling allowance at such rates as it mny specify.
- (ii) Selected candidates shall be required before appointment to submit themselves to a medical test by a qualified Medical Practitioner approved in this behalf by the appointing authority. The fees payable for the medical test shall be borne by the Corporation.
- 10 Procedures for promotion: (i) Promotion shall be made on the basis of seniority subject to fitness in respect of non-selection posts indicated in Appendix-1 of

the Staff Regulations. In judging fitness of an employee to such non-selection posts, the appointing authority shall take into account the Confidential Character Roll maintained in respect of such employees and performance in test, if any, prescribed by the Corporation.

- (ii) Promotion in respect of selection posts indicated in Appendix-1 of the Staff Regulations shall be made on the basis of merit, seniority being considered only when the merit of contending candidates is approximately the same.
- (iii) All promotions shall be considered by a Promotion Board duly constituted for this purpose and shall be regulated by the general instructions to be issued by the Corporation from time to time in regard to the field of choice of candidates, the size of the panel and the validity of the panel.
 - NOTE: Purely as an interim measure, pending their permanent absorption in the service of the Corporation, the employees of the Central Government in the Directorate General of Food posted to work under the administrative control of the Food Corporation of India may be given ad-hoc promotions, in accordance with the principles mutually agreed upon between the Corporation and the Central Government.
- 11. Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in the services under the Corporation: In making appointmens in the services of the Corporation, reservations and other concessions would be provided to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other category of persons as directed by Government of India from time to time. The Managing Director may issue detailed administrative instructions accordingly.
- 12. Treatment of appointment made prior to coming into force of these regulations: Appointments made prior to the coming into force of these regulations shall be treated in the following manner, namely:
 - (a) Where the appointment has been made on the basis of a competitive selection of candidates applying against an advertisement issued or against requisition sent to Employment Exchanges, the appointment shall be deemed to have been regularly made to the service of the Corporation by direct recruitment in the corresponding post in the table set out in Appendix-1.
 - (b) In every other case the appointment shall be deemed to have been made on an ad-hoc basis in accordance with sub-clauses (a), (b) and (c) of Clause 3 of regulation 7 as may be appropriate in the circumstances of each case.
- 13. Commencement of service: Service shall be deemed to commence from the working day on which an employee reports for duty in an appointment if he reports for such duty in the forenoon and from the following day if he reports for duty in the afternoon.
- 14. Declaration of Fidelity and Secrecy: Every person on first appointment to service of the Corporation shall before entering upon his duties make a declaration of fidelity and secrecy as required under Section 38 of the Act,
- 15. Probation: (1) Every person regularly appointed to any post in the Corporation under sub-clause (a) of clause (1) of regulation 7 shall be required to be on probation for a period of one year from the date of appointment.
- (2) The appointing authority may in his discretion extend the period of probation by a further period not exceeding one year.

- (3) During the period of probation an employee directly recruited shall be liable to be discharged from service without assigning any reason by giving him a notice of.
 - (a) 30 days or pay in lieu thereof in the case of an employee belonging to Category-I or Category-II:
 - (b) 7 days or pay in lieu thereof in the case of an employee belonging to Category-III and Category-IV.

An employee promoted from a lower post to a higher post shall be liable to be reverted to the lower post without notice and without assigning any reason.

- (4) An employee who has satisfactorily completed his probation in any post shall thereupon be confirmed as soon thereafter as possible.
- (5) Where an employee has rendered continuous temperary service or continuous service on deputation in any post immediately preceding his regular appointment to such post, the period of service so rendered temporarily or on deputation may be counted against the period of probation of the appointing authority so directs.
- 16. Seniority: Seniority of employees appointed shall be determined as follows:

(1) Direct recruits:

The relative seniority of all direct recruits will be determind by the order of merit in which they are selected for such appointment by the selecting authority; persons appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

(2) Promotees;

(a) The relative seniority of persons promoted to various grades will be determined in the order in which their names appear in the panel drawn up in accordance with regulation 10.

Provided that, the seniority of an employee, who refuses to accept promotion, may be altered in accordance with the administrative instructions issued by the Corporation from time to time,

- (b) Where promotions to a grade are made from more than one grade, the eligible persons will be arranged in a separate list in the order of their relative seniority in their respective grades. The Selection Committee will then select persons for promotion from each list upto the prescribed quota and arrange all the candidates selected from different lists in a consolidated order of merit which will determine the seniority of the persons on promotion to the higher grade.
- (3) The relative seniority of direct recruits and promotees:

The relative scniority of direct recruits and promotees will be determined according to the rotation of the vacancies as between direct recruits and promotees as based on the quotas reserved for direct recruitment and promotion respectively.

(4) Transferred Employees:

- (a) Inter-se seniority of the Food Department employees transferred to the Corporation will follow the order of their relative seniority in the Department of Food irrespective of their actual date of employment in the Corporation. The seniority of an employee belonging to a Regional Directorate who is working on the date of his employment by the Corporation in the Procurement Organisation on a temporary transfer basis, will be determined on the basis of his seniority in the Regional Directorate.
- (b) If employees in one or more grades in the Food Department are merged in a common grade in the Corporation, their inter-se seniority shall be determined on

the basis of length of continuous service in the equated grades.

(5) Relative scalority of Food Department transferees and direct recruits of the Corporation:

The seniority of employees transferred to the Corporation from the Food Department vis-a-vis the seniority of direct recruits employed by the Corporation will be determined with reference to the length of continuous service in the grade concerned in the Corporation including the service in an appropriate/equaled grade(s) in the Department. Such fixation of seniority will, however, be without prejudice to the inter-se seniority of the Food Department transferees to the Corporation in accordance with item (4) above and the Inter-se seniority of other persons employed by the Corporation in accordance with items (1) to (3) above.

(6) Seniority of deputationists absorbed in the service of the Corporation:

The seniority of deputationists absorbed in the service of the Corporation shall be determined with reference to the terms of absorption.

(7) Relative seniority of an employee transferred from one Unit to another;

An employee transferred from one unit of seniority to another will be ranked as the junior most in the particular category on the date he joins the new Unit. It, however, such transfer is in the opinion of the competent authority in the interest of the Corporation, seniority of the transferce will be fixed in the new Unit after giving full weightage to the service counting for seniority in the particular category in the old Unit.

- .17. Transfers and tours: An employee shall be liable to serve anywhere in India in the service of the Corporation and to proceed on tour in the course of his official duty to any place within India or abroad.
 - 18. Deputation of officers of the Corporation in other

Organisation: Employees of the Corporation may be sent on deputation to other organisations (including Central/State Government) with the prior approval of the Managing Director. The deputation of such employees shall be governed by the terms to the mutually agreed upon between the Corporation and the borrowing authority.

19. Termination of service and discharge: (1) The services of any employee who has been appointed on a regular basis to any post in the Corporation and has satisfactorily completed his period of probation may be terminated by the competent authority on giving such employee 90 days notice or pay in lieu thereof.

Provided that, services of a transferred employee shall not be terminated except as a consequence of abolition of posts or a reduction in their number. Termination of service consequent on such abolition or reduction shall take place in the order of juniority in the grade concerned in the Corporation and the period of notice or pay in lieu thereof in such cases shall not be less than the period or pay in lieu thereof to which such a transferred employee was entitled if he had continued in Government service.

Provided further that, a transferred employee who is promoted to a higher post in the Corporation shall be reverted to the grade from which he is promoted in the case of abolition or reduction in the number of posts to which he is promoted in the Corporation.

(2) The services of any employee appointed under sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (3) of regulation 7 may be terminated by the competent authority on giving him—
L59GI/71—8

- (a) 30 days' notice or pay in lieu thereof in case of an employee belonging to category I or category II;
- (b) 7 days' notice or pay in lieu thereof in the case of employees belonging to category III or category IV.
- (3) The Competent authority for purposes of this regulation will be an authority not lower in rank than the appointing authority.
- (4) Nothing contained in this regulation shall affect the right of the appropriate authority for dismissal, removal from retrice or compulsory retirement of an employee as a result of disciplinary proceedings or in pursuance of the provision relating to retirement under regulation 22.
- 20. Safeguards to transferred employees: The reemloyment or transferred employees by the Central Government who are rendered surplus as a result of winding up of the Corporation or abolition or reduction of posts will be regulated by the instructions contained in Appendix 3,
- 21. Resignation: (1) No employee shall resign from the service of the Corporation except by giving such notice as an employee of equivalent rank would have received under regulation 19 or under regulation 15(3) as the case may be if his services were to be terminated, or compensation paid in lieu of such notice.

Provided that, it shall be open to the appointing authority to waive such notice.

- (2) Resignation may be accepted by the appointing authority with immediate effect or at any time before the expiry of the period of notice in which case an employee shall be paid pay in respect of unexpired period of notice given by him. In case a shorter period of notice is accepted at the request of any employee he shall be entitled to receive his pay and allowances only in respect of actual period spent on duty in the Corporation.
- (3) An employee leaving the service of the Corporation without giving proper notice shall be liable to disciplinary action under these regulations.
- 22. Superannuation and Retirement: (1) Every employee appointed to the service of the Corporation shall retire when he attains the age of 58 years.
- (2) Notwithstanding anything contained in Clause (1):
- (A) (i) The appropriate authority shall, if it is of the opinion that it is in the interest of the Corperaton to do so, have the absolute right to retire a Category-I or II Officer by giving him a notice of not less than 3 months in writing or 3 months' pay and allowances in lieu of such notice.
 - (a) After he has attained the age of 50 years, if he had entered the Corporation service before attaining the age of 35 years.
 - (b) In any other case after he has attained the age of 55 years.
 - (ii) A Category-I or a Category-II Officer of the Corporation may, by giving a notice of not less than 3 months in writing to the appropriate authority, retire from the service of the Corporation after he has attained the age of 50 years if he had entered the Corporation service before attaining the age of 35 years and in all other cases after he has attained the performance in test, if any, prescribed by age of 55 years.

- (B) (i) The appropriate authority shall, if it is of the opinion that it is in the interest of the Corporation to do so, have the absolute right to retire a Category-III employee of the Corporation after he has completed 30 years of service by giving him a notice of not less than 3 months in writing or 3 months' pay and allowances in lieu of such notice.
 - (ii) A Category-III employee of the Corporation may, by giving a notice of not less than 3 months in writing to the appropriate authority, retire from the service of the Corporation if he has completed 30 years of service.
- (3) Nothing contained in clause (1) and clause (2) shall affect the right of the competent authority to retire an employee with due notice or pay in lieu thereof on his being certified by a medical examiner to be nominated for the purpose by such authority as being incapacitated for a further period of continuous service due to his continued illness or accident.
- (4) An employee may be permitted to retire at his own request on the competent authority being satisfied that such employee is incapacitated for a further period of continuous service due to his continued illness or accident.

Provided that, before acting under this clause it shall be open to such authority to require the employee to undergo a medical examination by such medical examiner as it may nominate for this purpose.

(5) The competent authority for the purpose of this regulation shall in respect of an employee be the authority competent to terminate the services of an employee of equivalent rank under clause (1) of regulation 19.

SECTION-3

LEAVE AND JOINING TIME

- 23. Kinds of leave; (1) Employees shall be eligible for the following kinds of leave, namely:—
 - (a) Earned Leave
 - (b) Sick Leave
 - (c) Maternity Leave
 - (d) Extraordinary Leave

Note:—In addition, the employees of the Corporation may be granted Casual Leave, Special Casual Leave, Quarantine Leave, Study Leave, Special Disability Leave and Terminal Leave in accordance with the administrative instructions to be issued by the Corporation from time to time.

(2) The transferred employees may exercise an option in writing in terms of section 12 A of the Act to be governed either by the Leave Rules of the corporation or by the Leave Rules of the Central Government as amended from time to time and such option shall be final. Those who have not exercised the option by the fixed date shall be deemed to have opted for the Leave Rules of the Corporation.

Explanation: Earned Leave/Half Pay Leave to the credit of the transferred employees on the date of their absorption in the Corporation shall be carried forward. Transferred employees opting for the Leave Rules of the Corporation will be allowed to avail themselves of half pay leave to their credit on the date of their transfer in accordance with the Leave Rules of the Central Government.

- 24. General conditions governing grant of leave: The following general principles shall govern the grant of leave to employees:
 - Leave cannot be claimed as a matter of right. When the exigencies of the Corporation's service

- so require, the discretion to refuse, postpone, curtail or revoke leave of any description or to recall to duty any employee already on leave is reserved to the authority competent to grant it.
- (ii) Subject to the provisions of regulation 23 all leave is reserved to the authority competent to grant it.
- (ii) Subject to the provisions of regulation 23 all loave lapsos on the cessation of the employee's service in the Corporation whether as a result of discharge, dismissal, retirement, death or otherwise.
- (iii) An employee on leave shall not take up any other service or accept any employment.
- (iv) Leave shall not be availed of without obtaining the prior sanction of the competent authority; applications for such sanction shall be submitted in writing to the competent authority sufficiently in an advance. In case where an employee is compelled to absent himself from duty on account of unforeseen circumstances without obtaining prior sanction, sanction for leave should be applied for at the carliest possible opportunity.
- (v) An employee is expected to avail himself of the leave granted fully before resuming duty and may not return to duty before the expiry of such leave except with the permission of the competent authority.
- Provided that, on employee who has been granted casual leave may at any time before the expiry of such leave rejoin duty without availing himself of the full period of the casual leave sanctioned.
- (vi) An employee who remains absent after the and of his leave shall be entitled to no leave salary for the period of such absence and the period of over-stayal shall be treated as extraordinary leave unless otherwise directed by the competent authority. An employee wilfully absenting from duty after the expiry of leave shall also be liable to disciplinary action.
- (vii) Leave may be prefixed and/or suffixed to a holiday but holidays intervening during the period of leave shall except in the case of casual or special casual leave, count as part of leave.
- (viii) Leave begins from the day on which charge is handed over if such handing over takes place in the forenoon of that day or from the next day if such handing over takes place on the afternoon of that day: leave ends on the day proceding that on which charge is resumed if such resumption takes place in the forenoon and on the day on which charge is resumed if such resumption takes place in the afternoon.
- (ix) Any kind of leave may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave.
- Provided that, casual leave cannot be availed of in conjunction or combination with any other kind of leave except special casual leave.
- (x) Unless otherwise provided, employees on deputation shall be governed by the leave rules applicable in their parent departments except in respect of casual leave/special casual leave.
- (xi) An employee before proceeding on leave shall intimate to the competent authority his address while on leave and shall keep the said authority informed of any change in the address from time to time.

- for a continuous period exceeding 5 years. An employee who remains absent beyond that period will cease to be an employee of the Corporation.
- (xiii) The kind of leave applied for by an employee and lying at his credit may not be altered by the authority competent to grant leave.
- 25. Earned Leave: (1) Earned leave shall accrue to an employee at the rate of one-eleventh of the period spent on duty. "Duty" for this purpose shall mean the period spent in the service of the Corporation excluding periods leave of any kind other than Casual Leave, Special Casual Leave and Quarantine Leave. The maximum period of earned leave which can be accumulated by any employee shall be 180 days. Leave upto a maximum of 120 days can be sanctioned at any one time.
- (2) The competent authority may compel any employee who has not availed himself of any earned leave for a continuous period of 36 months to proceed on such earned leave for such period as may be specified by the competent authority and not exceeding 30 days.
- (3) An employee on earned leave shall during the period of earned leave draw leave salary equal to the pay drawn on the day proceeding the day on which he proceeded on leave and allowances, other than conveyance allowance, appropriate thereto.
- 26. Sick Leave: (1) An employee shall be eligible for sick leave on medical certificate at the rate of 30 days for each completed year of service subject to a maximum of 24 months throughout his service with the Corporation. "Medical Certificate" for this purpose shall mean a certificate issued by the authorized medical attendant under the provisions regulating the reimbursement of medical attendance charges for employees.

Provided that, the competent authority before sanctioning such leave may require the employee to obtain a certificate from such other medical practitioners being a practitioner in the service of the Central or State Government or the Corporation, as it may specify.

- (2) No employee who has been sanctioned sick leave shall be permitted to rejoin duty without obtaining a fitness certificate from the authorized medical attendant or where the competent authority so requires from a medical practitioner of the description specified in the proviso to the preceding regulation.
- (3) (a) An employee during the period of sick leave shall be eligible to draw leave salary at one half of the pay drawn on the duty preceeding the day on which he proceeds on leave and such Dearness Allowance as is appropriate to such half pay. An employee on Sick Leave shall be eligible to draw House Rent and Compensatory Allowances, for a period not exceeding 120 days, at the same rate at which he was drawing these allowances before he proceeded on Sick Leave.

Provided that, Managing Director may relax the limit of 120 days in the case of employees undergoing prolonged medical treatment.

- (b) Drawal of these allowances during the period of Sick Leave in excess of 120 days shall be subject to furnishing such certificates as may be prescribed by the Managing Director from time to time.
- (c) An employee will not be eligible to draw conveyance allowance during the period of Sick Leave.
- (d) Any period of Sick Leave on half pay may be commuted into Sick Leave on full pay for half the period at the option of the employee and twice the amount of leave so commuted shall be debited against the Sick Leave account.

- 27. Maternity Leave: (1) Maternity leave may be granted to a female employee appointed in the service of the Corporation under clause (1) of Regulation 7 for a period which may extend upto 3 months from the date of its commencement or upto the end of 6 weeks from the date of confinement whichever is earlier, provided that such leave shall not exceed 12 months during the entireperiod of an employee's service.
 - NOTE: "Maternity leave may also be granted on the production of a medical certificate to a female employee upto six weeks in case of miscarriage including abortion."
- (2) An employee on maternity leave shall draw leave salary equal to the pay she drew on the day preceding that on which she proceeded on such leave, and allowances other than conveyance allowance appropriate thereto.
- 28. Extraordinary Leave: (1) An employee may be granted extraordinary leave in special circumstances when no other leave is admissible or when other leave being admissible the employee applies for the grant of extraordinary leave.
- (2) (a) An employee on extraordinary leave shall not be eligible to draw leave salary, deanress allowance or conveyance allowance. He shall however, be eligible to draw House Rent and Compensatory Allowances, for a period not exceeding 120 days, at the same rate at which he was drawing these allowances before he proceeded on leave.

Provided that, Managing Director may relax the limit of 120 days in the case of employees undergoing prolonged medical treatment.

- (b) Drawal of these allowances during the period of extraordinary leave in excess of 120 days shall be subject to furnishing such certificates as may be prescribed by the Managing Director from time to time.
- 29. Competent Authority: The Corporation may from time to time prescribe the competent authorities for grant of various kinds of leave and for the exercise of other powers in this chapter in respect of employees of different categories.
- 30. Joining Time: (1) Joining time may be granted to an employee to enable him:
 - (a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post; or
 - (b) to join a new post on return from leave.
- (2) Joining time shall be regarded as duty for the purpose of these regulations.
- (3) When the appointment to a new post does not involve a change of residence from one station to another, the joining time should not exceed one day. A holiday counts as a day for the purpose of this clause.
- (4) For transfers involving change of station, 6 days are allowed for preparation and in addition a period to cover the actual journey calculated as follows:—
 - (a) an employee is allowed:
 - (I) for the portion of the journey which he travels by aircraft.

 Actual time taken for the journey.
 - (ii) for the portion of the journey which he travels or might travel;

One day for each

By railway	500 kms	ገ
By ocean steamer	550 kms	or any longer time
By river steamer	150 kms	actually taken for
By motor vehicle	150 kms	(the journey.
or horse drawn conveyance		
In any other way	25 kms	1

- (b) (i) For purposes of journey by air under clause (a) (i) a part of a day shall be treated as one day.
- (ii) A day is also allowance for any fractional portion of any distance prescribed in clause (a) (ii).
 - (c) Travel by road not exceeding eight kilometres to or from a Ranway station or steamer ghat at the beginning or end of a journey does not count for joining time.
 - (d) Sunday does not count as a day for the purpose of the calculation in this clause.
 - (c) When the day immediately following the day on which the joining time expires is a holiday or one of a series of holidays, the employees may report for duty on the day following such holiday or series of holidays.
- (5) Joining time may be curtailed/extended at the discretion of the authority competent to transfer an employee for icasons to be recorded in writing.
- (6) Over-stayal of joining time:

An employee who does not join in his new post within his joining time is not entitled to any pay or leave salary after the end of joining time. An employee wilfully absenting himself from duty after the expiry of joining time shall be liable to disciplinary action under these regulations.

SECTION-4

CONDUCT REGULATIONS

- 31. General: Every employee shall at all times:-
 - (a) maintain absolute integrity;
 - (b) maintain devotion to duty;
 - (c) conform to and abide by the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder:
 - (d) comply with and obey all lawful orders and directions which may from time to time be issued to him in the course of his official duties by any person or persons to whom he may be subordinate in the service of the Corporation.
- 32. Every employee shall serve the Corporation honestly and faithfully and shall endeavour his utmost to promote and interest of the Corporation. He shall show courtesy and attention in all transactions and not do anything which is unbecoming of a Corporation employee.
- 33. Employment of near relatives of employees in private firms enjoying Corporation's patronage: (1) No employee shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any private business house/firm (herein-after called "firm") where he has official dealings.
- (2) (i) No Category I Officer shall, except with the previous sanction of the Corporation permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any private firm with which he has official dealings or in any other firm having official dealings with the Corporation.

Provided that, where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the Corporation or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the Corporation; and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Corporation.

(ii) An employee shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any private firm, intimate such acceptance to the Corporation and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with that firm,

Provided that, no such intimation shall be necessed. In the case of Category I officer if he has already obtained the sanction of, or sent a report to, the Corporation under clause (1)

- (3) No employee shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any firm or any other person if any member of his family is employed in that firm or under that person or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the employee shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.
- 34. Taking part in politics: (i) No employee shall be a member of or otherwise be associated with, any political party or any organization which takes part in politics, nor shall be take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.
- (ii) It shall be the duty of every employee to prevent any member of his tamily from taking part in, subscribing in aid of, assisting in any other manner, any movement or activity which, is, or tends directly or indirectly to be subversive of the Corporation or of the Government as by law established. Where an employee is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in aid of or assisting in any other manner any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the Corporation.

Explanation: If any question arises whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics, whether any movement or activity falls within scope of sub-paragraphs (i) and (ii) above, the decision of the Managing Director thereon shall be final

- 35. Taking part in elections: No employee shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in an election to any legislature or local authority, provided that:
 - (i) an employee qualified to vote at such an election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;
 - (ii) an employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this paragraph by reason only that he assists in the conduct of an election in due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation: The display by an employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this regulation.

36. Joining of associations by employees of the Corporation: No employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignity and integrity of India or to the interests of the Corporation or to public order or morality.

Provided that, the Associations/Union recognised by the Management either on de jure or de facto basis would not attract the above provision.

- 37. Demonstrations and strikes: No employee shall:-
 - (i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests and the sovereignity and integrity of India, the security of the State, the interests of the Corporation, friendly relations with foreign States,

- public order, decency or morality or which involves contempt or court, defamation or incitment to an offence of,
- (ii) resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other employee or employees of the Corporation.
- 38. Connection with Press or Radio: (i) No employee shall, except with the previous sanction of the Managing Director, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication.
- (ii) No employee shall, except with the previous sanction of the competent authority or excess in the bona fide discharge of his duties:—
 - (a) publish a book himself or through a publisher, or contribute an article to a book or a compilation of articles, or
 - (b) participate in radio broadcast or contribute an article or write a letter to a newspaper or periodical either in his own name or anonymously or pseudonymously or in the name of any other person.

Provided that, no such sanction shall be required:

- If such publication is through a publisher and is of a purely literary artistic or scientific character; or
- (ii) if such contribution, broadcast or writing is of a purely literary, artistic or scientific character.
- 39. Criticism of Government or the Corporation: No employee shall, in any radio broadcast or in any document published in his own name or anoymously pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the Press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion:—
 - which has the effect of an adverse eriticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government or of the Corporation;
 - (ii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any State or between the Central or any State Government and the Corporation;
 - (iii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign State;
 - Provided that, nothing in this regulation shall apply to any statement made or views expressed by an employee in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.
- 40. Evidence before a Committee or any other authority: (i) Save as provided in sub-para (iii), no employee shall, except with the previous sanction of the Managing Director, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority;
- (ii) Where any sanction has been accorded under sub-para (i), no employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government or of the Corporation;
 - (iii) Nothing in this regulation shall apply to :-
 - (a) evidence given at an enquiry before an authority appointed by the Central Government, Parliament or a State Legislature or the Corporation;
 - (b) evidence given in any judicial enquiry; or

- (c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities subordinate to the Government or the Corporation.
- 41. Unauthorised communication of information: No employee shall, except in accordance with any general or special order of the Corporation or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or information to any other employee of the Corporation or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

Explanation: Quotation by an employee (in his representations to the superior authority) of or from any letter, circular, Memoradum or from the notes on any file, to which he is not authority to have an access or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this regulation.

- 42. Subscriptions: No employee shall, except with the previous sanction of the Managing Director, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.
- 43. Gifts: (i) Save as provided in these regulations, no employee shall accept, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to accept any gift.

Explanation: The expression 'gift' shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the employee.

- Note (1) A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.
- Note (2) An employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual having official dealings with him or from industrial or commercial firms, organizations, etc.
- (ii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals, or religious functions, when the making of a gift is in conformity with the prevailling religious or social practice, an employee may accept gifts from his near relatives, but he shall make a report to the Corporation if the value of any such gift exceeds:
 - (a) Rs. 500 in the case of an employee holding any Category I or Category II post;
 - (b) Rs. 250 in the case of an employee holding any Category III post; and
 - (c) Rs. 100 in the case of an employee holding any Category IV post.
- (iii) On such occasions as are specified in sub-para (ii), an employee may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report to the Corporation if the value of the gift exceeds:—
 - (a) Rs. 200 in the case of an employee any Category I or Category II posts;
 - (b) Rs. 100 in the case of an employee holding any Category III post;
 - (c) Rs. 50 in the case of an employee holding any Category IV post.

- (iv) In any other case, an employee shall not accept any gift without the sanction of the Managing Director in the value thereof exceeds:—
 - (a) Rs. 75 in the case of an employed holding any Category I or Catgory II post, and
 - (b) Rs. 25 in the case of an employee holding any Category III or Category IV post.
- 44. Public demonstration in honour of Corporation employees: No employee shall, except with the previous sanction of the Corporation, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employee:

Provided that, nothing in this regulation shall apply to:—

- (i) a farewell entertainment of substantially private and informal character held in honour of an employee or any other employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of Corporation; or
- (ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainments arranged by public bodies or institutions.

NOTE—Exercise of pressure or influence of any sort on any employee to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantially private or informal character, and the collection of subscriptions from Category III or Category IV employees under any circumstances for the entertainment of any employee not belonging to category III or category IV, is forbidden.

45. Private trade or employment: (i) No employee shall, except with the previous sanction of the Managing Director, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment:

Provided that, an employee may, without such sanction, undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer; but he shall not undertake, or shall discontinue, such work if so directed by the Managing Director.

- Explanation: Canvassing by an employee in support of the business, insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this regulation.
- (ii) Every employee shall report to the Corporation if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency. He shall make a report to the prescribed authority of the employment of any member of his family in any organization/company or concern enjoying the patronage of the Corporation at the time of appointment of the member of the family.
- (iii) No employee shall, without the previous sanction of the Managing Director, except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any Co-operative Society for commercial purposes:

Provided that, an employee of the Corporation may take part in the registration, promotion or management of a Co-operative Society substantially for the benefit of the employees of the Corporation, registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force, or of a literary, scienti-

- fic or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any corresponding law in force.
- (iv) No employee may accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Managing Director.
- 46. Investment, lending and borrowing: (i) No employee shall speculate in any stock, share or other investment.
 - Explanation: Frequent purchase or sale or both of shares, securities or other, investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule.
- (ii) No employee shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties.
- (iii) If any question arises whether any transaction is of the nature referred to in sub-para (i) or (ii), the decision of the Managing Director thereon shall be final.
- (iv) No employee shall save in the ordinary course of business with a bank or a public limited company, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf:—
 - (a) lend or borrow or deposit money as a principal or an agent, to, or from or with any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealing or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person or firm or private limited company; or
 - (b) lend money to any person at interest or in a manned whereby return in money or in kind is charged or paid:
 - Provided that, an employee may give to or accept from, a relative or a personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a hona-fide tradesman or make an advance of pay to his private employee.
 - Provided further that nothing contained in this sub-regulation shall apply in respect of any transaction entered into by an employee with the previous sanction of the Corporation.
- (v) When an employee is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of sub-regulation (ii) or sub-regulation (iv) he shall forthwith report the circumstances to the competent authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be made by such authority.
- 47. Insolvency and habitual indebtedness: An employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. An employee against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the legal proceeding to the Corporation.
- Nate: The burden of proving that the insolvency or indebtedness was the result of circumstances which, with the exercise of ordinary diligence, the employee could not have foreseen, or ever which he had no control, and had not proceeded from extravagent or dissipated habits, shall be upon the employee.
- 48. Movable, Immovable and valuable property; (i) Fvery employee shall, on his first appointment and thereafter before the 31st January of every year, submit to the competent authority a return in the form given in Appen-

- dix 4 of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person who is dependent on him.
- (ii) The competent authority may also require an employee, on his first appointment and thereafter at such intervals as may be specified, to submit a return giving full particulars regarding:—
 - (a) shares, debentures and cash, including bank deposits inherited by him or similarly owned, acquired or held by him;
 - (b) other movable property inherited by him or similarly owned acquired or held by him; and
 - (c) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly.
 - Note: In all returns, the value of items of movable property worth less than Rs. 1.000 may be added and shown as a lump sum. The value of articles of daily use such as clothes, utensils, crockery, books, etc., need not be included in such return.
- (iii) No employee shall, except with the previous knowledge of the competent authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family.

Provided that, the previous sanction of the competent authority shall be obtained by the employee if any such transaction is:—

- (a) with a person having official dealings with the Corporation or the employee, or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.
- (iv) Every employee shall report to the competent authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family, if the value of such property exceeds Rs. 1,000/- in the case of an employee holding any Category I or Category II post, or Rs. 500/- in the case of an employee holding any Category III or Category IV post:

Provided that, the previous sanction of the competent authority shall be obtained if any such transaction is:—

- (a) with a person having official dealings with the employee; or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.
- (v) The Corporation or the competent authority may, at any time, by general or special order, require an employee of the Corporation to furnish, within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family, as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the Corporation or by the competent authority, include the details of the means by which, or the source from which, such property was acquired.

Explanation: For the purposes of this regulation the expression "movable property" includes:—

- (a) Jewellery, insurance policies the annual premia of which exceeds Rs. 1.000/- or one sixth of the total annual emoluments received from the Corporation, whichever is less, shares, securities and debentures;
- (b) loans advanced by such employees whether secured or not;
- (c) motor cars, motor cycles, horses, or any other means of conveyance; and

- (d) refrigerators, radios, radiograms, taperecorders and television sets.
- 49. Vindication of acts and character of Corporation employees: (1) No employee shall, except with the previous sanction of the Managing Director, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.
- (ii) Nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the employee shall submit a report to the competent authority regarding such action.
- 50. Canvassing of non-official or other inflence: No employee shall bring or attempt to bring any political personal or other influence to bear upon any authority of the Corporation to further his interests or the interests of any other person in respect of matters pertaining to his service or the service of such other person, or in respect of any other matter involving a pecuniary or other benefit to him or to such other person.
- 51. Bigamous marriages: (i) No employee shall enter into, or contract, a marriage with a person having a snouse living and (ii) no employee, having a spouses living, shall enter into or contract a marriage with any person.

Provided that, the Corporation may permit an employee to enter into, or contract, any such marriage as is referred to in sub-regulation (i) or sub-regulation (ii) if it is satisfied that—

- (a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and
- (b) there are other grounds for doing so.
- 52. Consumption of intoxicating Drinks and Drugs: An employee shall—
 - (a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being:
 - (b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duties and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug;
 - (c) not appear in a public place in a state of intoxication;
 - (d) not use in excess any intoxicating drink or drug.
 - 53. Definitions: For the purposes of this Section:
 - (a) 'members of family' in relation to an employee shall include—
- (i) wife or husband, as the case may be, of the employee, whether residing with the employee or not, but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the employee by a decree or order of a competent court;
- (ii) son or daughter or step-son or step-daughter of the employee and wholly dependent on him, but does not include a child or step-child who is no longer in any way dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived by or under any law;

- (iii) any other person related by blood or marriage to an employee or his wife or her husband and wholly dependent upon such employee;
- (iv) competent authority for the purpose of conduct regulations shall be such an authority as may be specified by the Managing Director from time to time.

SECTION 5

DISCIPLINE AND APPEAL REGULATIONS

54. Penalties: Notwithstanding anything contained in any other regulation, and without prejudice to such action to which an employee may become liable under any other regulation or law for the time being in force, the following penalties may for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed on any employee of the Corporation.

Minor Penalties:

- (i) censure;
- (ii) withholding of his promotion;;
- (iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Corporation by negligence or breach of orders;
- (iv) withholding of increments of pay.

Major Penalties;

- (v) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee of the Corporation will carn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vi) reduction to a lower time-scale of pay or post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee to the time-scale of pay or post from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the post from which the employee of the Corporation was reduced and his seniority and pay on such restoration to that post;
- (vii) compulsory retirement;
- (viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Corporation;
- (ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Corporation.

Explanation: The following shall not constitute a penalty within the meaning of this regulation:

- (a) discharge of an employee for failure to pass any examination or test or a medical test prescribed for fresh appointment to any category of post;
- (b) compulsory retirement of an employee in accordance with the provision relating to superannuation or retirement;
- (c) termination of service or reversion to a lower category or post of an employee appointed or promoted on probation either during or at the end of the period of probation;
- (d) discharge of an employee under regulation 19 or as a measure of retrenchment for want of vacancy;
- (e) termination of service of an employee employed under a contract or agreement in accordance

- with the terms of such contract or agreement or in the case of an employee appointed for a specific period, at the end of such period;
- (f) reversion of an employee promoted from n lower post to a higher post, to such lower post for want of vacancy;
- (g) non-promotion of an employee after consideration of his case for promotion whether on a regular or on ad-hoc basis to a post to which he is eligible for being considered;
- (h) replacement of the services of an employee whose services had been borrowed at the disposal of his parent organisation.
- 55. Provisions regarding transferred employees: Disciplinary proceedings under these regulations may also be initiated against a transferred employee, in respect of any act or omission, pertaining to the period of service rendered in the Department of the Central Government dealing with Food or in any of its subordinate or attached offices, before his transfer to the Corporation, if such act or omission amounted to a contravention of any of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 at if it were a contravention of these Regulations.
- 56. Disciplinary Authorities: The Board or the authority specified in Appendix 2 in this behalf or any other authority (higher than the authority specified on Appendix 2) empowered in this behalf by a general or social order of the Board, may impose any of the penalties specified in Regulation 54 on any employee,
- 57. Authority to institute proceedings: (1) The Board or any other authority empowered by it by general or special order may
 - (a) institute disciplinary proceedings against any employee of the Corporation;
 - (b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any employee of the Corporation on whom that disciplinary authority is competent to impose under these regulations any of the penalties specified in regulation 54.
- (2) A disciplinary authority competent under these regulations to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation on 54 may institute disciplinary proceedings against any employee of the Corporation for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these regulations to impose any of the latter penalties.
- 58. Procedure for imposing major penalties: (1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 shall be made except after an inquiry held; as far as may be, in the manner provided in this regulation and regulation 59, or in the manner provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (31 of 1850), where such inquiry is held under that Act,
- (2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee of the Corporation, it may itself inquire into or appoint under this regulation or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, as the case may be, an authority to inquire into the truth thereof.

Explanation: Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-regulation (7) to sub-regulation (20) and in sub-regulation (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

- (3) Where it is proposed to hold an inquiry against an employee of the Corporation under this regulation and regulation 59, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up---
 - (i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;
 - (ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain—
 - (a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the employee;
 - (b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.
- (4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the employee to submit, with in such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.
- (5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose; and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge as it may think fit and shall act in the manner laid down in regulation 59.
- (b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it considers it necessary to do so appoint, under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose.
- (c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may, by an order, appoint an employee of the Corporation or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.
- (6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority—
 - a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
 - (ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the employee;
 - (iii) a copy of the statements of witnesses, if any. referred to in sub-regulation (3);
 - (iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-regulation (3) to the employee, and
 - (v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer",
- (7) The employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow.

- (8) The employee may take the assistance of any other employee of the Corporation or any State or Central Government employee to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.
- Note: The Corporation shall pay travelling allowance only in respect of the employees of the Corporation and not Central/State Government employees.
- (9) If the employee who has not admitted any of the articles of change in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon.
- (10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.
- (11) The inquiring authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence:
 - (i) inspect and take extract from, if desired, within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-regulation (3);
 - (ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf.
- Note: If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-regulation (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the comemnement of the examination of the witnesses on behalf of the disciplinary authority.
 - (iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of Corporation but not mentioned in the list referred to in subregulation (3).

Note: The employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Corporation.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or cooles thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the document by such date as may be specified in such requisition;

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in subregulation (12), every authority in the Corporation having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority;

Provided that if the authority having the custody requisitioned possession of the documents satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the interest of the Corporation or security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee of the Corporation and withdraw othe requisition made by it for the production or discovery of such documents,

- (14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved, shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witness as it thinks fit.
- (15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence, exclusive of the day of adjournment and the such case the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence pro-posed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the The inquiring authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note: New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

- (16) When the case for the disciplinary authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee of the Corporation shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.
- (17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself on his own behalf, if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.
- (18) The inquiring authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.
- (19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any appointed, and the employee or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

- (20) If the employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this regulation, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.
- (21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 54 | but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54| has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 should be imposed on the employee that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.
- (b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witness and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these Regulations.
- (22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as here in before provided.

- (23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—
 - (a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour:
 - (b) the defence of the employee in respect of each article of charge;
 - (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge:
 - (d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation: If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

- (ii) The inquiring authority where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—
 - (a) the report prepared by it under clause (i);

- τ(b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee;
 - (e) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
 - (d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry; and
 - (c) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.
- 59. Action on the inquiry report: (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring autohrity shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of regulation 58 as far as may be.
- (2) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the lindings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.
- (3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 54 should be imposed on the employee, it shall, notwithstanding anything contained in regulation 58, make an order imposing such penalty.
- (4) (i) It the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 should be imposed on the employee it shall—
 - (a) furnish to the employee a copy of the report of the inquiry held by it and its findings on each article of charge, or, where the inquiry has been held by an inquiring authority appointed by it, a copy of the report of such authority and a statement of its findings on each article of charge together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority;
 - (b) give the employee a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days, as may be allowed, such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the inquiry held under regulation 58.
- (ii) The disciplinary authority shall after considering the representation, if any, made by the employee determine what penalty, if any, should be imposed on the employee and make such order as it may deem fit.
- 60. Procedure for imposing minor penalties: (1) Subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 59, no order imposing on an employee any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 54 shall be made except after—
 - (a) informing the employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

- (b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-regulations (3) to (23) of regulation 58, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
- (c) taking the representation, if any, submitted by the employee under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration;
- (d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.
- (2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-regulation (1), it in a case it is proposed, after considering the representation, if any made by the employee under clause (a) of that sub-regulation, to withhold increment of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of retirement benefits payable to the employee or to withhold increments of a pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-regulations (3) to (23) of regulation 58 before making any order imposing on the employee any such penalty.
- (3) The record of the proceedings in such cases shall include—
 - (1) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him;
 - (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
 - (iii) his representation, if any;
 - (iv) the evidence produced during the inquiry;
 - (v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and
 - (vi) the orders on the case together with the reasons therefor.
- 61. Communication of order: Order made by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on each article of charge or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the inquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority (unless they have already been supplied to him),
- 62. Common Proceedings: (1) Where two or more employees of the Corporation are concerned in any case, the Board or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

Note: If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

- (2) An order under sub-regulation (1) shall specify—
 - the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;

- (ii) the penalties specified in regulation 54 which such disciplinary authority shall be competent to impose;
- (iii) whether the procedure laid down in regulation 58 and regulation 59 or regulation 60 shall be followed in the proceeding.
- 63. Special procedure in certain cases: Notwithstanding anything contained in regulation 58 to regulation 62—
 - where any penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or
 - (ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these regulations,
 - (iii) where the Board is satisfied that in the interest of security of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these regulations,

the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.

64. Provisions regarding officers lent to other Organisation: (1) Where the services of an employee of the Corporation are lent to another organisation (hereinafter in this regulation referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such employee under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the employee (hereinafter in this regulation referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

- (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the employee—
 - (i) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 54 should be imposed on the employee, it may after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 should be imposed on the employee, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry and thereupon the lending authority may, if it is the disciplinary authority, pass such orders thereon as it may deem necessary, or if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass such orders on the case as it may deem necessary;

Provided that before passing any such order the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub-regulations (3) and (4) of regulation 59.

Explanation: The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with regulation 58.

- 65. Provisions regarding officers borrowed from Central or State Governments, Government owned Organisations, Companies and Corporations: (1) Where an order of suspension is made or disciplinary proceedings are taken against a Government servant or an employee of a public sector or private sector undertaking, whose services have been borrowed from a Government or an authority subordinate thereto or such undertaking, the authority subordinate thereto or such undertaking, the authority subording his services (hereinafter in this regulation referred to as the "lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension or of the commencement of disciplinary proceeding, as the case may be.
- (2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the borrowed Government servant, employee of the public sector or private sector undertaking—
 - (i) If the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 54 should be imposed on him, it may, after consultation with the lending authority, pass such orders as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the service of the Government servant or employee of the public sector or private sector undertaking shall be replaced at the disposal of the lending authority;

- (ii) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.
- 66. Suspension: (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Board, by general or special order, may place an employee under suspension—
 - (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or
 - (b) where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or
 - (c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial:

Provided that, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

- (2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority—
 - (a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours,
 - (b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent on such conviction.

Explanation: The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-regulation shall be computed

- from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.
- (3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.
- (4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.
- (5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.
- (b) Where an employee is suspected or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him order suspension may for reasons to be recorded by him in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.
- (c) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.
- (6) An employee under suspension or deemed to have been under suspension shall be entitled to subsistence grant at one half of the pay to which he would otherwise be eligible. He is eititled to draw other compensatory allowances, e.g., compensatory (city) allowance, house rent allowance, other than conveyance allowance admissible from time to time, on the basis of pay of which he was in receipt on the date of suspension subject to the fulfilment of other conditions laid down for the drawal of such allowances. If the headquarters of an employee under suspension are changed in the public interest by order of a competent authority, he shall be entitled to the allowance as admissible at the new station provided he furnishes the requisite certificates, if any, with reference to such station:

Provided that no payment under this regulation shall be made unless the employee furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

- (7) The authority next higher to the competent authority may vary the amount of subsistence grant for any period exceeding the first twelve months, as follows:
 - (i) The amount of subsistence grant may be increased by a suitable amount, not exceeding 50% of the subsistence grant admissible during the period of the first twelve months, if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing not directly attributable to the employees;

(ii) The amount of subsistence grant may be reduced by a suitable amount, not exceeding 50% of the subsistence grant admissible during the period of the first twelve months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons to be recorded in writing directly attributable to the employees;

Note: Where the competent authority is the Board/ Executive Committee, the increase or decrease will be made by the Board/Executive Committee as the case may be.

(8) When the suspension of an employee is held to be unjustified or not wholly justified; or when an employee has been dismissed or suspended is reinstated, the disciplinary, appellate or reviewing authority, as the

the disciplinary, appellate or reviewing authority, as the case may, whose decision shall be final, may grant to him for the period of his absence from duty—

- (a) if he is honourably acquitted, the full pay and allowances other than conveyance allowance to which he would have been entitled, if he had not been dismissed or suspended, less the subsistence grant;
- (b) if otherwise, such proportion of pay and allowances other than conveyance allowance as the disciplinary, appellate or reviewing authority may prescribe. In a case falling under clause (a), the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In case falling under clause (a), the period of absence from duty will be treated as a period spent on duty. In a case falling under clause (b) it will not be treated as a period spent on duty unless the disciplinary, appellate or reviewing authority, as the case may be, whose decision shall be final, so directs.

No order passed under this regulation shall have the effect of compelling any employee to refund any part of the subsistence grant paid to him.

- 67. Appeals: Orders against which no appeal lies: Notwithstanding anything contained in these regulations, no appeal shall lie against—
 - (i) any order made by the Board;
 - (ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;
 - (iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under regulation 58.
- 68. Orders against which appeals lie: Subject to the provisions of regulation 67, an employee of the Corporation may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely:
 - (i) an order of suspension made or deemed to have been made under regulation 66;
 - (ii) an order imposing any of the penalties specified in regulation 54 whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authority;
 - (iii) an order enhancing any penalty, imposed under regulation 54;
 - (iv) an order which-
 - (a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, and other retirement benefits as regulated by regulations or by agreement; or (b) interprets to his disadvantage the provisions of any such regulation or agreement;

- (v) an order-
 - (a) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post, otherwise than as a penalty;
 - (b) reducing or withholding the terminal benefits or denying the maximum terminal benefits admissible to him under the regulations;
 - (c) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof—
 - (d) determining his pay and allowances-
 - (i) for the period of suspension, or
 - (ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a timescale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post, or
 - (e) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation: In this regulation-

- (i) the expression 'employee of the Corporation' includes a person who has ceased to be in the service of the Corporation;
- (ii) the expression 'terminal benefits' includes gratuity and any other retirement benefit,
- 69. Appellate Authorities: An appeal against an order imposing any of the penalties made by the disciplinary authority shall lie to the appellate authority specified in this behalf in Appendix 2 or to any other authority (not lower in rank than the appellate authority specified in Appendix 2) empowered in this behalf by a general or special order of the Board. In other cases, an appeal lies to the authorities next higher to the authority passing the order.
- 70. Period of limitation for appeals: No appeal preferred under these regulations shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal in time.

- 71. Form and contents of appeal: (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.
- (2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order

- appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.
- (3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.
- 72. consideration of appeal: (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of regulation 66 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.
- (2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in regulation 54 or enhancing any penalty imposed under the said regulation, the appellate authority shall consider—
 - (a) where the procedure laid down in these regulation has been complied with, and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions under these regulations or in the failure of justice;
 - (b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and
 - (c) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe; and pass orders—
 - (i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or
 - (ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case;

Provided that-

- (i) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 an inquiry under regulation 58 has not already been held in the case the appellate authority shall, subject to the provisions of regulation 63, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 58 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-regulation (4) of regulation 59, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit:
- (ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 and an inquiry under regulation 58 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may

- be in accordance with the provisions of subregulation (4) of regulation 59, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during the inquiry, make such orders as it may deem fit; and
- (iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of regulation 60, of making a representation against such enhanced penalty.
- (3) In an appeal against any other order specified in regulation 68, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.
- 73. Implementation of orders in appeal: The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.
- 74. Review: (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Corporation may, at any time, either on its own motion or otherwise, call for the records of any inquiry and review any order made under these regulations, and
 - (a) confirm modify or set aside the order; or
 - (b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or
 - (c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or
 - (d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the reviewing authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 54 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in those clauses; no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in regulation 58 and after giving a reasonable opportunity to the employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry.

- (2) No proceeding for review shall be commenced until after;
 - (i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or
 - (ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.
- (3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations.
- (4) Powers similar to those specified in clause (1) above may be exercised by the Managing Director, Zonal Manager and Regional Manager (Additional/Joint Manager) in respect of orders passed by authorities subordinate to them,

- 75. Miscellaneous: Service of orders, notices, etc.: Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post.
- 76. Power to relax time-limit and to condone delay: Save as otherwise expressly provided in these regulations and authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.

Section 6

- 77. Scales of pay: The scales of pay applicable to the various categories of posts in the Corporation are set out in column 3 of the table in Appendix 1.
- 78. Allowances and Advances: The Corporation may prescribe from time to time:
 - The rates at which and the conditions subject to which travelling allowance may be paid to the employees in connection with journeys undertaken by them on tour or transfer in the service of the Corporation;
 - (ii) The rates at which and the conditions subject to which conveyance allowance may be paid to the employees for the maintenance of different types of conveyance for use on official duties;
 - (iii) The kinds and rates of any other allowances and the terms and conditions on which such allowances may be granted;
 - (iv) The rates at which and the conditions subject to which medical charges and insurance premia may be reimbursed to the employees of the Corporation; and
 - (v) The types of advances that may be granted to the employees and the terms and conditions on which such advances may be granted.
- 79. Commencement and cessation of pay: An employee shall commence to draw the pay of the post to which he is appointed and the allowances applicable thereto from the date he assumes charge of the post if such charge is assumed in the forenoon and from the following day if the charge is assumed in the afternoon and shall cease to draw the same from the day he relinquishes charge if the charge is relinquished in the forenoon and from the following day if the charge is relinquished in the afternoon.

Provided that in the case of an employee who dies while in service, pay shall cease to be payable with effect from the day subsequent to that on which the death occurs.

80. Pay during joining time: Where an employee is transferred from one post to another, he shall during the period intervening, the date of his handing over charge of the old post and the date of his taking over charge of the new post, draw pay and allowances pertaining to the old post or the pay and allowances pertaining to the new post, whichever is less.

Explanation: The above regulation shall also apply to a deputationist while joining the services of the Corporation or while being reverted to his parent department.

81. Pay on first appointment: The pay of an employee on first appointment to a post in the service of the Corporation shall be fixed at the minimum of the time scale applicable to the post to which he is appointed, or where the post is on a fixed pay, such fixed pay:

Provided that where any person appointed to a post to which a time-scale is applicable has been in continuous service for a period of not less than 2 years in any Department of the Central or any State Government or any Public Sector or Private Sector Undertaking immediately preceding such appointment, the appointing authority may in its discretion fix the pay at the stage in the time-scale applicable to the pay of the post next higher than the pay last drawn by him in such department or undertaking and may in addition, in his discretion, grant one advance increment.

Provided further that the Managing Director may grant a higher start to a direct recruit up to a maximum of five advance increments in consultation with the Financial Adviser; and Executive Committee may grant advance increments in excess of the above limit,

Provided also that in no case shall the pay be fixed at a stage higher than the maximum of the time-scale.

82. Pay on promotion: (1) When an employee of the Corporation is promoted from one post to a higher post in the service of the Corporation, his pay in such higher post shall be fixed at the next higher stage after allowing him one increment in the scale of pay, if any, applicable to the post from which he has been promoted.

Provided that where an employee is promoted to a post on a fixed pay, he shall be allowed only such fixed pay.

- (2) When an employee is specifically required by the competent authority to hold charge of a higher post in addition to his own duties, he shall be cligible to draw charge allowance in accordance with the instructions issued by the Corporation from time to time.
- 83. Pay in the case of deputationists from Central/State Government Departments or Public Sector Undertakings: The pay of a deputationist shall be regulated in accordance with his terms of deputation, as mutually agreed upon between the lending authority and the Corporation subject to the condition that in no case should the benefit accruing to a deputationist exceed the limits prescribed by the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. 10(24)-E.III/60, dated 4-5-61, as amended from time to time,
- 84. Pay and allowances in the case of deputationists from Private Sector Undertakings: Except where otherwise specified by Managing Director, the pay of deputationists from private sector undertakings shall be fixed in accordance with regulation 83.
- 85. Pay in the case of superannuated Government servants re-employed by Corporation: In the case of persons who have been superannuated from the service

of the Central or any State Government and have been re-employed in the service of the Corporation, the pay shall be regulated in accordance with the principles applicable to similar appointments in the Civil Departments of the Central Government. Annual increments in such cases shall be drawn on completion of the year of service in the Corporation.

86. Increments: Increments in the time-scale of a post to which a person is appointed shall be drawn as a matter of course except where such increments have been withheld as a result of a penalty imposed under those regulations. All increments shall fall due on the first of January of every year provided that where an employee has not completed six months of service on that date, the increment shall fall due only on the first of July, following.

Explanation: All service in the Corporation in equivalent or higher posts counts for increments.

- 87. Ad-hoc increment to employees stagnating at the maximum of their pay scale: An employee in category III or IV who has been stagnating or may hereafter stagnate at the maximum of his scale of pay for 2 years or more may be granted an ad-hoc increment equivalent to the rate of the increment last drawn by him in his existing scale. An employee against whom a disciplinary case is pending will, however, have to await the result of the pending disciplinary proceedings before being considered for the grant of such ad-hoc increment.
- 88. Ex-gratic grant: In the event of death of an employee in extra-ordinary tragic circumstances, the Managing Director may sanction, in accordance with such rules as may be framed by the Board in that behalf, an ex-gratia grant to the family members dependent on the employee if no terminal benefits/compensation is admissible under normal Rules.
- 89. Saving provisions: Nothing contained in these Regulations shall affect the application of any other law, rule or regulation for the time being in force.
- 90. Nothing contained in these Regulations shall invalidate any order made or action taken by the Corporation or any of its officers in accordance with the provisions contained in the draft Staff Regulations which were in force before the commencement of these Regulations.
- 91. Interpretation: If any doubt or difficulty arises in interpreting these Regulations, or in giving effect to them, or if any lacuna, inconsistency or anomaly is discovered in their application, it shall be open to the Board to issue general instructions not inconsistent with the Act, and the rules and regulations made thereunder for the purpose of removing such doubt, difficulty, lacuna, inconsistency or anomaly.

I. S. KANSAL

Jt. Personnel Manager, Food Corporation of India, New Delhi-1.

APPENDIX—I

STATEMENT SHOWING THE VARIOUS CATEGORIES OF POSTS, SCALES OF PAY, MODE OF RECRUITMENT ETC.

IN THE FOOD CORPORATION OF INDIA

SĮ.	Description of post	Scale of pay	Mode of recruitment	Pron	notion	Direct recruitment	Age limit	Correspond-	(10)
No.				Selection/non Experience selection.		Qualifications and experience, if any.	шш	ing cate- gories of posts in the Direc- torate General of Food.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	·				PART—I——SPECIA	L POSTS			
I.	Financial Adviser	2500-100-300	Transfer on deputation / direct recruitment/promotion. Mode of recruitment to be determined on each occasion as vacancy in the post arises.	Selection F.A.	7 years as Deputy F.A.	To be prescribed by the Chairman.	45 years		_
2.	Zonal Manager	Do.	Do.	Do.	7 years as Manager.	Do.	Do.		
3.	Commercial Manager .	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.		-
4.	Personnel Manager	2000-100-2500	Do.	Do.	5 years as Manager	Do.	Do.		-
5.	Manager (Quality control	1600-100-2000	Mode of recruit- ment to be deter- mined on each oc- casion as vacancy in the post arises.	Do.	Do.	Essential- (i) Master's degree in Zoology (with Entomology) Agrl. or Biochem. of a recognised University or equivalent qualification.	30-40 years		
						(ii) Adequate knowledge of classification and grading of foodgra- ins, their sampling and analysis.			
						(iii) About 7 years' practical experience in maintenance of quality of large stocks of foodgra- ains (including storage and inspec-			

(10)

surveys in a senior responsible capacity in a Government Department and/or a Commercial/Public Sector undertaking operating on a country-wide basis or of conducting and guiding research in these fields

					Familiarity with the application of operations research techniques and business economics.			
8. Manager (Engineering)	1600-100-2000	Refer to Item No. 1	of Part-JX	of the Appendix-1				
9. Manager/Deputy Zonal Manager.	1600-100-2000	50% by promotion from Joint Mana- gers' Grade and 50% by transfer on deputation, failing which direct recruit- ment.	Selection	5 years service in the lower grade.	To be prescribed by the Chairman.	40 years.	Regional Director (Food).	
		PART	IIGENE	ERAL ADMINISTRATION	CADRE			
ATEGORY II POSTS:								
1. Joint Manager	1100-50-1300-60 1600	66 2/3% by promotion from the grade of Senior Deputy Manager, General Admn./ Technical Movement/Planning & Research Cadres. 33 1/3% by trans-	Selection	3 years service in the grade of Senior Deputy Manager, General Administration/Technical/Movement/Planning & Research cadres.	_	_	Director	
		fer on deputa- tion, failing which by direct recruit- ment.						
2. Senior Deputy Manager.	900-50-1400	100% promotion from the grade of Deputy Mana- ger (General Administration.)	Selection	3 years' service in the grade of Deputy Manager (General Admn.)	_	_	Joint Director.	
3. Deputy Manager	700-50-1250	Direct 25%	_	_	Graduate; Diploma in Business Management 5 years experience in Food & allied fields	*35 years	Deputy Director.	*Relaxable in the case of employees of the Corporation.
		Promotion 75% (from Sr. Asstt. Managers)	Selection	3 years as Sr. Assistant Manager.	_		_	

a University or Institution of training or research as evidenced by published work.

Desirabe-

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Senior Assistant Manager	. 400-40-800-50- 950. 1	Direct 50%			Graduates; 4 years experience in Food & allied fields.	*32 years	Assistant Director.	*Relaxable in the case of employees of the Corporation.
		Promotion from A. M. (General Admn./ Godown) 50%-	Selection	3 years in the grade of Assistant Manager (Genl. Admn/Godown.)	~	^	-	à
CATEGORY-II POSTS								
5. Assistant Manager	350-25-500-30- 620-40-700.	Promotion 100%	Selection .	3 years as Assistant Grade-I (Genl. Admn.) / Stenographer Gr. I	-	_	Office Superintende	nts.
CATEGORY-III POSTS								
6. Assistant Grade-I	225-10-235-15- 430-20-550.	Promotion 100% N failing which direct recruitment.	Ion-Selection	3 years in the grade of Asstt. Grade-II/ Telex operator.	Graduate, 7 years experience in any office.	31 years	Assistant Superintendents, Accountants	Relaxable in the case of employees of the Corporation.
7. Assistant Grade-II	150-10-300	Promotion 100% failing which direct recruitment.	Non-Selection	3 years experience as Assistant Grade- III/Typists/Telephon operator.	Graduate +4 years experience in any office e	*28 years	Sr. Clerks, Deputy Accountants.	*Do,
8. Telex Operator	150-10-300	By transfer from the Grade of AG-II knowing typing on a tenure basis.	_	_		_	Telex Operator	–
9. Assistant Grade-III	120-10-240	Direct 90% Promotion 10% from Matricu- late Cat-IV employees with 3 years experi- ence.	ı —	_	Graduate	*24 years	Jr. Clerks. (who do not know the typing), Comptomete Operator.	*Do.
10. Telephone Operator	120-10-240	Direct Recruitment	` —	_	Matriculate with ex- perience as Telephone Operator for one year, preference be- ing given to lady candidates.	25 years	Telephone Operator.	
11. Typists	120-10-240	Direct 90%		_	Matriculate with a * speed of 40 w.p.m. in typewriting.	24 years	Jr. Clerks who know typing.	•Do.

		Promotion 10% from Matriculate Category-IV employees with 3 years experience and who possess the requisite typing speed.	Non-selection					:
PERSONAL STAFF:								
12. Personal Secretary	400-40-800- 50-950	_	To be determined	on each occasion as a	and when a vacancy arises.			
13. Steno Grade-I	225-10-235-15- 430-20-550.	Promotion 100% failing which direct recruitment.	Non-selection	speed 40 words and 120 words in	Matriculation with a speed of 40 and 120 words per minute in typewriting and shorthand respectively.	*25 years.	Sr. Steno- graphers.	*Relaxable in the case of employees of the Corpn.
14. Steno Grade II • •	150-10-300.	Promotion of typists, failing which direct recruitment.	Do.	speed 40 w.p.m. and shorthand	Matriculation with a a speed of 40 & 80 w.p. m. in typewriting and shorthand respectively.	*24 years.	Stenograph- er/Steno- typist,	*Do.
CATEGORY-IV POSTS	•		-					
I. Gesteiner Operator	Rs. 100-5-130	100% promotion failing which direct recruitment.	Do.	and qualification to operate a	Middle Standard pass and qualifi- cation to operate a Gestetner Machine.	28 years.	Gestetner Operator	_
2. Daftry	85-2-95-3-110	100% promotion	Do.	3 years as Peon.	_	_	Daftry	_
3. Peon	80-2-100	100% direct rect.	_	- .	Middle Standard pass.	25 years	Peon	
 Watchman (Chowkidar in offices). 	Recruitment	rules will be same as in	n the case of Wate	hman in Godown; the	y will be considered for prot	motion also a	long with Wa	tchmen in Godowns.
5. Picker	100-5-130	100% promotion	Non-selection	3 years as Sticher/ Dusting Operator/ head Watchman.	- •		Picker	_
6. Head Watchman	85-2-95-3-110	100% promotion	Do.	3 years as Watchman.	_	_	Head Watchman.	_
7. Dusting Operator	Do.	Do.	· Do.	3 years as Sifter/ Watchman/Sweeper.	Middle Standard Pass	25 years	Dusting Operator	Only literate. Sifter/Watchmen/Sweeper will be eligible for promotion. In case literate Sif- ter/Watchmen Sweeper i.e. those who are able to

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									read and writes instructions gives to the even in the local language are not available for promotion, the possiball be filled to direct recruitment.
8.	Stitcher	Do.	Do.	Do.	Do.	Middle Standard Pass	Do.	Stitcher	Do.
9.	Watchman (Godown) .	80-2-100	100% direct recruitment.		_	Do.	25 years	Watchman	_
	Sifter	Do.	Do.	_	_	Do.	Do.	Sifter	_
10. 11.	Labourer	Do.	Do.	_	~	Should be able to read and write in any language.	Do.	Labour/ Ckaning Gang.	-
12.	Sweeper	Do.	Do.		_	Do.	Do.	Sweeper	_
	EGORY —II POSTS Assistant Manager (De-	350-25-500-30-	PART- Promotion 100%	-IIIGOI Selection	DOWN CADRE 3 years as Assistant	_	_	Godown	-
	pot) (Godown/Dock Sup- dt.)	620-40-700.			Gr-I (Depot)			Supdt/Dock Supdt/Watch & Ward Ins- pector/Chief Verification Inspector.	
2.	Chief Labour Inspector .	350-25-500-3 0 - 620-40-700.	50% promotion	Do.	3 years as Labour Inspector	_	_	Chief Inspecto (Labour).	or —
			50% direct recruitment.	_	_	Degree from a recognised University preferably with Social Service or Diploma in Social Service/Social Welfare of a Recognised Institution.	*25 years.	_	*Relaxable in the case of employed of the Corportion.
						Experience. 2 years in Labour Welfare work or Social Service.			
CAT	EGORY-III POSTS								
3.	Labour Inspector	225-10-235-15- 430-20-550.	100% direct recruit- ment.	_	_	Degree or equivalent. Experience. 3 years in Labour Welfare	*25 years.	Inspector (Labour).	*Do.

4.	Assistant-Gr-I (Depot)	225-10-235-15- 430-20-550	Promotion 100%	Non-selection	3 years as AG-II (Depot)		_	Si. Godown Keeper/Ins- pector (FPS)/ Dock Inspec- tor/Veri. Insp./ Watch & Ward Sub- Inspector/ Inspector (Food).	*	PART III—SEC. 4]
5.	Assistant Gr. II (Depot) .	150-10-300	Promotion 100%	Do.	3 years as AG-III (Depot)	_	_	Junior Godown Keeper/Shed Supervisor.		THE
6.	Assistant Gr. III (Depot)	120-10-240	Promotion of Shed Tallymen taken over from Food Deptt. failing which:		_	-	_	Godown Clerk		GAZETTE
			Direct 90%	_	~	Graduate	*24 years	-	*D o.	OF
	•		Promotion 10% from Cat, IV employees who are matriculates.	Non-selection	3 years experience in Cat. IV	_	_		-	F INDIA,
7. 3	Shed Tallyman	120-5-150	Absorption of Shed Tallymen of Food Department.	·						MAY 8,
				PART IV—	-TECHNICAL CAD	PRE				, 1971
CAT	TEGORY -I POSTS									1
1.	Senior Deputy Manager (Tech.)	900-50-1400	100% Promotion	Selection	3 years as Deputy Manager (Technical).	_	_			(VAISAKH
2.	Deputy Manager	700-50-1250	Direct 25%	_	_	Essential			•	KH
	(Technical).					 (i) Degree in Agriculture or degree in Science with diploma in Food Technology or Masters Degree in Zoology or Biochemistry, or equivalent qualicfications. (ii) 5 years experience in storage of foodgrains 		Deputy Director (Tech.).	Relaxable in case of Corporation employee.	(A 18, 1893)
						and maintenance of stocks or in the examination,	;			1249

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						inspection and analysis of foodgrains in Government or Public/Private Ltd. undertakings.			
				,		Desirable: Knowledge of toxicology or insecticides, raticides and furnigants in use in grains stocks.			
			Promotion 75%	Selection	3 years in the Gd. of of SAM (Tech.).	_	_	-	
3.	Senior Assistant Manager (Tech.).	400-40-800-50- 950.	Promotion 100%	Selection	3 years in the Gd, of AM (Tech.).	_		Asstt. Director (Tech.).	
'A1	TEGORY - II POSTS								
4.	Assistant Manager (Technical).	350-25-500-30- 620-40 700.	Direct 40%	<u></u>	_	(i) Degree in Agriculture, or degree in science with Diploma in Food Technology or Master's degree in Zoology or Biochemistry or equivalent qualifications.		Technical officer/ Quality Supervisor.	*Relxable in case of Corporation em- ployee.
						(ii) 2 years experience in storage of foodgrains and maintenance of stocks or in the exa- mination inspection and analysis of food- grains in Governmen or Public/Private Private Ltd. Under- takings.	t		
						(iii) Knowledge of toxicology or insecticides, raticides and fumigants in use in grains stocks.			
			Promotion 50%	Selection	3 years as Assit. Gr-I (Tech.).				· <u> </u>

æ n	RT III—SEC. 4]	
se n		
] THE GAZETTE OF INDIA, MAY 8, 1971 (VAISAKHA 18, 1893)	
	, MAY	
	8, 1971	
	(VAISAKHA	
	18, 1893)	
	1251	

GORY-III POSTS								1		
Assistant Grade-I (Tech.)	225-10-235-15- 430-20-550.	Promotion 100%	Non-selection	3 years experience as Asstt, Gr. II (Tech.).		_	Tech. Assistants Analysers, Quality Ins- pectors,	· - *		
Assistant Grade-II (Tech.)	150-10-300	Promotion 100% failing which direct recruitment.	Non-selection	3 years experience as Asstt. Grade- III (Tech.).	Degree in Science preferably in Agriculture with 3 years experience in the field.	25 years	Assistant * Analysers, Fumigation Assistants.	Relaxable in case of Corporation employee.		
Assistant Grade -III (Tech.)	120-10-240	Direct 100%		-	Degree in Science pre- ferably in Agriculture.	Do.	Laboratory Assistants.	Do.		
PART V—MOVEMENT CADRE										
EGORY-I POSTS								((
Senior Deputy Manager (Movement)	900-50-1400	50% promotion	Selection	3 years as Deputy Manager (Movt.).	_	_	_	-		
		50% by transfer on deputation.								
Deputy Manager (Movt.)	700-50-1250	50% by promotion from SAM (Movt.) and 50% by transfer on deputation.	Do.	3 years as S.A.M. (Movt.).	<u> </u>	_	Deputy Director (Movt.)			
Senior Assistant Manager (Movt.).	400-40-800-50- 950.	50% by promotion from A. M. (Movt.) and 50% by transfer on deputation.	Do.	3 years as A,M, (Movt.).	_	_	Asstt. Director (Movt.)	_		
EGORY-II POSTS								Y		
Assistant Manager (Movt.)	350-25-500-30- 620-40-700.	50% by promotion from Asst. Gr-I (Movt.) and 50% by transfer on deputa- tion.	Selection	3 years as Asstt. GrGrI (Movt.).	_		Movt. Inspector.			
EGORY-III POSTS										
Assistant Grade-I (Movt.).	225-10-235-15- 430-20-550.	50% by promotion from Asstt. Gr-II (Depot) and 50% by transfer on deputa- tion from Railways.	Non-Selection	3 years as Asstt. Gi II (Depot),	r. —	_	Assistant Movt. Inspect	or		
EGORY-I POSTS			PART VI	PLANNING AND RE	SEARCH CADRE					
Senior Deputy Manager (P&R)	900-50-1400	Promotion 100%	Selection	3 year's as Deputy Manager (P&R)	_	_		_		
	Assistant Grade-II (Tech.) Assistant Grade-III (Tech.) Assistant Grade-III (Tech.) EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager (Movt.) Deputy Manager (Movt.) EGORY-II POSTS Assistant Manager (Movt.) TEGORY-III POSTS Assistant Grade-I (Movt.) TEGORY-III POSTS Senior Deputy Manager	Assistant Grade-I (Tech.) 225-10-235-15-430-20-550. Assistant Grade-II (Tech.) 150-10-300 Assistant Grade-III (Tech.) 120-10-240 EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 Senior Assistant Manager 400-40-800-50-950. EGORY-II POSTS Assistant Manager (Movt.) 350-25-500-30-620-40-700. TEGORY-III POSTS Assistant Grade-I (Movt.). 225-10-235-15-430-20-550. TEGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400	Assistant Grade-I (Tech.) 225-10-235-15-430-20-550. Assistant Grade-II (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% failing which direct recruitment. Assistant Grade-III (Tech.) 120-10-240 Direct 100% EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 50% promotion (Movement) 50% by transfer on deputation. Deputy Manager (Movt.) 700-50-1250 50% by promotion from SAM (Movt.) and 50% by transfer on deputation. Senior Assistant Manager (Movt.) 950. 50% by promotion from A. M. (Movt.) and 50% by transfer on deputation. EGORY-II POSTS Assistant Manager (Movt.) 350-25-500-30-620-40-700. 50% by promotion from Asst. Gr-II (Movt.) and 50% by transfer on deputation. EGORY-III POSTS Assistant Grade-I (Movt.) 225-10-235-15-430-20-550. 50% by promotion from Asst. Gr-II (Depot) and 50% by transfer on deputation. EGORY-II POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 Promotion 100%	Assistant Grade-I (Tech.) 225-10-235-15- 430-20-550. Assistant Grade-II (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% Non-selection failing which direct recruitment. Assistant Grade-III (Tech.) 120-10-240 Direct 100% — PART V— EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 50% promotion (Movement) Selection Deputy Manager (Movt.) 700-50-1250 50% by transfer on deputation. Deputy Manager (Movt.) 700-50-1250 50% by promotion from SAM (Movt.) and 50% by transfer on deputation. Senior Assistant Manager (Movt.) 950. 50% by promotion from A.M. (Movt.) and 50% by transfer on deputation. EGORY-II POSTS Assistant Manager (Movt.) 350-25-500-30-620-40-700. 50% by promotion from Asst. Gr-II (Depot) and 50% by transfer on deputation. EGORY-III POSTS Assistant Grade-I (Movt.) 225-10-235-15-430-20-550. 50% by promotion from Asstt. Gr-II (Depot) and 50% by transfer on deputation from Railways. PART VI— EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 Promotion 100% Selection	Assistant Grade-I (Tech.) 225-10-235-15-430-20-550. Promotion 100% Non-selection as Assit. Gr. II (Tech.). Assistant Grade-II (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% Non-selection failing which direct recruitment. Assistant Grade-III (Tech.) 120-10-240 Direct 100% PART V—MOVEMENT CADR EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 50% promotion Selection 3 years as Deputy Manager (Movt.) 50% by transfer on deputation. Deputy Manager (Movt.) 700-50-1250 50% by promotion from SAM (Movt.) and 50% by transfer on deputation. Senior Assistant Manager 400-40-800-50-50% by promotion from A. M. (Movt.) and 50% by transfer on deputation. EGORY-II POSTS Assistant Manager (Movt.) 350-25-500-30-620-40-700. 620-40-700. From A. SSI. Gr. I (Movt.) and 50% by transfer on deputation. EGORY-II POSTS Assistant Grade-I (Movt.) 225-10-235-15-430-20-550. From A. SSI. Gr. II (Dept) and 50% by transfer on deputation. FEGORY-I POSTS Assistant Grade-I (Movt.) 225-10-235-15-430-20-550. From Assit. Gr. II (Dept) and 50% by transfer on deputation from Railways. PART VI—PLANNING AND RESEGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 Promotion from Railways. PART VI—PLANNING AND RESEGORY-I POSTS Senior Deputy Manager 900-50-1400 Promotion 100% Selection 3 years as Assit. Gr. PART VI—PLANNING AND RESEGORY-I POSTS	Assistant Grade-I (Tech.) 225-10-235-15- 430-20-550. Promotion 100% Non-selection as Assit. Gr. II (Tech.). Assistant Grade-II (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% failing which direct recruitment. Assistant Grade-III (Tech.) 120-10-240 Direct 100% — Direct 100% — Degree in Science preferably in Agriculture. PART V—MOVEMENT CADRE EGORY-I POSTS Senior Deputy Manager (Movt.) 700-50-1200 50% promotion from SAM (Movt.) and 50% by transfer on deputation. Senior Assistant Manager (Movt.) 700-50-120 50% by promotion from SAM (Movt.) and 50% by transfer on deputation. Senior Assistant Manager (Movt.) 350-25-500-30- 620-40-700.	Assistant Grade-I (Tech.) 223-10-235-15 430-20-550. Promotion 100% Non-selection along the failing which direct recruitment. Assistant Grade-II (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% Non-selection failing which direct recruitment. Assistant Grade-III (Tech.) 120-10-240 Direct 100% ——————————————————————————————————	Assistant Grade-I (Tech.) 225-10-235-15 430-20-550. Promotion 100% Non-selection 3 years experience as Assit. Gr. II (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% Promotion 100% Non-selection 3 years experience as Assit. Gr. III (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% Non-selection 3 years experience as Assit. Gr. III (Tech.) 150-10-300 Promotion 100% Non-selection 3 years as perience as Assit. Gr. III (Tech.) 120-10-240 Direct 100% ——————————————————————————————————		

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	1252
2. Deputy Manager (P&R)	700-50-1250	Direct 50%	-		Essential (i) Master's Degree in	30 years*	-	*Relaxable in the case of Corporation employee.	THE
					Economics or Statistics with 1st or higher second class. (ii) **Six years' experience in (i) Market Research & (ii) Analysis and interpretation of economic data.			**Relaxable upto two years' in the case of candidates with better aca- demic qualifications.	GAZETTE OF
		Promotion 50%	Selection	3 years as SAM (P&R)	—		_		INDIA,
3. Senior Assistant Manager (P&R).	400-40-800-50 950.	Promotion 100e	Selection	3 years as A.M. (P&R).	~		÷		MAY
CATEGORY-II POSTS				()·					∦ × 8,
4. Assistant Manager (P&R)	350-25-500-30 620-40 - 700 .	Direct 50%	_	-	Essential	25 years*	_	*Relaxable in the case of Corpora- tion enployee.	, 1971
					Master's Degree in Eco- mics or Statistics with a 1st or high II Class.				(VAISAKHA
					Desirable :				AK
					Two years' experience in (i) Market Reseach a (ii) Analysis and integration of economic data.	nd			5,
		Promotion 50%	Selection	3 years as Statistical Assistant			_	_	1893)
CATEGORY-III POSTS				120-2-1201					
5. Statistical Assistant .	. 225-10-235-15 430-20-550.	Direct 100%	_	_	B.A./B.Sc./B. Com. in Economics/Statistics/ Commerce/Mathamatics with 1st or II class and proficiency in Machine Disk calculation and in systematic tabulation of Diverse material.	25 years	_	*Do.	[PART III—SEC.
NOTE :- Direct recruitment of	covers transfer on	deputation also.						•	4

1. Deputy Financial Adviser 1600-100-2000 Direct/%Promotion Selection 5 years as A.F.A. Graduate of a recognized University, years Associate/

Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India AICWA/ACWA (London) with 10 standing. years Membership of a similar body from U. K. for any other foreign country will be an advantage. Experience in a firm of Chartered Accountants of Standing or Public/Private Sector Commercial Undertaking for not less than 10 years. Should be wellversed in Audit of Accounts of Joint Stock Companies, Secretariat and Income Tax direct work (for recruits only).

2. Assistant Financial Adviser] 1100-50-1300- Direct/ % promotion Selection 60-1600

3 years as SDM (Accountants)

Graduate of a recog- 30-40 University, nized Associate/Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India/AICWA/ ACWA (London) with 7 years' standing, Membership of a similar body from U. K. or any other foreign country will be an advantage. Experience in a firm of Chartered Accountants of standing or Public/private sector commercial undertakings or not less than 7 years. Should be well versed in audit of accounts of Joint Stock Companies. Secretariat and income tax work (for direct recruits only.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Senior (Accou	Deputy Manager unts).	900-50-1400	Direct/%Promotion	Selection	3 years as D.M. (Accounts) or D.M. (Data Processing)	Chartered Accountants/ AICWA/ACWA (London) with 5 years experience (for direct recruits only)	30-40 years.	_	
4. Deputy (Accou	y Manager ants)	700-50-1250	Direct 25% promotion 75%	Selection	3 years as SAM. (Accounts)	Chartered Accountants AICWA/ACWA (London) with 5 years experience (for direct recruits only.)	30-40 years	- .	~
5. Senior A (Accou		`400-40-800-50- 950	Promotion 100%	Selection	3 years experience as Assistant Manager (Accounts)	_	_	Assistant P&AO	The promotion of Asstt. Managers (Accts.) possessing A.C.A., A.C.W.A., (London), AICWA qualifications and others shall be in the ratio of 1:1.
	int Manager	350-25-500-30- 620-40-700	Direct 50%			**ACA/ACWA (London)/AICWA preferably with experience in the Accounts Depart- ments of a Private/ Public Sector Com- mercial Undertaking. OR Graduate in Commerce with not less than 5 years experience in the Accounts Department of any Private/Public Sec- tor Commercial Undertaking.	25 to 35 yrs.	SAS Supdtof P&AO	*Relaxable in the case of Corporation's employees.
CATEGO	ND V.III		Promotion 50%	Selection	3 years experience as Accounts Asstt. Gr. I	_	_	-	1. (**) 2. (@)
	nts Assistant Grade-	1 225-10-235-15- 430-20-550	Direct 25%	-		Graduate, preferably B.Com.	*25 years /	Accountant/ Assistant	*Relaxation in the case of
			Promotion 75%	Non-Selection	3 years experience as Accounts Asstt. Gr. II	_	_	superintendent/ Senior/ Grade Ckerk of P & A Office.	Corporation's employees.

8. Accounts Assistant Grade-II	150-10-300	Promotion 100%	Do.	3 years experience as Accounts Asstt. Gr. III	-	_	U.D.C.	- 4
9. Accounts Assistant Grade-III	120-10-240	Direct 100%	~	~	Graduate, preferably B.Com.	*24 years	L.D.C.	*Relaxable in the case of Corporation's employees.
CATEGORY-I POSTS			PART-V	/II-A—DATA PROCE	SSING CADRE			employees.
Dy. Manager (Data Processing)	700-50-1250	Promotion 100%	Selection	3 years as S.A.M. (Data Processing),	_		 ,	The incumbent of the post will be con- sidered for promotion to the post of
2. Senior Assit. Mana ger (Data	400-40-800 -50-950	Promotion 50%	De.	3 years as A.M. (Data Processing).	_	_	_	S.D.M. (A/c)
Mana ger (Data Processing.) CATEGORY-II POSTS	-30-930	Direct 50%		(Data Processing).	 (i) Degree in Commerce with a good Accounting background. (ii) 3 to 5 years experience in operating IBM machines of which at least one year as Supervisor of an installation. 		_	
3. Assistant Manager. (Data processing) CATEGORY-III-POSTS	350-25-500-30- 620-40-700	Promotion 100%	Selection	3 years as Machine operator Gr. I.	_			_
4. Machine Operator Grade-I.	225-10-235-15- 430-20-550	Promotion failing which by direct recruitment.	Non-selection.	3 years as Machine Operator Grade-II.	(1) First Class graduate in Mathematics/Physics/ Accounts.	28 years	_	Advance Increment can also be given in deserving case.
					(2) At least 2 years experience in working in the Accounts Department of a Commercial or Govt. organisation.			
**Condidates with ACAMAC					(3) 1 year experience in operating IBM Machines e.g. 0.82 Sorter, 514 Reproducer, 602 calculating punch and 407 accounting Machine etc.			

^{**}Candidates with ACA/ACWA (London)/AICWA qualifications will be started with Rs. 400/- P. M.

[@]For promotion by selection of Assistant Grade-I to the post of Assistant Manager (Accounts) their performance in the prescribed training programme will also be taken into account, "The percentage of direct recruitment and promotion in these grades has not been prescribed for the present. The position will be reviewed after a period of 3 years when it may be possible to lay down percentages of vacancies in these grades to be filled by direct recruitment or promotion. In the meantime, however, while filling up any of the existing/future vacancies in these grades, the Corporation shall first explore the possibilities of promotion and then resort to other methods.

^{*}Relaxable in the case of Corporation employees.

Note:—Direct recruitment covers transfer on deputation also.

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Machine Grade-I		150-10-300	Promotion failing which by direct recruitment.	Non-Selection	3 years as Key Punch Operator.	(1) 2nd class graduate in Mathematics/Physics/Accounts.	28 years*		_
						(2) At least 2 years experience in working in Accounts Deptt. of a Commercial or a Govt. organisation.			
6. Key Pur	ich Operator.	120-10-240	Direct 100%	_	_	Essential (1) Graduate. (2) Aptitude for figure wo Desirable	24 years rk		Preference will be given to female can- didates,
						Knowledge of typewriting.			
				PART-VIII	LEGAL CADRE				
SPECIAL P I. Manager		Rs. 1600-100- 2000	Direct/Promotion	Selection	3 years as a Joint Manager (Legal)	(i) Degree in Law from a recognised University.	45 years		Mode of recruitment to be decided at the time of
CATEGOR	RY-I POSTS					(ii) At least 15 years experience as Legal Officer in Central/State Government or Public/Private Sector Undertaking or 10 years' practice at the Bar.			appointment.
	anager (Legal)	Rs. 1100-50-1300	- D o.	Do.	3 years as SDM	(i) Degree in Law	40 years	_	Do.
		60-1600			(Legal)	from a recognised University. (ii) At least 10 years' experience as Legal Officer in Central/State Govt or Public/Private Sector Undertaking or 7 years' practice at the Bar.			
3. Senior I (Legal)	Deputy Manager	Rs. 900-50-1400	Promotion 100% failing which direct recruitment.	Do.	3 years' as D.M. (Legal)	(i) Degree in Law from a recognised University. (ii) At least 8 years' experience in Legal work in Central/State Govt. or a Public/Private Sector Undertaking or 5 years' practice at the Bar.	40 years	_	_

(i) Degree in Law from a recognised University

30 to 40 years

45 years

•To

each

ment.

(ii) At least 5 years experience in Legal work in Central/ State Government or Public/Private Sector Undertaking or 3 years'

practice at the Bar.

PART-IX-ENGINEERING CADRE

SPECIAL POST

1. Manager (Engg.) . . Rs. 1600-100-2000 Promotion/Direct/Selection transfer on Deputation*

5 years as Joint Essential: Manager (CE)/ (EE)/(ME).

(i) Degree in Civil/ Electrical Mechanical Engineering of a recognised University or equivalent.

(ii) About 10 years experience of Civil/ Electrical/Mechanical Engineering works, of which about 5 years should be in the capacity of Executive Engineer or equivalent.

Desirable:

- (i) Master's Degree in Civil/Electrical/ Mechanical Engineering with speci-alised knowledge of Rice Mills, Food Processing Industries, Preparation of Designs and Specifications, maintenance and operation of mechanical handling equipments at Ports/ Godowns.
- (ii) Persons who have held independent charge of Engineering Division Industrial establishments/Public Sector Undertakings and have had experience of planning and execution of projects will be preferred.

^{*}Relaxable in the case of Corporation employees.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					CIVIL WING	G			
CATEG	ORY-I								
2. Joint	Manager (CE)	Rs. 1100-50- 1300-60-1600	100% promotion failing which by deputa- tion.	Selection	3 years as SDM (CE)		••		
3. Senio (CE)	or Deputy Manager	Rs. 900-50-1400	Do.	Do.	3 years as DM (CE)		• •	••	
4. Dept	ity Manager (CE) .	Rs. 700-50-1250	100% promotion, failing which direct re- cruitment.	Do.	3 years as S.A.M. (CE).	Degree in Civil Engg. and experience for 5 years.	45 years	Executive Engineer.	
5. Senio (CE)	or Assistant Manager	Rs. 400-40-800- 50-950	50% promotion Direct	Do.	3 years as A.M. (CE) Engineer			Assistant Engineer	• •
CATEGO:		,	50% recruitment			Degree in Civil Engin- eering and experience for 3 years.	30 years	raigincer	• •
	ant Manager (CE) .	Rs. 350-25-500- 30-620-40-700	100% promotion, failing which direct recruitment.	Selection	3 years as Junior Engineer who are Degree holders and 5 years in the case of Diploma holders.	Degree in Civil Engin- eering and experience for 3 years.	30 years		
CATEGO	RY-III								
7. Junior	Engineer	Rs. 225-10-235- 15-430-20-550	100% direct recruitment.		••	Degree in Civil Engin- eering or Diploma in Civil Engineering with 1 year experience.		Section Officer.	
DRAFTSN	MEN CATEGORY-	II POST							_
8. Head I	Draftsman .	Rs. 350-25-500- 30-620-40-700	100% promotion, failing which direct recruitment.	Selection	3 years as Draftsman Grade-I.	Diploma in Civil Engin- eering with 5 years experience as In- charge of Drawing Office in any organisa- tion.	35 years	Head Draftsman	
CATEGO	RY-III POST								
9. Drafts	man Gr-I . ,	Rs. 225-10-235- 15-430-20-550	100% promotion failing which direct recruitment	Non-selection	3 years as Draftsman Grade-II.	Diploma in Civil Engin- eering with 2 years experience as Drafts- man in any organisa- tion.	30 years	Draftsman Grade-I.	
10. Drafts	man Gr-II	Rs. 150-10-300	100% direct recruitment.			Matriculation or equivalent with Diploma in Draftsmanship after a study of not less than 2 years from a Recognised Institution.	28 years	Draftsman Grade-II.	

12. Blue Printer Do.	100% direct recruit- ment.			Matriculation or equiva- lent with tachnical training certificate in drawing from a Recognised Institute 2 years experience in drawing work.	25 years		••	(*)
CATEGORY-II	Do.	• •		Do				
I. Joint Manager (EE) Rs. 1100-50-	1000/		ELECTRICAL WI	NG			••	j
1300-60-1600.	100% promotion, failing which by deputation.	Selection	3 years as SDM (EE)	<u></u>	••	• •	••	
2. Senior Deputy Manager Rs. 900-50-1400 (EE).	Do.	Do.	3 years as D.M. (EE)					J
3. Deupy Manager (EE) . Rs. 700-50-1250	100% promotion,	D.	1			••		
	failing which by direct recruitment.	Do.	3 years as SAM (EE)	Degree in Electrical Engineering with experience for 5 years.	45 years	Executive Engineer.	• •	
4. Senior Assistant Manager Rs. 400-40-800- (EE). 50-950.	50% promotion	Do.	3 years as A.M. (EE)/			_		ľ
	50% direct recruit-		Foreman (FE)	• •	• •	Assistant Engineer.	**	[]
CATEGORY-I	ment.		fication.	Degree in Electrical Engineering with 5	30 years	raginteel.		
5. Assistant Manager (EE) . Rs. 350-25-500-	100% promotion,	_		years expenence.				
30-620-40-700 CATEGORY-III	failing which by direct recruitment.	Do.	3 years as Junior Engineer (Elec.) if Degree holder and 5 years if Diploma Holder	Degree in Electrical Engineering with ex- perience for 3 years.	30 years	••		
6. Junior Engineer (EE) . Rs. 225-10-235-	100% direct recruit-		present inorder					ļļ
15-430-20-550 CATEGORY-II	ment.	••		Degree in Electrical Engineering or Dip- loma in Electrical Engineering, with 1 year experience in the case of Diploma hol- ders only.	28 years	Section Officer,		
7. Foreman (EE) Rs. 350-25-500- 30-620-40-700	100% promotion,	Selection	3 years as Charge-	March 1 of				·
ATEGORY-III	failing which direct recruitment.		man (EE).	Matriculation or equiva- lent Diploma in Electrical Engineering Certificate in Human Relations. 5 years experience in main- tenance and opera- tion of electrical installations covering electrical machines.	35 years	Foreman	••	
	1000/			machines.				
15-430-20-550 M59GI/71—12.	100% promotion, failing which direct recruitment.	Non-Selection	3 years as Head Electrician,	Matriculation or equiva- lent Diploma in Electrical Engineering. Certificate in Human Relations. 3 years experience in maintenance of elec- trical installations.	35 years	Chargeman		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9. Head Elea	etrician .	. Rs. 200-10-250- 15-400.	100% promotion, failing which direct recruitment.	Non-selection	3 years as Electrician-cum-Operator/ Wireman Gr. I/ Batteryman (those possessing Electrical Supervisors Certificate only will be eligible for promotion).	engineering. Electri- cal Supervisory Lice-		Head Electrician.	,.
10. Electrician	n-cum-Operator	Rs. 120-10-240	100% Promotion, failing which dire recruitment.	Do.	3 years as Wireman Gr. II/Electric Motor Driver.	Middle Standard, Wire- man certificate. 3 years experience on maintenance of elec- trical installations work.	·	Electrician- cum- operator.	
11. Wireman (Batteryma		Rs. 120-10-240	Do.	Do.	Do.	Middle Standard. Wiremen Gr. I competency certificate. 3 years experience on maintenance of electrical installation works.	·	Wireman Gr. I/ Batteryman.	
2. Wireman Electric Motor		Rs. 120-5-150	100 % direct recruitment		••	Middle Standard, Wireman Grade-II competency certificate. 3 years experience on maintenance of electrical installation works.		Wireman Gr. II/ Electric Motor- Driver.	
RAFTSMEN CATEGORY-I						`			
3. Head Draf		Rs. 350-25-500- 30-620-40-700.	100% Promotion, failing which direct recruitment.	Selection	3 years as Draftsman Grade-I.	Diploma in Electrical Engineering. 5 years experience as Incharge of Drawing office in any organisation.	35 years	Head Draftsman.	
CATEGORY-I 4. Draftsman		Rs. 225-10-235 15-430-20-550	Do.	Non-Selection	3 years as Draftsman Grade-II.	Diploma in Electrical Engineering. 2 years experience as Draftsman in any organisation.	30 years	Draftsman Grade-I.	

15. Draftsman GrII . ,	Rs. 150-10-300	100% direct recruitment.	·	••	Matriculation or equiva- lent with Diploma in Draftsmanship after a study of not less than 2 years from a recognised insti- tution.	28 years	Draftsman Grade-II.		Z)
CATEGORY-I MECHANICAL	L WING								
1. Joint Manager (ME) .	Rs, 1100-50-1300 60-1600	100% Promotion failing which by deputation.	Selection	3 years as S.D.M. (ME).		••	••	••	
2. Senior Deputy Manager (ME).	Rs. 900-50-1400	Do.	Do.	3 years as D.M. (ME)		. >	••	••	
3. Deputy Manager (ME) .	Rs. 700-50-1250	100% Promotion, failing which by direct recruitment.	Do.	3 years as S.A.M. (ME).	Degree in Machanical Engineeering with ex- perience for 5 years.	45 years	Executive Engineer.	••	
4. Senior Assisant Manager (ME).	Rs. 400-40-800- 50-950	50% Promotion	Do.	3 years as A.M. (ME)/ Foreman with AMIE quali- fication.			Assistant Engineer,	••	
•		50% Direct recruitment.	••	ikation.	Degree in Mechanical Engineering with 3 years experience.	30 years	••		
CATEGORY-II					•				
5. Assistant Manager (ME) .	Rs. 350-25-500- 30-620-40-700	100% Promotion, failing which direct recruitment.	Selection	3 years as Junior Engineer (ME) if Degree holder and 5 years if Diploma holder.	Degree in Mechanical Engineering with ex- perience for 3 years.	30 years	1.	••	
CATEGORY-III									
6. Junior Engineer (ME) .	Rs, 225-10-235- 15-430-20-550	100% direct recruitment.			Degree in Mechanical Engineering or Dip- loma in Mechanical Engineering with 1 year experience in the case of Diploma holders.	28 years	Section Officer.		
			SUPERVISORY	(POSTS (GROUP-G)					
CATEGORY-II									
7. Foreman (ME)	Rs. 350-25-500- 30-620-40-700	100% Promotion, failing which direct recruitment.	Selection	3 years as Charge- man/Shift Super- visor.	Matriculation or equiva- lent. Diploma in Mechanical/Automo- bile, Engineering. Certificate in Human Relations.	•	Foreman	;	
	-7. T-10-				5 years experience in a workshop.				

PART III—SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 8, 1971 (VAISAKHA 18, 1893)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
CATEGOR	Y-III								
8. Charge Supervi	man (ME)/ Shift isor.	Rs. 225-10-235- 15-430-20-550. Transferee Officers will start at a minimum of Rs. 250/-	100% Promotion, failing which direct recruitment.	Non-selection	3 years in a post of Group-E or 2 years in a post of Group-F, subject to passing the Proficiency Test.	Matriculation or equiva- lent. Diploma in Mechanical / Automo- bile Engineering. Certificate in Human Relations.	35 years	Chargeman/ Shift Supervisor.	
	,					3 years experience in a workshop.			*
				HIGHLY	SKILLED POSTS				
GROUP	'F'								
9, Head M	Aechanic •	Rs. 200-10-250- 15-400.	100% Promotion, failing which direct recruitment.	Non-Selection	3 years in a post of Group "D' or 2 years in a post of Group E', subject to passing the Proficiency Test.	ficate in diesel and petrol engines. Certi ficate in Human Relations.	 1	Head Mechanic.	
						5 years experience in a workshop.			
10. Assistar	nt Supervisor .	Do.	Do.	Do.	Do.	Middle Standard, ITI Trade Certificate in general mechanical engineering or equiva- lent. Certificate in Human Relations. 5 years experience in supervising and con- trolling labour force.	35 years	Assistant Supervisor.	
11. Head W		Do.	Do.	Do.	Do.	Matriculation or equiva- lent. Should possess Welder's certificate awarded by any State Govt. ITI Trade Certificate in general mechanical engineering. Certifica- te in Human Rela- tions. 5 years experience in electric and gas welding works.	35 years	Head Welder,	
				_					
Mechan	Mechanic/Motoric.	Rs, 150-10-300	50% Promotion 50% Direct re- cruitment.	Do.	of Group 'D', sub- ject to passing the	Middle Standard. ITI Trade certificate in diesel and petrol engines. 3 years experience in a workshop.	32 years	Driver Mechanic/ Motor Mechanic.	 ፋ

GROUP 'D'	GROU	JP.	'D'
-----------	------	-----	-----

GROUP 'D'					
13. Mechanic-cum-operator/ Rs. 120-16 Engine Driver.	0-240 100% Promotion, failing which direct recruitment.	Do.	Group-B or 1 year in a post of Group 'C', sub-	and petrol engines. Operator Engine 3 years experience in Driver.	
14. Welder Do.	Do.	Do.	Do.	Middle Standard, Shou- ld possess Welder's Certificate awarded by any State Govern- ment. 3 years experience on electrical and gas welding jobs.	प
15. Turner Rs. 120-10	-240 100% promotion, failing which direct recruitment.	Non-selection	3 years in a post of Group 'B' or 1 year in a post of Group 'C' subject to passing the pres- cribed Trade Test.	Middle Standard. Trade 30 years Turner Certificate from I.T.I. or equivalent.	-
•				3 years experience in operation of lathes, drilling machines, grinders etc.	
16. Boiler Attendant Do	Do.	Do.	Do.	Middle Standard. Should 28 years posses Boiler Attendant's Certificate.	-
				3 years experience in operation and maintenance of medium pressure boilders.	
17. Carpenter D	o. Do.	Do.	Do.	Middle Standard. ITI 30 years Carpenter Trade Certificate in Carpentry.	-
				3 years experience in Carpentry shop.	
GROUA 'C'					
18. Sewing Machine Opera- Rs. 120-5-3 tor/Mistry/Mechanic.	50 100% promotion, fail ing which direct recruitment.	- Do.	Pomotion from Group 'B' posts. Employees who have passed the prescri- bed trade Test will be eligible for pro- motion.	Middle Standard, ITI 30 years Sewing Trade Certificate in Machine General Mechanical Engineering. Middle Standard, ITI 30 years Machine Operator/ Ministry/ Mechanic.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						3 years experience in a workshop dealing in steel fabrication works for engines.			
19. Cyclone	Attendant	Rs. 120-5-150	100% Promotion failing which direct recruitment.	Non-Selection	Promotion from Group 'B' posts, Employees who have passed the prescribed Trade Test will be eligible for promotion.	Trade Certificate in general mechanical engi- neering. Should also possess Wireman Gr. II		Cyclone- Attendant	
					Ŷ	3 years experience in a Workshop dealing with steel fabrication works for engines.			
20. Fitter		. Do.	Do.	Do.	Do.	Middle Standard. Should 30 have completed Fitter's Course in any I.T.I.) years l	Fitter	-
						3 years experience as Fitter in a Workshop.			
21. Tinsmit	h	· Do.	Do.	Do.	Do.	Middle Standard, I.T.I. 3 Trade Certificate in tinsmithy and welding.	0 years	Tinsmith	_
						3 years experience as Tinsmith.			
2. Painter	• •	· Do.	Do.	Do.	Do.	Middle standard. I.T.I. Trade Certificate in painting or equivalent.	30 years	Painter	_
						3 years experience as Pain-			
23. Blacksmi	ith	Do.	Do.	Do.	D ₀ .	ter. Middle Standard. ITI 30 Trade certificate in black- smith.	years P	Blacksmith	
24. Dryer C	perator .	. Do.	Do.	Do.	Do.	Matriculation. I.T.I. 30 training in general mechanical engg.) years	_	-
		1				3 years experience in the line.			

Category-IV SEMI-SKILLED POSTS (GROUP B)									*
25. Asstt. Welder	Rs. 100-5-130	Do.	Do.	Employees of Group 'A' posts, subject to passing the prescribed Trade Test.		28 years	Asstt, Welder.	_	
					2 years experience on both electrical & gas welding works.				
26. Asstt. Mechanic/Greaser.	Do.	Do.	Do.	Do.	Middle Standard ITI Trade Certificate in general mechanical engi- neering.	28 years	Asstt. Mechanic/ Greaser.		
,					2 years experience in Workshop dealing with enginees of fabrication works.				
Un-skilled Posts: (Groups'A')							~		
27. Khalasi/Cleaner · .	Rs. 85-2-95-3-110	Do.	Do.	2 years as Oilman/ Tube well Operator	Middle Standard.	25 year:	Khalasi/ Cleaner		!
					2 years experience in any mechanical workshop.				
28. Oilman/Tubewell Operator	Rs. 80-2-100	100% direct recruit- ment.	_	_	Middle Standard.	25 yaears	—		
Draftsmen; Category-II					•				
29. Head Draftsman	Rs. 350-25-500- 30-620-40-700	100% Promotion, failing which direct recruitment.	Selection	3 years as Draftsman Gr. I	Diploma in Mechanical Engineering with 5 years experience as Incharge of Drawing office in any organisation.	•	Head Draftsman		
Category-III	٠								
30. Draftsman Gr. I	Rs. 225-10-235- 15-430-20-550.	Do.	Non- Selection.	3 years as Draftsman Grade -II.	Diploma in Mechanical Engineering with 2 years experience as Draftsman in any organiation.	-	Draftsman Grade-I.		
31. Draftsman Gr. II -	Rs. 150-10-300	100% direct recruit- ment		_	Matriculation or equivale with Diploma in Draftsmanship after a study of not less than two years from a recognised institution.	nt 28 years	Draftsman Grade-II	-	

[PART III—SEC. 4

PART-X MISCELLANEOUS CADRE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Category I 1. Public Re	elations Officer .	Rs. 1100-50-1300 60-1600	Direct	-		Graduate of any recognised University. Minimum 5 years experience in handling public relations work for any private or public sector commercial undertaking. Journalistic experience will be an added qualification. Essential:	years.	- .	_
2. Assistant Officer	Public Relation	Rs. 400-40-800- 50-950.	100% direct recruitment.	_	<u>. </u>	(i) Degree of a recognised University or equivalent and Diploma in Journalism. (ii) Minimum 3 years experience in handling Public Relations work in a Private/Public Sector Undertaking.		_	~~
						Desireable (i) Journalistic experience. (ii) Good command over English and one or more re- gional languages.			
						Preference may be given to candidates with Post-graduate qualification and aptitude for Public Relations work, and experience in organising exhibitions.			
Category-II									
3. Librarian	1	Rs. 350-25-500- 30-620-40-700,	Direct/recruitment/ Promotion from Library Assistant.	Selection	3 years as Library Assistant.	Graduate with a diploma 35 ye in Library. Science Experience in any library for 5 years. (for direct recruits only)	ars	_	_
Category-III	ŧ.								
4. Receiptio	onist .	. Rs. 300-25-600	Direct recruitment	-	_	Graduate with knowledge 25 typewriting and short-hand preference being given to ladies.	years	_	. –

5. Library Assistant	Rs. 225-10-235-1 430-20-550	15- Do	-	_	Graduate with a diploma in Library Science.	25 years		-
. Comptist	Rs. 225-10-235- 15-430-20-550	D o		- .	B. A., B. Sc., or B. Com. in Economics, Statistics, Commerce or Mathematics (I or II class) and proficiency in Machine or Disk calculation and in systematic tabulation of diverse material.	25 years	_	
/. Comptometer operator .	Rs. 150-10-300	Direct		_	handling computing	24 years Relaxable in deserving cases.	Comptometr Operator.	re
	,				Desiable :			
					 (i) Mathematics as one of the subjects in Materiulation or equivalent qualification. (ii) Aptitute for figure work. 			
					(iii) Two years ex- perience in a similar capacity in a Central/State De- partment or Public Sector or Private Sector Undertaking.			
8. Proof Reader	Rs. 150-10-300	Direct	- -	_	(i) Degree of a recog- nised University	28 years	—	_
					(ii) Two years experience of Proof reading in a news papers office or Printing press.			
9. Caretaker-cum-Cook .	Rs. 120-5-150	Do.		_	Capable of cooking Conti- nental as well as Indian Should be able to take orders in English and speak Hindi fluently.	40 years		
10. Vehicle Drivers Gr. I	Rs. 120-10-240	100% Promotion failing which direct recruitment.	Non-selection	6 years as vehicle Driver G. II.	Middle standard and licence to drive heavy vehicles with a driving experience for at least 5 years.		/ehicle p driver }	Vehicle Driver out incharge of heavy vehicles will also be eligible to this scale of pay.
11. Vehicle Drivers Grade II	Rs. 120-5-150	100 % direct recrui(- ment.		-	Middle standard, Car/light vehicle licence with a driv- ing experience of 4 years.	28 years	Vehicle Driver	

DISCIPLINE AND APPEAL REGULATIONS

Statement showing competent authorities.

SI. N	lo. Posts					A	Appointing Authority	Authority competent to relax ago limit and qualifications	Authority competent to impose penalities and penaltes it may impose		Appellate Authorit
									Authority	Penalties	-
1	2						3	4	5	6	7
1. C	ategory IV										`
	District Office		•	•	•	•	District Manager	Regional Manager/Joint Manage	er District Manager	AIJ	Regional Manager/Joint Mana- ger.
	Regional/Port Office .		•	•		•	Deputy Manager/Dy. Regional Manager.	Regional Manager/Joint Manage	er Deputy Manager/ Deputy Regional Manager	All	Regional Manager/Joint Manager.
	Zonal Office/Head Office	ce		•	•	.]	Deputy Manager	Dy. Zonal Manager/Joint Manag	er Deputy Manager	All	Zonal Manager/Personnel Manager.
2. 0	Category III										
	Regional /Port Office .		•	•	•	•	Regional Manager/Joint Manager.	Personnel Manager	Dy. Manager/Dy. Regional Manager Joiut Manager	Minor	Regional Manager/ Joint Manager/Zonal Manager.
	Zonal Office		•	•	•	•	Deputy Zonal Manager	Personnel Manager	Deputy Zonal Manager	All	Zonal Manager
	Head Office			-			Joint Manager	Personnel Manager	Joint Manager	All	Personnel Manager
	ategory II (i) Accounts & Technical	1.				. 1	Managing Director	Chairman	Managing Director	Ail	Chairman
	(ii) Other posts			•			Zonal Manager/Personnel Manager	Managing Director	Zonal Manager/ Personnel Manager	All	Managing Director
4.	Category I Officers other than Heads of		Di	Division		. Е	Executive Committee	Executive Committee Execu	utive Committee/ Board	Minor	Board
									Dome	All	Board
	Heads of Division .					•	Board	Board	Board	Ail	Board

APPENDIX-3

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, The 5th June, 1969

OFFICE MEMORANDUM

Subject:—RE-EMPLOYMENT OF FOOD DEPARTMENT TRANSFEREES RENDERED SURPLUS FROM THE SERVICE OF THE FOOD CORPORATION OF INDIA AS A RESULT OF THE CORPORATION CEASING TO PERFORM CERTAIN FUNCTIONS.

No. F. 14/8/69- Esstt(D)——The undersigned is directed to refer to Deptt. of Food u. o. No. 5/1/68-REI dated 5-4-1969, on the above subject and to say that in the circumstances stated therein, it has been decided that in the event of reduction in the functions of the Corporation, the Food Department transferres i.e. the epmployees transferred to the Food Corpo ation of India from the Food Department under the Food Corporation Amendments Act. 1968, will, for the purpose of employment under the Central Government, be entitled to the same priority for employment assistance through Employment Exchange as is admissible to the Retrenched Central Government Employees, vide Ministry of Home Affairs O. M. No. 4/4/59-RPS, dated 25-11-1959, read with their O. M. No. 71/49/54-DGS(C), dated 31-8-54.

A	PE	EN	DIZ	(-4
---	----	----	-----	-----

	STATEMENT OF IM	MOVABLE :	PROPERTY ON FIRS	STAPPOINTMENT	FOR THE YEAR	
1. Name of Officer (in full and service to	which officer belongs):					
2. Present post held:						
3. Present Pay :						
Name of District Sub-division, Taluk and Village in which property is situated				If not in own name state in	How acquired whether Annual income by purchase, lease from the property	
vinage in which property is situated	Housing and other buildings	Lands	*Present value	whose name held and his/her relationship to	mortgages, inheritence gift or otherwise with date of acquisition and name with details of person from whom aquired@	Remarks
₩						
					·	
Note:—The declaration form is required to be appointment to the service and thereafter at the or mortgage, either in his own name in the name.	e interval of every twely	e months, giv	ving particulars of all in	nmoyable property o	48 of the Food Corporation of India States wated, acquired or inherited by him or	ff Regulations on first held by him on lease
					ű	ire
					Date—	
(*) In case where it is not possible to	assess the value accura	tely the appr	roximate value in relati	on to present cond	itions may be indicated,	
(%) Inapplicable clause to be struck ou	i.					
(@) Includes short term lease also.						
					1.	S. KANSAL,
						nnel Manager

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombuy, the 24th March 1971

CORRIGENDUM

No. 1524...In our corrigendum SBS No. 803 dated the 12th February, 1971 published in the Gazette of India, Part III—Sec. 4 for the week ending 27th February, 1971 on page 662 the following discrepancies are amended as follows:—

- (i) Under the heading 'State Bank of India' insert the words "Central Office".
- (ii) In line 5 of the corrigendum the month should be read as "November" instead of "December".

Sd. ILLEGIBLE Addl. Chief Officer